R.N.I. No.HIN/2002/8718 www.aksnews.com M.P./BHOPAL/642/2021-23

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

वर्ष : 20 । अंक : 16

16 से 31 मई 2022

पृष्ठ : 48

मूल्य : 25 रु.

आरक्षण से कब मुक्त होगा देश?

ओबीसी आरक्षण के पेंच में
गड़बड़ाया मप्र का चुनावी गणित

सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद
अब बिना आरक्षण होंगे चुनाव

ANU SALES CORPORATION

We Deal in Pathology & Medical Equipment

BA200

BioSystems

The Highest Flexibility

Add : Ground Floor, 17/1, Shanti Niketan
Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
9329556524, 9329556530 Email : ascbhopal@gmail.com

इस अंक में

योजना

8 | बिना ड्यूटी की शराब नहीं बिकेगी

घोटालों व साठगांठ के आरोपों से घिरा रहने वाला आबकारी विभाग भी ऑनलाइन होने जा रहा है। जल्द ही ई-आबकारी पोर्टल लांच होने वाला है। इससे ठेकेदार ई-वॉलेट से भुगतान कर सकेंगे। अफसर इसकी निगरानी...

राजपथ

10-11 | मिशन 2023 शिव बनाम नाथ

मप्र में आगामी विधानसभा चुनाव 2023 में होंगे। लेकिन इससे पहले ही चुनावी मैदान सज गया है। कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ तो भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चेहरा होंगे। इन दोनों नेताओं...

समस्या

15 | जहरीली हो रही हैं प्रदेश की नदियां

बढ़ते शहर एवं उद्योगों की वजह से नदियां तेजी के साथ प्रदूषित हो रही हैं। इनके संरक्षण के लिए बनाई गई कार्ययोजनाएं कागजी साबित हो रही हैं। कुछ समय पहले ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मप्र की नदियों की रिपोर्ट तलब की थी, जिसमें 22 नदियों...

बिजली

18 | निजी कंपनियों की फांस में बिजली

मप्र में सरकारी ताप बिजली घरों से पर्याप्त विद्युत उत्पादन होने के बाद भी प्रदेश सरकार ने देश के धन्नासेठों की कंपनियों से बिजली खरीदने का अनुबंध कर प्रदेश पर आर्थिक बोझ तो डाला ही है, अब जब बिजली की जरूरत है तो कंपनियों ने हाथ खड़े कर लिए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

मप्र में ओबीसी आरक्षण की फांस में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव इस कदर फंस गए हैं कि इससे पार पाना सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए मप्र सरकार को बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने का निर्देश दिया है। जिसके खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगाया है। दरअसल, मप्र ही नहीं देशभर में आरक्षण राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बन गया है।

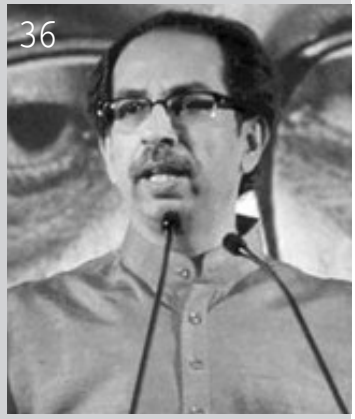

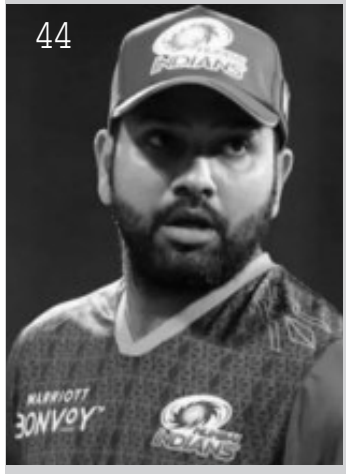

राजनीति

30-31 | किस ओर कांग्रेस?

भीतरी दुविधाओं और भाजपा के गांधी परिवार के खिलाफ लगातार हमलों के बीच फंसी कांग्रेस की चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर (पीके) से भी बात नहीं बन पाई। मसला 2024 के लोकसभा चुनाव और उससे पहले राज्यों में पार्टी को खड़ा करने का था। प्रशांत किशोर सीधे अध्यक्ष सोनिया...

राजस्थान

35 | राजनीति का केंद्र बना राजस्थान

राजस्थान इस समय देश की राजनीति का केंद्र बिंदु बना हुआ है। देश की दो सबसे बड़ी पार्टियां भाजपा और कांग्रेस इस महीने राजस्थान में अपने-अपने दल की बड़ी बैठकें कर रही हैं। कांग्रेस ने अपनी पार्टी की दशा-दिशा सुधारने के लिए राजस्थान के उदयपुर में 13 से 15 मई...

बिहार

38 | विरासत की जंग

चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच छिड़ी विरासत की जंग के बाद अब लालू प्रसाद यादव के घर में भी जंग शुरू हो गई है। तेज प्रताप यादव बगावत के मूड में नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप ने अपना सरकारी बंगला छोड़ दिया है।

6-7 अंदर की बात
41 महिला जगत
42 अध्यात्म
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

अपनी बात

मुफलिसी भी नहीं बन पाई राह का रोड़ा...

किसी शायर ने लिखा है...

नीयत साफ हो जिनकी उनके कदमों में जमीं होती है,
आसमां में उड़ने वालों को कब सितारों की कमी होती है।

ये पंक्तियां इस बार माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं-12वीं बोर्ड में अव्वल आने वाली लड़कियों पर खरी उतरती हैं। हर बार की तरह इस बार भी माशिमं की बोर्ड परीक्षाओं में बेटियों ने टॉप कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। इनमें से भी अधिकांश लड़कियां गरीब, मजदूर, किसान आदि की हैं। इन बेटियों ने साबित कर दिया है कि अगर लक्ष्य साधने का मन बना लिया जाए तो मुफलिसी भी राह में रोड़ा नहीं अटका सकती है। जज्बे से भरी इन बेटियों के चेहरों की मुस्कान उनके हौसले बयां करती है। किसी के पिता किसान हैं, किसी के मजदूर, तो कोई सड़क किनारे रेहड़ी लगाने या सिलाई का काम करते हैं। इनमें पिता के साये से महरूम रहीं बेटियां भी हैं, जिनकी मां ने बेटी के सपने को पंख देने की ठानी। ये बेटियां मुफलिसी के बीच पली-बढ़ीं, लेकिन इनके इरादों में कोई कमी नहीं दिखती। तभी तो इन्होंने मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में अपना परचम लहराया, टॉपर बनीं और मिसाल भी। माशिमं की दोनों ही बोर्ड परीक्षाओं की मेरिट लिस्ट में लड़कियों का वर्चस्व रहा। हाईस्कूल परीक्षा में 55 छात्राएं एवं 40 छात्र (कुल 95) मेरिट में आए हैं। इस वर्ष भी छात्रों की तुलना में छात्राओं ने बाजी मारी है। इसी तरह हायर सेकेंडरी परीक्षा परिणाम की मेरिट सूची में 93 छात्राओं एवं 60 छात्रों (कुल 153) ने स्थान पाया है। इसमें भी छात्राओं ने छात्रों की तुलना में अधिक स्थान प्राप्त किया है। इस साल हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा में नियमित छात्रों के पास होने का प्रतिशत 56.84 और नियमित छात्राओं के पास होने का प्रतिशत 62.47 रहा। शासकीय विद्यालयों का परीक्षाफल 55.40 प्रतिशत एवं अशासकीय विद्यालयों का 69.48 प्रतिशत रहा है। हाईस्कूल में मेरिट सूची में 55 छात्राओं और 40 छात्रों (कुल 95) ने स्थान पाया है। हायर सेकेंडरी परीक्षा में इस बार 72.72 प्रतिशत नियमित तथा 32.90 प्रतिशत स्वाध्यायी परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। नियमित छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 69.94 और नियमित छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 75.64 रहा। शासकीय विद्यालयों का परीक्षाफल 70.92 प्रतिशत और अशासकीय विद्यालयों का 76.30 प्रतिशत रहा है। वहीं 2015 से 2022 तक के आंकड़ों को देखें तो यह सामने आएगा कि 10वीं एवं 12वीं दोनों कक्षाओं में छात्रों के मुकाबले छात्राएं आगे रही हैं। वर्ष 2022 की हाईस्कूल के परिणाम में 65.87 फीसदी छात्राएं और 56.84 फीसदी छात्र सफल रहे, यानि लड़कियों का प्रतिशत 5.63 फीसदी अधिक रहा। वहीं हायर सेकेंडरी में भी 75.64 फीसदी छात्राएं और 69.94 फीसदी छात्रों ने सफलता हासिल की है। इस बार भी लड़कों के मुकाबले लड़कियां 5.70 फीसदी अधिक पास हुई हैं। लड़कों का पास होने का प्रतिशत हर साल कम रहा है। कोविड महामारी के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई के बाद हुई ऑफलाइन परीक्षा के परिणाम भले ही संतोषजनक नहीं रहे लेकिन बेटियों ने यह दिखा दिया कि घर पर पढ़ाई करके भी लक्ष्य को साधा जा सकता है। अभावों के बीच पढ़कर जिस तरह बेटियों ने बोर्ड परीक्षाओं में अपना परचम लहराया है, उससे यह बात साबित हो गई है कि पढ़ाई के लिए सुविधाओं की नहीं बल्कि जज्बे की जरूरत है। बेटियों की परफॉर्मेंस से मप्र सरकार भी उत्साहित है और सरकार ने अव्वल आने वाली बेटियों को कई तरह की सुविधाएं देने की घोषणाएं की हैं।

- राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स

वर्ष 20, अंक 16, पृष्ठ-48, 16 से 31 मई, 2022

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

ब्यूरो
कोलकाता:- इंद्रकुमार, **छत्तीसगढ़:**- संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी,
जयपुर:- आर.के. बिन्नानी, **लखनऊ :**- मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता
094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे
098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया
094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार
098934 77156, (गंजबासौदा) ज्योत्सना अनूप यादव
089823 27267, (रतलाम) सुभाष सोमानी
075666 71111, (विदिशा) मोहित बंसल

क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी
फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान)
मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर,
फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर,
भिलाई, मोबाइल 094241 08015
इंदौर : नवीन रघुवंशी, रघुवंशी कॉलोनी, इंदौर,
मो.-9827227000
देवास : जय सिंह, देवास
मो.-7000526104, 9907353976

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

पत्र–संपादक के नाम

aksnews.com

कांग्रेस सक्रिय

2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर मप्र कांग्रेस काफी सक्रिय हो गई है। कांग्रेस में नई रणनीति को लेकर मंथन किया जा रहा है। गुटबाजी के कारण असमय कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ा था, लेकिन अब कांग्रेस के दिग्गज एक होकर मप्र में चुनाव जीतने की तैयारी में जुटे हुए हैं।

● **पूजा सोनी,** भोपाल (म.प्र.)

मप्र विकास की ओर

मप्र आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। मप्र अपने गठन के समय बूझी गई संभावनाओं को साकार करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। खासतौर से पिछले डेढ़ दशक का अरसा इस बात का गवाह रहा है, कि मप्र विकास के पथ पर अब आगे ही आगे है।

● **फातिमा कुरैशी,** इंदौर (म.प्र.)

अस्पताल की लूट

कोरोनाकाल में कई निजी अस्पतालों ने मरीजों की हालत खराब कर दी। अस्पतालों ने तो आईसीयू में भर्ती मरीजों से 3 लाख रुपए से भी ज्यादा ले लिया। एक तरफ सरकार लोगों को आयुष्मान भारत मिशन जैसी सुविधाएं दे रही है, वहीं अस्पताल मरीजों को परेशान कर रहे हैं।

● **सुरेंद्र सिंह,** ग्वालियर (म.प्र.)

गर्मी से सीख

इस साल देशभर में जो गर्मी पड़ी है, उसके जिम्मेदार कहीं न कहीं हम ही हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग को न्यौता दे रहे हैं। बड़े स्तर पर पेड़ों को काटकर हम अपने आने वाले भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। विशेषज्ञों ने दावा किया है कि आने वाले वर्षों में धरती पर जो आपदाएं बढ़ेंगी, उनमें जंगलों में आग और बाढ़ जैसी मौसम संबंधी प्राकृतिक आपदाएं होंगी। इसके साथ ही महामारी और रासायनिक दुर्घटनाओं जैसी खतरनाक आपदाएं भी शामिल होंगी। यदि ऐसा ही चलता रहा तो दुनिया को 2030 तक हर साल करीब 560 विनाशकारी आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है और अधिक से अधिक पौधरोपण करने की जरूरत है।

● **ऋषभ साहू,** पिपरिया (म.प्र.)

बिजली का संकट

बिजली की कमी ने प्रदेश सरकार की तैयारियों की पोल खोल दी है। आए दिन राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई शहरों में घंटों तक बिजली कटौती की जा रही है। प्रदेश में बिजली संकट की सबसे बड़ी वजह कोयला है। माइंस से रेलवे की रैक पर्याप्त नहीं मिल पा रहे हैं इस वजह से कमी है। ज्यादातर इकाईयां कोयले से बिजली बनाती है। इसके अलावा बिजली की बैकिंग इस समय होती है क्योंकि रबी सीजन के लिए ज्यादा बिजली की जरूरत होती है। सरकार को बिजली के इस संकट को खत्म करने उपाय निकालना होगा।

● **अमन गर्ग,** होशंगाबाद

किसान परेशान

मप्र सहित कई राज्यों में कपास की खेती बड़े पैमाने पर होती रही है। लेकिन कोरोनाकाल से लेकर कृषि कानूनों को लेकर चले किसान आंदोलन और यूक्रेन–रूस के युद्ध के चलते खेती पर विपरीत असर पड़ा है। इससे कपास की उपज से लेकर कारोबार तक प्रभावित हुआ है। सरकार की ओर से अनदेखी और कोरोना महामारी से कपास की बिकवाली सही तरीके से नहीं हो पाई है। हाल यह है कि कपास में तो किसानों की लागत तक नहीं निकल पाई है।

● **हेमलता शर्मा,** जबलपुर (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन–1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ–02, 03, एमपी नगर, भोपाल

वक्त का फेर

देश के सबसे बड़े सूबे उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पुलिस महानिदेशक को एक झटके में हटा दिया। गोयल उप्र कैडर के आईपीएस अधिकारियों में काफी वरिष्ठ हैं। अभी तो नौकरी भी 21 महीने बची है। 1987 बैच के गोयल अपने पद पर एक वर्ष भी पूरा नहीं कर पाए। अपने मूल कैडर में आने से पहले गोयल ने करीब पांच साल केंद्र में डेपुटेशन पर बिताए थे। हितेश अवस्थी के सेवानिवृत्त होने के बाद गोयल को पिछले साल जून में उप्र पुलिस की कमान सौंपी गई थी। लेकिन मुख्यमंत्री के साथ उनके सहज और मधुर रिश्ते कभी नजर नहीं आए। इसके पीछे शासन के कुछ आईएएस और आईपीएस अफसरों की लॉबिंग का तो असर था ही, संघ के दबाव में नियुक्ति पाना भी था। चर्चा तो उन्हें हटाने की विधानसभा चुनाव से पहले भी खूब सुनाई पड़ी थी। शायद तब मुख्यमंत्री ने संघ परिवार और पार्टी आलाकमान की नाराजगी मोल लेना ठीक नहीं समझा होगा। एक डर चुनाव आयोग के हस्तक्षेप का भी रहा होगा। हकीकत तो यह है कि लखनऊ का सचिवालय भी नौकरशाहों की अंदरूनी खेमेबाजी से मुक्त नहीं है। गोयल को हटवाने के पीछे असली भूमिका सूबे के अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी और इस समय कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक बनाए गए देवेंद्र सिंह चौहान की मानी जा रही है।

भतीजे की भावना

एक वक्त था जब महाराष्ट्र की सियासत में कयास लगाए जाते थे कि बालासाहब ठाकरे का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। उस समय बालासाहेब के पुत्र उद्धव ठाकरे सियासी संकोची के रूप में दिखते थे और उनके भतीजे राज ठाकरे की एक मजबूत छवि बन रही थी। लेकिन वक्त के साथ बालासाहेब ने अपने पुत्र उद्धव को ही अपना उत्तराधिकारी बनाया जो आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन इन दिनों राज ठाकरे जितनी शिद्दत से बालासाहेब को याद कर रहे हैं वह सियासी गलियारों में चर्चा का विषय है। राज ठाकरे ने ट्विटर पर बालासाहेब का वह वीडियो डाला जिसमें वे सड़क पर नमाज पढ़ने और मस्जिदों के लाउडस्पीकर के खिलाफ बोल रहे हैं। राज ठाकरे उद्धव पर इस बात के लिए निशाना साध रहे हैं कि हिंदू हृदय सम्राट के पुत्र होते हुए भी हनुमान चालीसा से डरते हैं। राज ठाकरे का भगवा शाल भी लोगों की नजर में आ रहा है जिसे वे इन दिनों बालासाहेब की शैली में ही ओढ़ रहे हैं। साल 2006 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की स्थापना के बाद भी राज ठाकरे का सियासी कद नहीं बढ़ा और उनके चचेरे भाई मुख्यमंत्री हैं। अब राज ठाकरे यही दिखाने की कोशिश में हैं कि बालासाहेब के असली वैचारिक उत्तराधिकारी वे ही हैं। शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने राज ठाकरे की इस नकल पर बालासाहेब ठाकरे का वीडियो डालते हुए तंज कसा। प्रियंका ने अपने ट्वीट में कहा कि नकल करने वाले कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं।

चुनावी साल के बवाल

चुनावी साल में हिमाचल में कहीं भर्ती के पर्चे लीक हो रहे है तो कहीं खालिस्तानी झंडे लग रहे हैं। ऐसे में आक्रामक प्रचार के लिए मशहूर भाजपा मुश्किल में है कि वह अपना प्रचार अभियान कैसे शुरू करे। हिमाचल में हिंदू-मुसलमान करना भी इतना आसान नहीं है। खालिस्तानियों के नाम पर भी वोट बटोरे नहीं जा सकते। उल्टे सरकार की ही फजीहत होगी। ऐसे में भाजपा व इसके रणनीतिकार असमंजस में हैं कि शुरूआत कहां से करें। भाजपा ने कुछ लोगों को सर्वे कराने पर लगा रखा है। कुछ और काम कर रहे हैं। लेकिन माहौल नहीं बन रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ही नहीं अब तो प्रधानमंत्री तक का दौरा कराने की कोशिश हो रही है। पिछले 6 महीने में हिमाचल में जहरीली शराब का कांड हो चुका है। उसके बाद ऊना में पटाखों के कारखाने में धमाका हो चुका है। इन दोनों मामलों में दो दर्जन के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। अब पुलिस भर्ती का पर्चा लीक हो गया है। नेताओं की सिफारिशों पर तो भर्ती होती रही है और इल्जाम भी लगते रहे हैं। लेकिन लेन-देन के किस्से पहली बार सुनने को आ रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिन भाजपा के लिए मुश्किल भरे होने वाले हैं।

हुई बहुत सस्ती शराब

आम आदमी महंगाई से त्रस्त है वहीं दिल्ली एनसीआर के मदिरा प्रेमियों की बांछें शराब की लगातार घटती कीमतों से खिली हुई हैं। भाग्य विधाता राजनीतिकों ने तीन चीजों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा है। पेट्रोलियम पदार्थ, तंबाकू उत्पाद और मदिरा। देशभर में एक समान कर प्रणाली की व्यवस्था के बावजूद इन उत्पादों पर हर राज्य अपनी सुविधा और मर्जी से टैक्स लगाने को स्वतंत्र है। तंबाकू उत्पाद और पेट्रोलियम पदार्थ तो महंगे किए जा रहे हैं पर दिल्ली हरियाणा के बीच शराब की कीमतें घटाने को लेकर जंग छिड़ी है। गुरुग्राम में हालांकि हरियाणा सरकार ने थोक विक्रेता (एल-1) लाइसेंस पहले से दे रखे थे। जो खुदरा कीमत से कम पर शराब की बिक्री वर्षों से 24 घंटे कर रहे थे। पड़ोसी राज्यों दिल्ली, राजस्थान और उप्र के राजस्व पर इसका प्रतिकूल असर होने लगा तो अरविंद केजरीवाल ने पिछले साल नवंबर में आबकारी राजस्व बढ़ाने के फेर में शराब विक्रेताओं को 25 फीसदी तक की कटौती की इजाजत दे दी।

गुजरात भाजपा में भारी बेचैनी

इस वर्ष के अंत में गुजरात विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में भाजपा आलाकमान ने अभी से चुनावी तैयारियां शुरू कर डाली हैं। गत वर्ष एंटी इन्कमबेंसी को कम करने की नीयत से पार्टी ने न केवल मुख्यमंत्री बल्कि पूरी कैबिनेट ही गुजरात में बदल दी थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और उनके पूरे मंत्रिमंडल को बाहर का रास्ता दिखा भाजपा ने इतिहास रच डाला था। अब खबर जोरों पर है कि पार्टी हाईकमान ज्यादातर विधायकों के टिकट काट नए चेहरों पर दांव लगाने की कवायद में जुट गया है। सूत्रों की मानें तो टिकट कटने की आशंका ने प्रदेश भाजपा भीतर भारी बेचैनी पैदा कर दी है। दरअसल बीते 27 वर्षों से गुजरात में सत्ता पर काबिज भाजपा को इस दफे चौतरफा फैली एंटी इन्कमबेंसी का भय सता रहा है। विजय रूपाणी को हटा मुख्यमंत्री बनाए गए भूपेंद्र पटेल की परफॉरमेंस कुछ खास नहीं रही है। भाजपा किसी भी कीमत पर गुजरात नहीं खोना चाहती है।

अब चौथे से यारी...

उर्दू में एक प्रचलित कहावत है- इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। इसके बावजूद देश की सबसे पढ़ी-लिखी बिरादरी यानी ब्यूरोक्रेट्स प्रेम के पेंच लड़ाते रहते हैं और सोचते हैं इसकी जानकारी किसी को नहीं होगी। प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में ब्यूरोक्रेट्स के प्रेम के चर्चे अक्सर हुआ करते हैं, लेकिन वर्तमान समय में एक महिला आईएएस के इश्क के चर्चे चटखारे लेकर सुनाए जा रहे हैं। अभी तक तीन लोगों से प्यार की पारी खेल चुकी मैडम ने अब किसी चौथे व्यक्ति से यारी गांठ ली है। यह चौथा व्यक्ति कौन है, इसकी पड़ताल में मैडम के करीबी के साथ ही खबर्ची भी जुट गए हैं। 2014 बैच की इस महिला आईएएस ने पहले अपने बैच के ही एक आईएएस अधिकारी से शादी की थी, लेकिन इनकी शादी अधिक दिन नहीं चल पाई और मैडम ने मुंह मोड़ लिया। उसके बाद वे एक आईएफएस अफसर के साथ कुछ दिन लिव-इन में रहीं। बात आगे बढ़ती, इससे पहले ही मैडम का उनसे भी मन भर गया। फिर मैडम का दिल एक होमगार्ड सैनिक पर आ गया। दोनों के रिश्ते अभी प्रगाढ़ हो ही रहे थे कि उक्त सैनिक की हत्या हो गई। बताया जाता है कि अब मैडम का दिल किसी चौथे व्यक्ति पर आ गया है। मैडम इन दिनों उस व्यक्ति के साथ ही जीवन की लंबी पारी खेलने की प्लानिंग कर रही हैं। यह प्लान फेल होगा या पास होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बता दें मैडम इन दिनों राजधानी में पदस्थ हैं।

एक और पदयात्रा की तैयारी

मप्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री एक बार फिर पदयात्रा की तैयारी कर रहे हैं। गौरतलब है कि 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले इन माननीय ने अपनी पार्टी को सत्ता में वापसी कराने के लिए नर्मदा की पैदल परिक्रमा की थी। इसका फल भी मिला था और उनकी पार्टी सत्ता में वापस लौटी थी। आरोप ये भी लगे थे कि इन्हीं के कर्मों के कारण पार्टी 15 माह में ही सत्ता से बाहर भी हो गई थी। अब 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। सूत्रों का कहना है कि 2018 में पैदल परिक्रमा से 110 विधानसभा सीटों को साधने से उत्साहित माननीय अब एक बार फिर से पदयात्रा करने की ठान चुके हैं। इस बार ये किसी धार्मिक स्थल या नदी की बजाय जनता के दर पर पैदल पहुंचेंगे। माननीय की प्लानिंग के अनुसार वे अक्टूबर में अपनी पदयात्रा शुरू करेंगे। इस पदयात्रा के माध्यम से उन्होंने अबकी बार 200 पार का लक्ष्य भी तय किया है। हालांकि माननीय की पदयात्रा पर उन्हीं की पार्टी के कुछ लोग कटाक्ष भी कर रहे हैं कि हर बार बबूल के नीचे आम नहीं मिलता है। उधर, अपनी धुन के पक्के माननीय ने अपने शागिर्दों को यात्रा की तैयारी करने का निर्देश दे दिया है। अब देखना यह है कि यह यात्रा माननीय और उनकी पार्टी के लिए कितनी फायदेमंद होती है।

अभी आधी-अधूरी सुनवाई

प्रदेश में एक भारी-भरकम विभाग की जिम्मेदारी संभालने वाले आईएएस अधिकारी पिछले कुछ महीनों से अपनी विभाग में पदस्थ 4 महिला आईएएस से परेशान हैं। इसकी वजह यह है कि ये महिला आईएएस अधिकारी साहब की तनिक भी सुन रही हैं। साहब ने इन महिला आईएएस अधिकारियों को अपने यहां से हटाकर किसी दूसरे विभाग में पदस्थ करने के लिए प्रशासनिक मुखिया को पत्र लिखा था। साहब के पत्र को प्रशासनिक मुखिया ने गंभीरता से लेते हुए गत दिनों उनके विभाग से एक महिला आईएएस को दूसरी जगह भेज दिया। लेकिन अभी भी तीन महिला आईएएस जमी हुई हैं। सूत्रों का कहना है कि 1996 बैच के उक्त आईएएस अधिकारी सरकार की मंशानुसार विभाग को द्रुत गति से चलाना चाहते हैं, ताकि योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक से हो सके। इसके लिए उन्हें तेजतर्रार अफसरों की जरूरत है। ऐसे में विभाग में उनके सहयोग के लिए पदस्थ की गईं महिला आईएएस अधिकारी न तो समय पर ऑफिस आती हैं और न ही कामों का निपटारा कर पाती हैं। इससे साहब हैरान-परेशान हैं। साहब ने कई बार इन महिला अफसरों को चेतावनी भी दी है, लेकिन उन पर कोई असर नहीं पड़ा है। ऐसे में साहब चाहते हैं कि इनकी जगह किसी पुरुष अधिकारी को पदस्थ किया जाए। साहब की आधी-अधूरी मंशा पूरी हुई है। अब देखना यह है कि उनकी मंशा पूरी तरह पूर्ण कब होती है।

आखिर लौटना ही पड़ा

केंद्रीय मंत्री के रहमोकरम पर एक जोन में करीब 4 माह तक आईजी रहने के बाद एक आईपीएस अफसर को बदनामी की चादर ओढ़ने के बाद आखिरकार राजधानी लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं जिस अफसर की पदस्थापना रोककर इन्हें आईजी बनाकर भेजा गया था, अब उसी अफसर को इनकी जगह भेजा गया है। गौरतलब है कि जनवरी में 1997 बैच के तेजतर्रार आईपीएस अधिकारी को एक जोन का आईजी बनाया गया था, लेकिन एक केंद्रीय मंत्री के हस्तक्षेप के बाद उनकी पदस्थापना को रोककर उनके जगह 2002 बैच के आईपीएस अधिकारी को पदस्थ कराया गया। इसकी वजह यह थी कि उक्त आईपीएस अधिकारी मंत्रीजी के ओएसडी के रिश्तेदार हैं। अपनी पदस्थापना के बाद से ही साहब अपनी सुस्ती के कारण चर्चा में बने रहे। इनकी यह सुस्ती ही अंतत: उन पर भारी पड़ी और एक बड़े कांड के बाद उन्हें चलता कर दिया गया। सबसे हैरानी की बात यह है कि केंद्रीय मंत्री ने जिस अफसर का विरोध किया था अब वही अफसर उस जोन में आईजी पदस्थ किए गए हैं।

3 मौतों का जिम्मेदार कौन ?

इसे विडंबना ही कहेंगे कि जिस दौर में प्रदेश में माफिया, अपराधियों और तस्करों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जा रहा है, उसी समय प्रदेश में 3 पुलिसकर्मियों को तस्करों द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रशासनिक सख्ती के बीच तस्कर ऐसा कदम कैसे उठा पाए। सूत्रों का कहना है कि प्रदेश में सरकार के मुखिया भले ही अपराध और अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए हैं, लेकिन शासन-प्रशासन में बैठे कुछ लोगों की मिलीभगत से माफिया, अपराधी और तस्कर निरंतर अनैतिक गतिविधियों में जुटे हुए हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि इनको संरक्षण देकर मोटी रकम भी वसूली जा रही है। ऐसे में अपराध और अपराधियों को खत्म करने की मुहिम अधूरी रह जाती है। बताया जाता है कि गुना जिले में बड़े स्तर पर अपराधिक गतिविधियां चल रही हैं और उन्हें सरकारी संरक्षण भी मिल रहा है। जिसके कारण अपराधियों के हौंसले बुलंद हैं। ऐसे ही संरक्षण प्राप्त अपराधियों ने कर्त्तव्यनिष्ठ 3 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया।

बिना ड्यूटी की शराब नहीं बिकेगी

बोतलों पर लगाए जाएंगे नवीन एक्साईज एडहेसिव लेबल

प्रदेश में अवैध और जहरीली शराब पर अंकुश लगाने के लिए आबकारी विभाग ने मदिरा की बोतलों पर नवीन एक्साईज एडहेसिव लेबल लगाने के निर्देश जारी किए हैं। इस निर्देश के अनुसार विदेशी मदिरा निर्माण इकाईयों, बीयर निर्माण इकाइयों, देशी मदिरा निर्माण इकाईयों को आबकारी विभाग मप्र एवं प्रतिभूति मुद्रणालय, हैदराबाद के मध्य निष्पादित अनुबंध के अनुक्रम में विभाग को नवीन एक्साईज एडहेसिव लेबल का उपयोग किया जा रहा है। ई-आबकारी पोर्टल पर समस्त इकाईयों के लाइसेंसियों, प्रभारी अधिकारियों की यूजर आईडी एवं उपयोग में सहायता हेतु यूजर मैन्युअल संलग्न किया गया है। शराब की बोतलों पर इस नवीन एक्साईज एडहेसिव लेबल लगाने से जहां अवैध शराब के कारोबार पर नकेल कसेगी, वहीं सरकार की आय भी बढ़ेगी।

घोटालों व साठगांठ के आरोपों से घिरा रहने वाला आबकारी विभाग भी ऑनलाइन होने जा रहा है। जल्द ही ई-आबकारी पोर्टल लांच होने वाला है। इससे ठेकेदार ई-वॉलेट से भुगतान कर सकेंगे। अफसर इसकी निगरानी कर सकेंगे। विभाग विशेष अवसरों पर शराब पिलाने के लिए एक दिन का लाइसेंस देता है। पोर्टल पर ही आवेदन कर राशि जमा की जा सकेगी। शराब दुकान व ब्रांड के आधार पर रेट लिस्ट उपलब्ध रहेगी। कहीं ज्यादा वसूली हो रही है तो ऑनलाइन शिकायत की जा सकेगी। कलेक्टर व अन्य प्रशासनिक अफसर भी निगरानी कर सकेंगे। किसी इलाके में अवैध शराब बिक्री की शिकायत की जा सकेगी। हर जोन के अधिकारियों के नाम व नंबर रहेंगे।

प्रदेशभर में अब अवैध, जहरीली या किसी अन्य प्रदेश से चोरी-छुपे आई शराब नहीं बिक पाएगी। आबकारी विभाग शराब की हर बोतल पर बार कोड लागू कर रहा है। इससे कोड स्कैन करते ही पता चल जाएगा कि यह शराब कहां से आई है और कहां के लिए, किस कंपनी से बनी है। अभी बोतल पर सिर्फ होलोग्राम होता है। विभाग का दावा है कि इससे पता चल जाएगा कि शराब असली है या नकली। साथ ही ड्यूटी चुकाई हुई है या नहीं? अभी यह प्रयोग तेलंगाना, दिल्ली, चंडीगढ़ सहित कुछ राज्यों में हो रहा है।

आबकारी के सूत्रों के मुताबिक शराब की हर बोतल का यूनिक नंबर होगा। शराब फैक्टरी से बोतल निकलने से पहले राज्य सरकार उसे एक नंबर जारी करेगी। बार कोडिंग नंबर को ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम पर डालकर कहीं भी असली-नकली की पहचान हो सकेगी। विभाग बार कोडिंग की शुरुआत कर रहा है, जिसमें शराब के ब्रांड के साथ बोतल का नंबर, स्थान समेत सभी जानकारी होगी। सरकार का तर्क है कि बार कोडिंग से न सिर्फ असली शराब मिलेगी, बल्कि पड़ोसी राज्यों से तस्करी होकर बिकने वाली शराब भी बंद होगी।

विभाग के अधिकारियों ने बताया कई बार ऐसी जानकारी भी मिलती है कि कंपनियां ड्यूटी फ्री शराब बेच रही हैं। कुछ लोग भी इस तरह का धंधा करते हैं। अब यदि कोई ठेकेदार ऐसा करेगा तो चेकिंग में उसकी पूरी डिटेल सामने आ जाएगी। एक अहम बदलाव यह भी हो रहा है कि अब तक ठेकेदारों को माल मंगवाने के लिए पहले बैंक से चालान भरना पड़ता था। अब आबकारी पोर्टल के माध्यम से इन्हें ई-वॉलेट की सुविधा मिलेगी, जिससे ऑनलाइन पेमेंट हो सके।

दरअसल, घोटालों व साठगांठ के आरोपों से घिरा रहने वाला आबकारी विभाग भी ऑनलाइन होने जा रहा है। जल्द ही ई-आबकारी पोर्टल लांच होने वाला है। ठेकेदार को राशि बैंक अथवा ट्रेजरी में जमा कर विभाग को रसीद देनी होती थी। इन रसीदों के कारण ही इंदौर में 42 करोड़ का घोटाला हो चुका है। इससे बचने के लिए पुरानी व्यवस्था बंद कर ठेकेदारों को ई-आबकारी पर ई-वॉलेट की सुविधा दी जाएगी। जहां से वे सीधे राशि जमा कर सकेंगे। किसी को एक दिन की पार्टी के लिए लाइसेंस चाहिए तो वह ऑनलाइन आवेदन कर राशि जमा कर लाइसेंस ले सकेगा। इससे उसे विभाग के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

आबकारी विभाग के अधिकारियों पर ठेकेदारों से साठगांठ के आरोप लगते रहे हैं। यह भी आरोप हैं कि वे अवैध शराब की बिक्री को अनदेखा करते हैं। व्यवस्था में सुधार के लिए ई-आबकारी पोर्टल कुछ दिनों में लांच होने वाला है। इस पोर्टल में जिलेवार हर ठेकेदार का अकाउंट व ई-वॉलेट रहेगा। ई-वॉलेट से सारे शुल्क ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। स्थानीय अफसरों के साथ भोपाल व ग्वालियर मुख्यालय के अफसर भी सीधे जानकारी लेते रहेंगे। अधिकारी ने बताया कि ई-आबकारी पोर्टल लांच होने वाला है। इससे विभाग की सारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। 2017 में हुए आबकारी घोटाले में विभाग के 7 वरिष्ठ अफसर अब तक जांच में फंसे हैं। करीब 20 करोड़ की राशि तो डूब भी चुकी है। ठेकेदार ने विभाग को फर्जी रसीदें दी और अधिकारियों द्वारा इसे चेक नहीं करने पर घोटाला हुआ था। ऑनलाइन सुविधा से ऐसे घोटालों की आशंका खत्म होने का दावा है।

इधर ठेकेदार आबकारी विभाग के चक्कर काट रहे हैं। अप्रैल में पहली बार खुली दुकानों में स्टॉक हो रहा है, वहीं कई ग्रुप ने इंदौर के साथ अन्य जिलों में भी दुकानें ले ली हैं। इनका कहना है कि चालान भरने के बाद भी डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है। डिपो में माल ही नहीं है। इस मामले में अधिकारियों का कहना है कि नई दुकानें खुलती हैं तो थोड़े दिन सेटलमेंट में लगते हैं। गरमी और शादियों की वजह से भी डिमांड बढ़ी है। मालूम हो, इंदौर में हर महीने 225 करोड़ से ज्यादा की शराब बिक्री होती है।

● **सुनील सिंह**

बिहार को भाया मप्र का गौ संरक्षण मॉडल

मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गौ सरक्षण के लिए अनुदान का जो मॉडल अपनाया है उसे देशभर में सराहा जा रहा है। गौरतलब है कि मप्र सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती करने वाले देसी गोपालकों को प्रतिमाह 900 रुपए देने की घोषणा की गई है। अब बिहार भी मप्र के इस मॉडल को लागू करने जा रहा है। बिहार में प्रति गायपालक को 10,800 रुपए देने की योजना बनाई गई है।

गौरतलब है कि देश में खेती की लागत को कम करने एवं रासायनिक खेती से हो रहे नुकसान को कम करने के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो वहीं अब मप्र की तर्ज पर बिहार में भी देसी गायों को संरक्षण दिया जाएगा। अभी बिहार सरकार मप्र मॉडल का अध्ययन करा रही है। सारे तथ्यों पर विचार के बाद गायों के संरक्षण का कोई आदर्श मॉडल अपनाया जाएगा। यानी कि अगर आप भी गौपालक या फिर गौ पालने की इच्छा रखते हैं तो यह खबर आपको खुश कर देगी। बिहार में गायों के संरक्षण के लिए गोशालाओं के साथ निजी गोपालकों को भी प्रोत्साहित करने की तैयारी है। इस संबंध में उपमुख्यमंत्री व पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने प्रदेश की सभी गोशालाओं के अध्यक्षों और सचिवों की बैठक बुलाई है। बिहार में गोवंश के संरक्षण-संवर्धन के लिए आत्मनिर्भर बिहार सात निश्चय के तहत कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। पशु विज्ञान विश्वविद्यालय गोवंश विकास संस्थान की स्थापना की प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

वहीं बात करें बिहार में सरकारी गोलाओं की तो अभी 33 जिलों में केवल 86 सरकारी गोशालाएं मौजूद हैं। इन सभी गोशालाओं का सरकार ने विस्तृत ब्यौरा मांगा है। इसके साथ ही गोशालाओं की भूमि, उसकी स्थिति और पशुओं की संख्या आदि की जानकारी मांगी गई है। आपको बता दें कैमूर, अरवल, बांका, शिवहर और पूर्णिया जिले में अभी एक भी सरकारी गोशाला नहीं है। तो वहीं तारकिशोर प्रसाद का कहना है कि ज्यादा दूध लेने की होड़ में देसी गायें उपेक्षित हो रही हैं। उनका संरक्षण-संवर्धन के लिए बंद गोशालाओं को शुरू कराने और जरूरत के अनुसार नई गोशाला बनाना जरूरी है। इसके साथ ही उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि राज्य सरकार सीमांचल इलाके में गोवंश की तस्करी हर हाल में रोकेगी। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि प्रदेश में गोवंश को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता में है। सरकार पशु चिकित्सकों के खाली पदों को भरने की भी कोशिश में लगी हुई है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सक तैनात कर दिए जाएंगे।

एक दौर था, जब गांवों में ज्यादातर लोग, खासकर किसान पशुपालन करते थे। तब हर गांव में चारागाह भी होते थे और खेतों में भी हरा चारा व गेहूं-धान कटने पर भूसा-पुआल जैसा सूखा चारा भी भरपूर होता था। क्योंकि पशुपालक और किसान इस चारे को सालभर के लिए संचित करके रखते हैं। समय बदला, सोच बदली और आधुनिक खेती होने से सूखे चारे की कमी होती गई। इसके बावजूद मप्र इन दिनों दुधारू प्रदेश बना हुआ है। यहां दूध की नदियां बह रहीं हैं। दूध उत्पादन में देश में तीसरे स्थान वाले मप्र में अब रिकार्ड दूध उत्पादन की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि इस वर्ष राज्य में दूध उत्पादन 19 हजार टन का आंकड़ा पार कर चुका है हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि अभी नहीं हो सकी है। राष्ट्रीय स्तर पर रिपोर्ट जारी होने के बाद ही सही स्थिति सामने आएगी। स्थिति ये है कि प्रदेश में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 545 ग्राम प्रतिदिन पर पहुंच गई है। दूध की यह उपलब्धता राष्ट्रीय औसत 405 ग्राम से भी ज्यादा है। प्रदेश में 10 हजार 205 दुग्ध सहकारी समितियां हैं जिनसे दूध का संकलन बढ़ाया गया। हाल ही में गुजरे वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदेश को यह उपलब्धि प्राप्त होने की उम्मीद है।

जानकारी के अनुसार प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2016-17 में 13 हजार 445 टन दूध उत्पादन हो रहा था, जो वित्तीय वर्ष 2020-21 में बढ़कर 17 हजार 999 टन हो गया। प्रदेश के लिए यह बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि वित्तीय वर्ष 2015-16 से पहले प्रदेश का दूध उत्पादन 12 हजार टन से भी कम था। जिसे देखते हुए सरकार ने दूध उत्पादन बढ़ाने के प्रयास शुरू किए। गाय-भैंस को खुरा (पैर और मुंह में होने वाला रोग) सहित अन्य बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। पौष्टिक पशु आहार की इकाइयां खुलवाई गईं। प्रदेश में सिंचाई रकबा और फसल उत्पादन बढ़ने से भी गाय-भैंस की सेहत सुधरी है। इसी का असर है कि प्रदेश में महज चार साल में साढ़े चार हजार टन से अधिक दूध उत्पादन बढ़ गया।

● **लोकेंद्र शर्मा**

10,205 समितियां कर रही दूध संकलन

प्रदेश में वर्ष 2001 में 190 दुग्ध सहकारी समितियां थीं, जिन्हें बढ़ाकर 10 हजार 205 किया गया। जाहिर है दूध का संकलन बढ़ गया। जिससे दूध उत्पादन के सही आंकड़े आना शुरू हुए। इन समितियों ने कोरोना संक्रमणकाल में भी दूध संकलन का सिलसिला जारी रखा। भारत सरकार की देखरेख में हर साल दूध उत्पादन का सर्वे कराया जाता है। पिछले वित्तीय वर्ष में भी सर्वे हुआ है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार दूध उत्पादन का आंकड़ा 19 हजार टन को पार कर जाएगा। पशुपालन विभाग के अधिकारी बताते हैं कि सर्वे के आंकड़े केंद्र स्तर पर घोषित किए जाते हैं। संचालक पशुपालन डॉ. आरके मेहिया का कहना है कि प्रदेश में पालतू पशुओं के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। सिंचाई का रकबा बढ़ने, कृषि उत्पादन बढ़ने से प्रदेश में दूध उत्पादन बढ़ रहा है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भी उत्पादन बढ़ने के संकेत हैं।

मप्र में आगामी विधानसभा चुनाव 2023 में होंगे। लेकिन इससे पहले ही चुनावी मैदान सज गया है। कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ तो भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चेहरा होंगे। इन दोनों नेताओं ने अपनी-अपनी पार्टी के आलाकमान से मिले संकेत के बाद रणनीतिक तैयारियां तेज कर दी हैं। दोनों नेता अब पूरी तरह चुनावी मोड में हैं और पार्टी को भी सक्रिय कर रहे हैं।

मिशन 2023 शिव बनाम नाथ

उप्र, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में मिली शानदार जीत के बाद भाजपा ने इस साल के आखिर और 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्लानिंग शुरू कर दी है। इस साल होने वाले चुनावों के साथ ही छत्तीसगढ़ और राजस्थान में साल 2023 में होने वाले चुनावों में भाजपा का चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे, जबकि मप्र में शिवराज सिंह चौहान चुनावी चेहरा बनेंगे। इसकी पुष्टि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी की है। वहीं कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर विश्वास जताया है और प्रदेश के नेताओं ने उनके चेहरे पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है।

भाजपा और कांग्रेस के चुनावी चेहरों को देखकर यह साफ है कि मिशन 2023 शिवराज के 15 साल के शासनकाल बनाम कमलनाथ 15 माह के शासनकाल के बीच होगा। मप्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास लगातार 4 बार मुख्यमंत्री बनने का रिकार्ड है। अपने अब तक के **15 साल** के कार्यकाल में उन्होंने विकास का ऐसा पहाड़ खड़ा किया है, जिसकी कांग्रेस कल्पना भी नहीं कर सकती है। प्रदेश में सत्ता और संगठन पूरी तरह शिवराज के साथ है। जबकि कांग्रेस में स्थिति अलग है। यहां आज भी पार्टी विभिन्न गुटों में बंटी हुई है। हालांकि चुनावी बेला में कमलनाथ ने एकता की कोशिश की है, लेकिन उसकी संभावना कम नजर आ रही है।

चौथी पारी में शिवराज सिंह चौहान ने आत्मनिर्भर मप्र का नारा दिया है। यानी 2023 के चुनावी शंखनाद से पहले वे प्रदेश को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। इसके लिए वे निरंतर योजनाएं-परियोजनाएं बनवा रहे हैं और उन्हें क्रियान्वित करवा रहे हैं। अभी हाल ही में दो दिन तक सतपुड़ा की खूबसूरत वादियों में मंथन करने के बाद अब टीम शिवराज चुनावी मोड पर आ गई है। दो दिन चले मंथन में शिवराज सरकार का पूरा फोकस मिशन-2023 पर रहा। पचमढ़ी चिंतन बैठक के बाद एक बात साफ हो गई है कि शिवराज सरकार अब पूरी तरह इलेक्शन मोड पर है और भाजपा 2023 का विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर ही लड़ने जा रही है। चिंतन बैठक में तय किया गया कि शिवराज सरकार के पिछले कार्यकाल की फ्लैगशिप योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, लाडली लक्ष्मी योजना के साथ-साथ तीर्थ दर्शन योजना को फिर से लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ सीएम राइज स्कूल योजना जिसकी तारीफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके है को भी नए शिक्षण सत्र से प्रारंभ करने का फैसला किया गया।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को 21 अप्रैल से फिर से नए स्वरूप में प्रारंभ किए गया। कन्या विवाह के **आयोजन की राशि** को 51 हजार से बढ़ाकर 55 हजार रुपए किया जा गया। प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले समारोह का विकासखंड के स्तर पर पहले से तिथि तय की जाएगी, प्रचार-प्रसार किया जाएगा। इसके साथ कोरोना के चलते बंद मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को 18 अप्रैल से शुरू किया गया। गंगा

2023 की तैयारियों में जुटी दोनों पार्टियां

मप्र में 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। क्योंकि अब चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है, लिहाजा भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों ने सक्रियता बढ़ाने के साथ अपने-अपने नेताओं को परफॉर्मेंस दुरुस्त करने का अल्टीमेटम भी दे दिया है। बीते दिनों दोनों ही दलों में बैठकों का दौर चला और संगठन के कार्यक्रमों में ढिलाई बरतने वाले पदाधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई गई। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में दोनों पार्टियों में इसका असर देखने को मिल सकता है। दरअसल, मप्र में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस बार चुनाव बेहद अहम माना जा रहा है कि ऐसे में सत्ताधारी भाजपा और विपक्षी दल कांग्रेस कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है। भाजपा जहां बूथ विस्तार अभियान और समर्पण निधि जैसे अभियानों के जरिए पार्टी को मजबूत करने में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस भी घर चलो घर-घर चलो अभियान के जरिए पार्टी को मजबूत करने की कोशिश में है।

स्नान, काशी कारीडोर, संत रविदास और कबीरदास के स्थलों के दर्शन के साथ योजना शुरु हुई। इसके साथ तीर्थ दर्शन यात्रा में मंत्री भी ट्रेन में तीर्थ यात्रियों के साथ जाएंगे। ट्रेन में बोगी में स्पीकर सिस्टम के माध्यम से तीर्थ स्थलों की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इसके साथ तीर्थ दर्शन यात्रा के कुछ स्थलों को हवाई तीर्थ दर्शन यात्रा से भी जोड़े जाने का फैसला किया गया है।

पचमढ़ी बैठक में शिवराज जिस आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई दिए वह यह बताता है कि उनको केंद्र की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार मप्र के कार्यक्रमों में वर्चुएल और एक्चुअल रूप से शामिल होना और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ करना भी इस बात के संकेत है कि भाजपा 2023 के विधानसभा चुनाव में मोदी और शिवराज के चेहरे के साथ उतरने की पूरी तैयारी कर चुकी है। पचमढ़ी चिंतन बैठक में शिवराज ने जिस आत्मविश्वास के साथ आने वाले समय में कार्यक्रमों का रेखाचित्र खींचा वह यह बताता है कि वह मप्र को देशभर में एक खास पहचान प्रदान करने के लिए पूरी तरह संकल्पित हैं। दरअसल सरकार की योजना और कार्यक्रम ही नहीं, बल्कि उन पर अमल के लिहाज से भी शिवराज राज्य में अपने लगभग सभी पूर्ववर्तियों से काफी आगे हैं। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण पक्ष यह कि चौहान ने नवाचार पर सर्वाधिक जोर दिया है। उनकी उपलब्धियों के खाते के **वृहद आकार** में इसी बात का सबसे बड़ा योगदान रहा है। ऐसे में जब शिवराज सिंह चौहान देश में भाजपा के सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड बना चुके हैं तब वह अपने नेतृत्व में मप्र की भाजपा शासित राज्य की एक ऐसी छवि बनाना चाह रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ की कसौटी पर पूरी तरह खरा उतरता हो।

प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है। गत दिनों प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आवास पर आयोजित पार्टी नेताओं की बड़ी बैठक में विधानसभा चुनाव की रूपरेखा तय कर एक

बड़ा निर्णय लिया गया। बैठक में सभी नेताओं ने एकजुट होकर तय किया कि प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कमलनाथ के नेतृत्व में ही मैदान में उतरेगी। कमलनाथ ने विगत दिनों प्रदेश के सभी दिग्गज नेताओं और पूर्व मंत्रियों को रात्रिभोज पर आमंत्रित किया था। यहां अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों की रणनीति पर मंथन किया गया। बैठक में सभी नेताओं ने एक सुर में कमलनाथ के नेतृत्व में भरोसा जताया और तय किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में कमलनाथ ही कांग्रेस का चेहरा होंगे। इसके साथ ही प्रदेश में कांग्रेस नेतृत्व को लेकर चल रही अटकलों पर पूरी तरह से विराम लग गया। प्रदेश में भाजपा के मजबूत संगठन से मुकाबला करने के लिए यह जरूरी भी है कि कांग्रेस चुनाव से पहले किसी तरह के संशय में न रहे। चेहरे को लेकर चली दुविधा और विवाद के चलते ही पंजाब में पार्टी को अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाए थे।

ऐसे में चुनाव से 18 महीने पहले ही कमलनाथ का चेहरा तय होना पार्टी के लिए बेहतर नतीजे देने वाला साबित हो सकता है। चेहरा तय होने के बाद पार्टी ने अब शिवराज सरकार की नीतियों पर मुखर होकर जनता के बीच जाने का फैसला लिया है। जनता से जुड़े मुद्दों का पूरी ताकत से उठाकर उनके साथ जनता को जोड़ने के लिए भी बैठक में मंथन हुआ।

बैठक में कमलनाथ ने भी जनता से जुडे मुद्दों को जन आंदोलन में बदलने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में अब महज 18 महीने ही बचे हैं। ऐसे में पूरी ताकत से चुनाव की तैयारियों में जुटना होगा। उन्होंने प्रदेश की बदहाल आर्थिक स्थिति, भ्रष्टाचार, व्यापमं घोटालों से रोजगार खोते युवाओं, महंगाई से त्रस्त महिलाओं और किसानों के मुद्दों पर पूर्व मंत्रियों से व्यापक जन आंदोलन प्रारंभ करने को कहा। बैठक के बाद कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी कांग्रेस के विधानसभा चुनाव में कमलनाथ के चेहरे के साथ ही उतरने की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ जन आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर ली गई है और अब विधानसभा चुनाव तक ये आंदोलन लगातार जारी रहेंगे। कांग्रेस के लिहाज से बैठक की सबसे अच्छी बात यह रही कि पार्टी में गुटबाजी की खबरों को प्रदेश के नेताओं ने ही खारिज किया। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने बैठक में कमलनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने की बात कही। वहीं अन्य वरिष्ठ नेताओं ने कमलनाथ द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी पर खरा उतरने का भरोसा दिलाया।

● **कुमार राजेन्द्र**

कांग्रेस ने भी दिया अल्टीमेटम

वहीं दूसरी ओर प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस ने भी कमर कस ली है, लेकिन संगठन की ओर से सौंपे गए दायित्वों को लेकर पदाधिकारियों की लेट लतीफी कमलनाथ के लिए बड़ी समस्या बन गई है। 25 फरवरी तक मंडलम सेक्टर में नियुक्तियों के अल्टीमेटम के बावजूद नियुक्तियां पूरी नहीं हुई हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि कमलनाथ क्या कड़ा रुख अपनाते हैं। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री महेंद्र सिंह चौहान का कहना है कि मप्र के सभी जिलों की 230 में से 190 विधानसभाओं में ही अब तक मंडलम सेक्टर की नियुक्ति हो सकी है। पार्टी नेताओं का दावा है कि 2 से 3 दिनों में और भी नियुक्तियां कर ली जाएंगी। दूसरी और संगठन ने पार्टी के विधायकों के साथ पदाधिकारियों को जनता के बीच रहने और उनकी मांगों, समस्याओं को जोर-शोर से उठाने के निर्देश दिए हैं और यह भी साफ कर दिया है कि सभी कार्यों को तय समय पर पूरा किया जाए। यानी 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों दल अभी से एक्शन मोड में जुट गए हैं। विपक्ष जहां जनता की समस्याओं और परेशानियों को लेकर मुखर नजर आ रहा है। तो वहीं भाजपा प्रदेश सरकार की योजनाओं को जनता के बीच पहुंचाने में जुटी हुई है।

विकास का मॉडल बने मप्र के गांव

ग्रामीण विकास योजनाओं से बदल रहा है ग्रामीण परिवेश

प्रदेश में गांवों की स्थिति अब तेजी से सुधर रही है। ग्रामीण इलाकों में विकास के नए सोपान गढ़े जा रहे हैं। प्रदेश को कई योजनाओं में देश में प्रथम स्थान मिलने से इसकी पुष्टि होती है। ग्राम सभाओं में भागीदारी, पंचायतों के सशक्तीकरण, सामूहिक विकास में समुदाय का समावेशन, सामुदायिक निगरानी, सहभागिता, सामुदायिक स्वामित्व जैसे मुद्दों के साथ ग्रामीण अधोसंरचना विकास, मूलभूत सुविधाएं, आवागमन, सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण, आत्मनिर्भरता, रोजगार-स्व-रोजगार, नवीन तकनीकियों की ग्राम स्तर तक पहुंच, विशेषकर शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और आजीविका क्षेत्र में प्रतिबद्धता से काम किए जा रहे हैं। इन तमाम प्रयासों से गांवों की तस्वीर बदलती दिख रही है। ग्रामीण क्षेत्र में उन्नत कृषि, पशुपालन में बुनियादी सुविधाएं, सिंचाई, भण्डारण, वृहद् बाजारों को गांव से जोड़ने के लिए भी उल्लेखनीय जतन किए गए हैं। वैज्ञानिक ढंग से विकास की प्रक्रिया का अनुसरण किए जाने से परंपरागत आय के संसाधनों पर निर्भरता कम होने के फलस्वरूप सकारात्मक परिवर्तन आना शुरू हुए हैं।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आत्मनिर्भर मप्र अभियान को प्रदेश के गांव संबल दे रहे हैं। इसकी वजह यह है कि प्रदेश सरकार के नवाचारों से गांवों की तस्वीर बदली है। आज मप्र के गांव देशभर के लिए विकास के मॉडल बने हुए हैं। यह संभव हो पाया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसौदिया के संयुक्त प्रयास से। अब मप्र के गांव भी स्वच्छता और सुविधाओं के मामले में छोटे नगरों को टक्कर देने लगे हैं। पंचायतें भी लक्ष्य तय करती हैं और आपसी प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने की होड़ में गांवों का नक्शा बदल रही हैं। गांवों की महिलाएं भी अब समूहों के रूप में उद्यमी बन रही हैं, जिससे वे आर्थिक रूप से सक्षम बनकर अपने बच्चों को शिक्षित बनाकर देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। नवाचारों ने विभाग में विकास की दृष्टि से नए आयाम स्थापित कराए हैं।

गौरतलब है कि प्रदेश की बड़ी आबादी गांवों में रहती है। इसलिए सरकार का फोकस भी गांवों पर रहा है। केंद्र की योजनाएं हो या राज्य की प्रदेश सरकार ने उनका सुनियोजित क्रियान्वयन गांवों में कराया है, इसलिए आज मप्र के गांव छोटे शहरों को टक्कर देने लगे हैं। गांवों में पलायन को रोकने के लिए सरकार ने ग्राम शिल्पी अभियान चलाया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास के इस नवाचार के तहत ग्रामीण शिल्पियों जैसे नाई, बढ़ई, कुम्हार, लोहार व बसोर आदि का चयन कर उन्हें व्यवसाय करने हेतु प्रेरित किया, उन्हें प्रशिक्षण दिलाया गया और पंचायत क्षेत्र में स्थान देकर उनका व्यवसाय शुरू कराया गया। इसका सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि जहां गांव में प्रशिक्षित शिल्पी मिलने लगे, तो वहीं इस वर्ग से जुड़े लोगों का पलायन भी रुकने लगा।

प्रदेश सरकार का शहर की ही तरह गांवों के विकास पर भी फोकस है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की अभ्युदय योजना को माध्यम बनाया गया है। विभागीय मंत्री महेंद्र सिंह सिसौदिया ने इस नवाचार पर व्यक्तिगत रूचि दिखाई जिसके कारण इस योजना के तहत प्रदेश के ब्लाक में 40-40 आदर्श गांव बनाए जा रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन गांवों का विकास कैसे हो, इसके लिए उसी गांव के प्रत्येक घर में सरकारी बाबू पहुंचेंगे और ग्रामवासी से पूछेंगे कि वे गांव को आदर्श बनाने के लिए क्या सोचते हैं। यानी कि घर-घर सर्वे किया जाएगा और इससे जो रोडमैप तैयार होगा, उसी आधार पर गांव का विकास कर उसे आदर्श गांव की श्रेणी में खड़ा किया जाएगा।

पैसे के लिए पुरूषों पर निर्भर रहने वाली ग्रामीण महिलाओं को बैंक सखी ने आत्मनिर्भर बना दिया है। इसके तहत स्व-सहायता समूहों की दीदी उन महिलाओं को दो हजार रुपए तक की नगद राशि उपलब्ध कराती हैं, जिन्हें पैसों की जरूरत होती है। वहीं विभाग ने एक ओर जहां महिलाओं को अपने हुनर के आधार पर व्यवसाय करने में सहायता उपलब्ध कराई तो उन्हें कर वसूली जैसे काम की जिम्मेदारी भी सौंपी। गांव में स्व-सहायता समूहों से जुड़ी कई महिलाएं अब रजिस्टर और रिकार्ड लेकर कर वसूली के काम में जुटी हुई हैं। दीदियों को बिजली बिल, जल कर एवं स्वच्छता कर वसूली का दायित्व सौंपा गया है। वर्तमान में 2 हजार से अधिक स्व-सहायता समूहों द्वारा उक्त वसूली का कार्य किया जा रहा है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री पोषणशक्ति योजना में विद्यार्थियों को ताजी एवं ऑर्गेनिक सब्जियां उपलब्ध कराने सभी शालाओं में मनरेगा के सहयोग से किचन गार्डन विकसित किए जा रहे हैं। पिछले वर्ष 24,271 मां की बगिया पूर्ण कराई गई है।

सरकार ने प्रदेश के हर गांव में विकास की उमंग भरने के लिए गांव का जन्मदिन मनाने का निर्णय लिया है। इसे ग्राम गौरव दिवस नाम दिया गया है। इससे जहां ग्रामवासियों को अपने गांव के प्रति गौरव का भाव उत्पन्न होगा, तो वहीं गांव के विकास के लिए भी ग्रामीणों के सुझाव भी मिलेंगे। यानी कि अब गांव का विकास कैसे और किस तरह से होना है, ये निर्णय कोई सरकारी बाबू नहीं गांव के लोग ही तय करेंगे कि गांव में कैसे विकास होगा। वहीं विभाग ने मनरेगा योजना से ग्रामीण शालाओं में पत्थरों के पटियों से डाइनिंग टेबल बनवाए हैं। ये टेबल पढ़ाई के साथ-साथ भोजन अवकाश में भोजन के काम भी आते हैं। अब इंटरवल में बच्चों को पेड़ के नीचे या जमीन पर बैठकर खाना खाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। इसका सबसे मजबूत पहलू ये रहा कि अब बच्चों की उपस्थिति स्कूलों में पहले से ज्यादा होने लगी और गांव के निर्धन व सक्षम बच्चों के बीच की दूरियां भी खत्म हो गई, वे शहरी क्षेत्र के बच्चों जैसा भाव महसूस करते हैं।

● **राजेश बोरकर**

मप्र कांग्रेस पर दिग्गी राजा का घेरा

मप्र में कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव कमलनाथ के चेहरे पर ही लड़ेगी। लेकिन विडंबना यह है कि प्रदेश कांग्रेस में दिग्विजय सिंह का दबदबा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। पार्टी संगठन का जैसे-जैसे विस्तार हो रहा है, दिग्विजय सिंह समर्थक नेताओं को मुख्य जिम्मेदारी मिलती जा रही है। इसे कमलनाथ के लिए बड़ी परेशानी का सबब बताया जा रहा है।

15 साल बाद 2018 में सत्ता में आई कांग्रेस 15 महीने बाद ही सत्ता से दूर हो गई। इसकी वजह पार्टी के दिग्गज नेताओं में समन्वय की कमी बताई गई। अब एक बार फिर से कांग्रेस सत्ता में वापसी की कोशिश में जुटी हुई है। लेकिन कमलनाथ की कांग्रेस में दिग्गी राजा का दबदबा बढ़ता जा रहा है, जिससे पार्टी में असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

मिशन 2023 की तैयारी में जुटी कांग्रेस दावा कर रही है कि वह एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। इसके लिए नेताओं को अलग-अलग जिम्मेदारी दी जा रही है। लेकिन देखा जा रहा है कि अधिकतर प्रमुख पदों पर दिग्विजय सिंह समर्थक का कब्जा होता जा रहा है। इससे विधानसभा चुनाव के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जिस तरह से दिग्विजय की पैठ होती जा रही है, उससे चुनाव के दौरान टिकट बंटवारे में कमलनाथ के पसीने छूट सकते हैं।

मप्र कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के विरोधी माने जाने वाले दिग्विजय सिंह धीरे-धीरे पीसीसी के पदों पर अपने लोगों को बैठाते जा रहे हैं। कार्यकारी अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष से लेकर कई पदाधिकारियों की फौज और युवा-महिला कांग्रेस-सेवादल व नेता प्रतिपक्ष तक दिग्विजय सिंह के समर्थक हैं। दिग्विजमय होती जा रही कांग्रेस से आने वाले विधानसभा चुनाव में कमलनाथ को उनके **समर्थकों** के टिकट को काटने में काफी परेशानी होगी।

गौरतलब है कि प्रदेश कांग्रेस में 1 मई को कमलनाथ ने 4 साल पहले कमान संभाली थी लेकिन तब उनके साथ जो लोग थे आज वे उनके सामने ही चुनौती बनते जा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से दिग्विजय ने कमलनाथ का साथ दिया था और सरकार बनने के बाद भी वे विधायक नहीं होते हुए भी सरकार में सीधा दखल करते थे। इसके बाद जब सरकार गिर गई तो धीरे-धीरे कमलनाथ-दिग्विजय सिंह के बीच रिश्तों में दूरियां आती गईं। हाल में जब दिग्विजय सिंह अपने बंगले के सामने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ धरना दे रहे थे तो कमलनाथ के साथ उनका सड़क पर जो संवाद हुआ, उससे दोनों के बीच के खटास भरे रिश्ते सार्वजनिक हो गए थे।

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह प्रदेश कांग्रेस में अपने समर्थकों को बैठाने में निरंतर कामयाब होते जा रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ अकेले पड़ते जा रहे हैं। कमलनाथ ने अपनी कार्यकारिणी में विधानसभा चुनाव, लोकसभा उपचुनाव के दौरान असंतुष्ट नेताओं को नियुक्ति पत्र बांटकर काफी बड़ी संख्या में पदाधिकारी बना दिए थे जिसमें उपाध्यक्ष-महासचिव और सचिवों के साथ प्रवक्ता और जिलों में कार्यकारी अध्यक्ष शामिल हैं। वहीं, दिग्विजय सिंह ने नए पदाधिकारियों में युवा कांग्रेस-महिला कांग्रेस, सेवादल की नियुक्तियों में अपने समर्थकों को बैठा दिया है तो नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह भी उनके साथ ही हैं। युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत पूर्व पीसीसी अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया के बेटे हैं जो दिग्विजय सिंह के निकट हैं।

कमलनाथ के साथ एक समय प्रदेश कांग्रेस के एक गुट के प्रमुख रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व पीसीसी अध्यक्ष सुरेश पचौरी हैं जिनके समर्थक राजीव सिंह इस समय कमलनाथ के साथ हैं। राजीव सिंह प्रभारी महामंत्री प्रशासन हैं। पचौरी इस समय कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरह ही कमलनाथ के साथ खड़े दिखाई देते हैं। इसी तरह पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व. अर्जुनसिंह के पुत्र, वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह भी इस समय गुटीय राजनीति से दूर हो गए हैं। विंध्य में इस समय कांग्रेस के लिए वह एक चेहरा हैं लेकिन उनके विरोधी बन चुके पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल उनका वहां स्थान लेने की कोशिश कर रहे हैं। माना भी जाता है कि विंध्य में अजय सिंह को कमजोर करने के लिए उनके विरोधियों ने पार्टी के ही कुछ नेताओं का सहारा लिया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व पीसीसी अध्यक्ष अरुण यादव इन दिनों अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में सक्रिय हुए हैं और वे प्रदेश में दौरे कर रहे हैं। मगर उन्हें विधानसभा चुनाव के पहले पीसीसी चीफ से हटाने और लोकसभा उपचुनाव खंडवा में जो झटके लगे हैं, उसको वे शायद ही भूल पाएंगे।

● **अरविंद नारद**

पीसीसी में कौन किसका समर्थक?

प्रदेश कांग्रेस में जहां कमलनाथ समर्थक के रूप में प्रभारी संगठन उपाध्यक्ष चंद्रप्रभाष शेखर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रकाश जैन, मोर्चा समन्वयक-महासचिव जेपी धनोपिया, अनुसूचित जनजाति अध्यक्ष अजय शाह, बाल कांग्रेस अध्यक्ष लक्ष्य गुप्ता, एनएसयूआई अध्यक्ष मंजूल त्रिपाठी, किसान कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश गुर्जर, मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा की गिनती होती है, वहीं दिग्विजय सिंह समर्थक के रूप में कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष व ग्वालियर ग्रामीण अध्यक्ष अशोक सिंह, युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, महिला कांग्रेस अध्यक्ष विभा पटेल, सेवादल अध्यक्ष रजनीश सिंह, अनुसूचित जाति मोर्चा अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी और नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह का नाम शामिल है। ऐसे में कमलनाथ दिग्विजय समर्थकों को अपने हिसाब से चला पाएंगे इसको लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हैं।

2018 के विधानसभा चुनाव में लगे झटके के बाद भाजपा मिशन 2023 के लिए फूंक-फूंककर रणनीति बना रही है। इसी रणनीति के तहत पार्टी ने प्रारंभिक फैसला किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक विधानसभा सीटों पर युवाओं को टिकट दिया जाए। इसके तहत पार्टी ने 60+ का फॉर्मूला बनाया है। यानी 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले नेताओं को इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा।

फॉर्मूले ने उड़ाई दिग्गजों की नींद

परिवारवाद से भाजपा की दूरी

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की टीम में भी नए चेहरों को मौका दिया गया है, जिसमें ज्यादातर युवा हैं। साथ ही परिवारवाद को भी दूर रखा गया है। नंदकुमार सिंह चौहान के निधन के बाद यह माना जा रहा था कि उनकी जगह उनके बेटे को टिकट मिल सकता है लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। ऐसा ही उदाहरण दमोह उपचुनाव में देखने को मिला, जहां पर जयंत मलैया और उनके बेटे को पार्टी ने टिकट नहीं दिया। हालांकि मलैया को टिकट न देने के चलते पार्टी को हार मिली। लेकिन पार्टी ने जो गाइडलाइन तय की है उसके मुताबिक ही चल रही है।

भाजपा इस समय पीढ़ी परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। संगठन में युवाओं को जिम्मेदारी देने के बाद अब पार्टी आलाकमान की मंशा है कि आगामी चुनाव में अधिक से अधिक युवाओं को टिकट दिया जाए। इसके लिए पार्टी ने 60+ का फॉर्मूला बनाया है। यानी 60 की उम्र पार कर चुके नेताओं को विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया जाएगा। अगर 2023 में भाजपा ने मप्र में यह फॉर्मूला लागू किया तो विधानसभा अध्यक्ष, 6 मंत्रियों समेत 30 विधायकों का टिकट कट सकता है।

प्रदेश भाजपा के उम्रदराज नेता सत्ता का मोह छोड़ पाएंगे या नहीं, यह तो भविष्य तय करेगा, लेकिन अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का टिकट मिलना मुश्किल लग रहा है। दरअसल, पार्टी के कई नेता 60+ वाले फॉर्मूले में फिट नहीं हैं। लिहाजा उन्हें टिकट मिलने में दिक्कत आ सकती है। पार्टी इन्हें चुनावी मैदान में उतारने में हिचकिचा सकती है।

2023 में पार्टी के 60+ के फॉर्मूले के आधार पर आंकलन करें तो विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, 6 मंत्री और पार्टी के लगभग 23 विधायक अगले साल होने वाले चुनाव के दौरान 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके होंगे। इनमें लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव, खाद्य मंत्री बिसाहूलाल सिंह, खेल एवं युवा कल्याण यशोधरा राजे सिंधिया, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी और पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण रामखेलावन पटेल का नाम शामिल है। ऐसे में पार्टी को देवतालाब, शिवपुरी, अमरपाटन, खुरई, सांची, रेहली और अनूपपुर के लिए नए उम्मीदवार की अभी से तलाश शुरू करनी होगी। वैसे इन नेताओं में से कईयों के पुत्र वर्षों से इन विधानसभा क्षेत्रों में सक्रिय हैं।

आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा के और जो विधायक 60+ के पार हैं या हो जाएंगे उनमें सूबेदार सिंह रजौधा-जौरा, गोपीलाल जाटव-गुना, पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय-हटा, श्यामलाल द्विवेदी-त्योंथर, पंचूलाल प्रजापति-मनगंवा, केदारनाथ शुक्ल-सीधी, अमर सिंह-चितरंगी रामलल्लू वैश्य-सिंगरौली, सुशील कुमार तिवारी-पनागर, करण सिंह वर्मा-इछावर, नारायण पटेल-मंधाता, देवीलाल धाकड़-गरोठ, यशपाल सिंह सिसोदिया-मंदसौर, डॉ. राजेंद्र पांडे-जावरा, अजय विश्नोई-पाटन, गौरीशंकर बिसेन-बालाघाट, सीतासरन शर्मा-होशंगाबाद, नागेंद्र सिंह-नागौद, नागेंद्र सिंह-गुढ़, जयसिंह मरावी-जयसिंह नगर, प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा-सिवनी मालवा, महेंद्र सिंह हार्डिया-इंदौर-5 और पारस जैन-उज्जैन उत्तर का नाम शामिल है।

कई ऐसे नेता भी हैं जो पिछले चुनाव में हार चुके हैं, लेकिन एक बार फिर अगले चुनाव के लिहाज से अपने क्षेत्रों में सक्रिय हैं। इन नेताओं में उमाशंकर गुप्ता, रामकृष्ण कुसमारिया, हिम्मत कोठारी और रुस्तम सिंह भी टिकट के लिए दावेदारी कर सकते हैं, लेकिन चुनाव तक इन सभी की आयु 70 के पार हो जाएगी। हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणामों में भी इस फॉर्मूले का गहरा असर पड़ा है। ऐसे में अब मप्र के दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान से बाहर होने का डर सताने लगा है। चुनाव आने पर पार्टी इनको रिटायर कर सकती है।

2018 में विधानसभा चुनाव के दौरान अमित शाह ने भोपाल में चिंतन मंथन किया था। तब उन्होंने संकेत दिया था कि 65+ नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इस कारण गौरीशंकर शेजवार, कुसुम मेहदेले, माया सिंह, हर्ष सिंह, अंतर सिंह आर्य सहित कई और बुजुर्ग नेताओं के टिकट काट दिए गए थे। हालांकि राजनीतिक दल कई तरह के मापदंड तय करता है, लेकिन चुनाव आने पर किसी भी तरह से सिर्फ जीत ही मकसद होता है। ऐसे में तय किए गए मापदंड भी कई बार ब्रेक किए जाते हैं। इसके बाद भी भाजपा-कांग्रेस ने 60+ या इससे अधिक उम्र वाले नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन इसमें से सिर्फ 3 को जीत मिली थी। भाजपा के तीन प्रत्याशी गुढ़ से नागेंद्र सिंह (76), नागौद से नागेंद्र सिंह (76) और रेगांव से जुगल किशोर बागरी (75) चुनाव जीतने में सफल रहे। गुढ़ विधायक नागेंद्र सिंह विधानसभा में सबसे उम्रदराज जनप्रतिनिधि बने थे। तब उनकी उम्र 76 वर्ष थी।

● **जय सिंह**

जहरीली हो रही हैं प्रदेश की नदियां

प्रदेश की इन नदियों को माना गया है प्रदूषित

मप्र की 22 नदियों को सबसे अधिक प्रदूषित माना गया है। इन्हें अब प्रदूषणमुक्त करने के लिए केंद्र सरकार ने भी प्रयास शुरू किया है। इसमें प्रमुख रूप से रीवा की बिछिया, टोंस चाकघाट (रीवा), मंदाकिनी चित्रकूट सतना, खान नदी इंदौर, क्षिप्रा उज्जैन, चंबल नदी नागदा (उज्जैन), बेतवा मंडीदीप भोपाल एवं विदिशा, कलियासोत कोलार, ताप्ती बुरहानपुर, गोहद, कटनी नदी, कुंडा नदी खरगोन, मालेनी जौरा, नेवाज शाजापुर, सिमरार कटनी, वैन गंगा सिवनी, सोन नदी धनपुरी, चामला बड़नगर, पार्वती नदी पीलुखेड़ी, चोपन गुना, कन्हान छिंदवाड़ा आदि हैं।

बढ़ते शहर एवं उद्योगों की वजह से नदियां तेजी के साथ प्रदूषित हो रही हैं। इनके संरक्षण के लिए बनाई गई कार्ययोजनाएं कागजी साबित हो रही हैं। कुछ समय पहले ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मप्र की नदियों की रिपोर्ट तलब की थी, जिसमें 22 नदियों में व्यापक प्रदूषण पाया गया था। इसमें रीवा जिले की दो नदियां बिछिया और टमस शामिल थी। साथ ही सतना के चित्रकूट में मंदाकिनी के प्रदूषण पर भी चिंता जाहिर की गई थी। एनजीटी ने प्रदेश सरकार से इन सभी नदियों को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए व्यापक कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया था। जिस पर सरकार ने भी उस दौरान तत्परता दिखाते हुए चिन्हित की गई नदियों को निर्मल बनाने के लिए कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया था। रीवा में जलसंसाधन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नगर निगम को जिम्मेदारी मिली थी कि वह बिछिया नदी को निर्मल बनाने के लिए व्यापक कार्ययोजना बनाएं।

शुरुआती दौर में कुछ कार्य हुआ लेकिन अन्य सरकारी योजनाओं की तरह इस कार्य में भी हीलाहवाली शुरू हो गई और अब इसकी फाइल धूल फांक रही है। रीवा में बिछिया नदी को पुनर्जीवित करने के लिए कार्ययोजना तैयार की गई है, जिसके लिए सरकार को भी प्रस्ताव भेजा गया है। नदियों को प्रदूषणमुक्त बनाने के लिए स्थानीय नगरीय निकायों को जिम्मेदारी दी गई है। रीवा में अमृत योजना के तहत सीवरेज प्रोजेक्ट का कार्य प्रारंभ किया गया है। नदी में शहर के गंदे नालों को मिलने से रोकने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जा रहे हैं। केंद्र के जलशक्ति मंत्रालय ने भी इसकी रिपोर्ट मंगाई है और कहा गया है कि विशेष कार्ययोजना के तहत केंद्र सरकार भी मदद देगी।

नदियों को प्रदूषण होने से बचाने के लिए स्थानीय स्तर पर तैयार किया गया एक्शन प्लान सरकार को भेज दिया गया है। इस मामले में बीते कई महीने से एक्शन प्लान बनाकर सरकार को दिया गया है। जिसमें लंबे समय से सरकार ने भी कोई संज्ञान नहीं लिया है। रीवा सहित अन्य नगरीय निकायों को एक्शन प्लान के मुताबिक कार्य करना है। इस प्लान में नदियों में गंदे पानी वाले नालों को रोकने के साथ ही नदियों के किनारे ग्रीन बेल्ट में अतिक्रमण को हटाने, नदियों में जरूरत के हिसाब से घाट तैयार करने और पौधरोपण कर बैंक एरिया के कटाव को रोकने का कार्य करना है। पूर्व से चल रहे कार्य तो किए जा रहे हैं लेकिन नए प्लान का असर अब तक नहीं देखा जा रहा है। रीवा में बिछिया और चाकघाट में टमस नदी का प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है।

बिछिया नदी रीवा में ही किले के पास राजघाट में बीहर में मिलकर समाप्त हो जाती है। यह कई वर्षों से प्रदूषण और अतिक्रमण का दंश झेल रही है। इस नदी को निर्मल बनाने जन अभियान भी चलाया गया। लोगों ने स्वयं श्रमदान कर इसकी सफाई कराई, जिसके बाद प्रशासन भी आगे आया और नदी का गहरीकरण कराया गया था। बरसात के बाद इस नदी में पानी की आवक बंद हो जाती है लेकिन रीवा शहर में दर्जनों की संख्या में नाले मिलने की वजह से इसमें पानी हर मौसम में शहर वाले हिस्से में भरा रहता है। नदी के दोनों किनारों में तेजी के साथ अतिक्रमण फैल रहा है।

नदियों को प्रदूषणमुक्त बनाने केंद्र सरकार के सहयोग से नगरीय निकायों में अमृत योजना लागू की गई है। करीब 5 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है लेकिन हर जगह यह प्रोजेक्ट लेटलतीफी और मनमानी का शिकार हो चुका है। जिसके चलते प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हाल ही में ही शर्तों के अनुसार समय पर काम नहीं कर पाने की दशा में जुर्माना भी लगाया है। जिसके तहत नगर निगम रीवा पर 214.10 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर सही काम नहीं करने की वजह से करीब 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। नगर परिषद चाकघाट को टमस नदी में मिलने वाले नालों को रोकने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का निर्देश था, वहां पर भी कार्य नहीं हुआ तो जुर्माना लगाने की प्रक्रिया चल रही है। इसी तरह चित्रकूट की मंदाकिनी नदी में भी स्वच्छ पानी छोड़ने के लिए कार्ययोजना बनाई गई है। रीवा में नदी संरक्षण के नाम पर 28 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट 10 वर्ष पहले भी लागू हुआ था।

मप्र में नदियों को स्वच्छ और प्रदूषणमुक्त बनाने के लिए सरकारी, धार्मिक, राजनीतिक और समाजिक स्तर पर रह-रहकर अभियान चलाया जाता है। लेकिन सारे अभियान असफल साबित हो रहे हैं, क्योंकि प्रदेश की लगभग सारी नदियां प्रदूषण की चपेट में हैं। कई नदियों का पानी तो जहरीला हो गया है। देश में मां के समान पूजित नदियां इस समय अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। इनमें से मप्र से उद्गम करने वाली कई नदियां भी शामिल हैं। दरअसल सभ्यता की जननी नदियां, उद्योगों की लापरवाही और राज्य व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनदेखी से मृतप्राय सी हो रही हैं। नर्मदा नदी तो डिंडोरी में बुरी हालत में है। उज्जैन के नागदा में केमिकल फैक्ट्री से निकलने वाला जहर चंबल में जा रहा है। सीहोर में सीवन नदी में बहता पानी नजर ही नहीं आ रहा। इस पर काई जमी है। औद्योगिक इकाइयां जहरीले पानी बिना ट्रीट किए नदियों में बहा रही हैं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्रवाई के बजाय फाइलें अलमारी में बंद कर रहा है।

● **राकेश ग्रोवर**

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार के प्रयास से अब मप्र ऑटोमोबाइल का हब बनेगा। इसकी उम्मीद प्रदेश के पहले ऑटो शो में जगी है। इंदौर में आयोजित तीन दिवसीय ऑटो शो कई कंपनियों ने प्रदेश में निवेश की इच्छा जताई है। एमपीआईडीसी के अधिकारियों का कहना है कि जिस तरह उद्योगों और निवेश को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक निवेश नीति बनाई गई है, उसी तरह अब ई-व्हीकल पॉलिसी बनाई जाएगी। इससे इंदौर, पीथमपुर सहित मप्र में ऑटोमोबाइल के ई-सेक्टर में उद्योग लगाने या निवेश करने करने वाली कंपनियों को कई प्रकार की छूट व रियायतें दी जाएंगी।

ऑटोमोबाइल का हब बनेगा मप्र

इंदौर में आयोजित ऑटो शो का आयोजन प्रधानमंत्री के मेक इंडिया का अनुसरण करते हुए किया गया। मप्र की ग्रोथ रेट 19.7 प्रतिशत देश में सबसे ज्यादा है। प्रति व्यक्ति आय 13 हजार से बढ़कर 1 लाख 24 हजार प्रतिवर्ष हो गई है। देश की जीडीपी में हमारा योगदान पहले 3.6 प्रतिशत था, अब 4.6 प्रतिशत हो गया है। अब बहुत जल्दी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए नई पॉलिसी लाने जा रही है। इस पॉलिसी के अंतर्गत सरकार 40 प्रतिशत तक निवेश प्रोत्साहन सहायता उपलब्ध कराएगी।

गौरतलब है कि पहले एमपी ऑटो शो में दूसरे दिन पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जहां हर साल इस शो के आयोजन की घोषणा कर दी, वहीं अगले वर्ष जनवरी में लगातार चार दिन बड़े आयोजन की भी जानकारी दी। 7 और 8 जनवरी को इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद 9 और 10 जनवरी को पहले प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने शासन की नई स्टार्टअप नीति जल्द जारी करने के साथ ही कहा कि अब प्रदेश बीमारू राज्य नहीं रहा। यहां तक कि कोरोनाकाल में भी 650 उद्योग स्थापित हुए, जिसके जरिए 40 हजार करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आया। मेक इन इंडिया की तर्ज पर आयोजित एमपी ऑटो शो का अब हर साल आयोजन होगा और जल्द ही प्रदेश ऑटोमोबाइल हब के रूप में भी पहचाना जाएगा। सिंगल विंडो सिस्टम के तहत 30 दिन में ही सभी तरह की अनुमतियां उद्योगों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत मिल जाती हैं। पीथमपुर को **देश का डेट्राइट** कहा जाता है। अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में पीथमपुर सेक्टर जैसी बात कही जाए।

ऑटो शो में औद्योगिक संगठन के विनोद अग्रवाल ने कहा कि देश के ऑटो उद्योग का कुल कारोबार करीब 100 बिलियन डॉलर है। इसमें से करीब 30 प्रतिशत हिस्सा हम निर्यात कर रहे हैं। देश की मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी में 35 फीसदी हिस्सेदारी ऑटो इंडस्ट्री की है। देश की जीडीपी में ऑटोमोबाइल उद्योग 7 प्रतिशत हिस्सेदारी कर रहा है। साथ ही यह क्षेत्र 3 करोड़ रोजगार भी दे रहा है। उद्योगपतियों ने कहा कि देश के ऑटो उद्योगों का कुल कारोबार करीब 100 बिलियन डॉलर है। इसमें से करीब 30 प्रतिशत हिस्सा हम निर्यात कर रहे हैं। उद्योगपतियों ने मुख्यमंत्री को सुझाव दिया कि एक्सपो को वार्षिक आयोजन के तौर पर मान्यता देते हुए हर वर्ष नियमित आयोजन की घोषणा की जाए। मंत्री दत्तीगांव ने मांग का समर्थन किया। मुख्यमंत्री ने माइक संभालते ही सबसे पहले हर साल ऑटो शो करवाने का ऐलान किया।

प्रदेश में औद्योगिक विकास और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए शासन द्वारा नई स्टार्टअप पॉलिसी मई में जारी की जाएगी। इससे प्रदेश में औद्योगिक विकास का ईको सिस्टम बनेगा। पीथमपुर में स्किल डेवलपमेंट एकेडमी की स्थापना की जा रही है। इसके लिए जरूरी भवन और अधोसंरचना शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। एकेडमी में प्रशिक्षण ले रहे युवाओं के कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए डेनमार्क, स्वीडन, जापान, जर्मनी के साथ टेक्नोलॉजी कोलाब्रेशन किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार पीथमपुर और मप्र में ऑटोमोबाइल उद्योगों की ओर से हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्तावों पर सहमति बन चुकी है।

प्रदेश सरकार मई में स्टार्टअप नीति के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए नई नीति घोषित करेगी। लोकेशन, पानी, जमीन की उपलब्धता के लिहाज से मप्र में उद्योगों के लिए आज भी आदर्श स्थिति है। इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट मैन्यूफैक्चरिंग के लिए आ रही नई नीति में 40

प्रदेश की शांति, उद्योगों के लिए अहम

उद्योगपतियों ने कहा कि अभी निवेश के लिए बेहतरीन समय है। आने वाले समय में 75 हजार करोड़ से एक लाख करोड़ के निवेश की उम्मीद की जा रही है। उद्योग प्रतिनिधियों ने मप्र की नीति और लोकेशन को तो उद्योगों के लिए मुफीद करार दिया। साथ ही यहां की शांति को भी अहम बताया। उन्होंने कहा कि अब हमें लोगों के बीच जाकर बताना होगा कि यहां की खासियत क्या है। उन्होंने कहा कि अभी यूरोप में चल रहे वाल्वो कंपनी के ट्रकों के इंजन जो यूरो-6 तकनीक के हैं, वे भी पीथमपुर से ही बनाकर निर्यात किए जा रहे हैं। प्रदेश के औद्योगिक नीति व निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन दत्तीगांव ने कहा कि अभी पूरी सरकार यहीं मौजूद है, रेड कारपेट बिछा है, जो निवेश करना चाहते हैं अभी आएं और मिलें।

प्रतिशत तक टैक्स राहत निवेश प्रोत्साहन सहायता के तहत उपलब्ध कराई जाएगी। अगर उद्योग निजी या अविकसित सरकारी भूमि पर स्थापित होते हैं तो बिजली, पानी, सड़क पर किए व्यय की प्रतिपूर्ति सरकार करेगी। उद्योगों को पावर टैरिफ में राहत मिलेगी। आरएंडडी के साथ गुणवत्ता प्रमाणन के लिए उद्योग द्वारा किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति भी सरकार करेगी। उद्योग दिव्यांगजन को ट्रेनिंग देते हैं, नौकरी देते हैं तो कौशल विकास और पीएफ राशि की प्रतिपूर्ति भी मप्र सरकार करेगी। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, स्टाम्प ड्यूटी, अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े प्रस्तावों पर केस-टू-केस विचार कर राहत मिल सकेगी।

सुपर कॉरिडोर और बिजासन रोड जंक्शन पर 25 एकड़ में आयोजित इस ऑटो एक्सपो में लगभग 100 कंपनियों ने हिस्सा लिया, जिनमें कई वाहन बनाने वाली, तो बाकी कंपनियां कलपुर्जे, टायर-ट्यूब से लेकर अन्य ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी शामिल हुईं। लगभग एक हजार ऑटोमोबाइल क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने इस ऑटो एक्सपो में हिस्सा लिया। चूंकि गर्मी काफी थी, इसलिए शाम 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ही इंदौरी दर्शकों की भीड़ रही। पहले दिन हालांकि भीड़ नहीं थी, मगर दूसरे और तीसरे दिन अच्छी संख्या में लोग मय परिवार के वाहनों को निहारने पहुंचे। बैटरी से चलने वाली आधुनिक साइकिलों से लेकर दोपहिया और अब जो नए ई-वाहन लॉन्च हो रहे हैं, उन्हें भी देखा गया। एमपीएसआईडीसी का कहना है कि लगभग दो दर्जन ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े उद्योगपतियों ने जमीनों की मांग भी की है, वहीं सबसे अधिक रुझान इलेक्ट्रिक वाहनों में देखा गया।

युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार दिलाने के लिए सरकार कई आकर्षक योजनाएं ला रही है। प्रधानमंत्री जल्द ही मप्र की पहली स्टार्टअप पॉलिसी और **पोर्टल लॉन्च** करने वाले हैं। नई स्टार्टअप पॉलिसी में युवाओं को उद्यमिता की ओर प्रोत्साहित करने के लिए कई तरह की राहत दी गई है। इस आयोजन में कई स्टार्टअप कंपनियों की भी मौजूदगी रही, वहीं एमएसएमई सेक्टर को भी प्रोत्साहन मिलने का अनुमान है।

नीति में मप्र स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज पुरस्कार स्थापित किया है, यह सरकार की समस्याओं का नवाचारी हल बताने पर 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिलाएगा। मप्र की स्टार्टअप पॉलिसी का कार्य क्षेत्र विस्तृत बनाया गया है। इसे इनोवेटिव आइडियाज तक ही सीमित नहीं किया गया है। सरकार अब इनोवेटिव प्रॉडक्ट मैन्यूफेक्चरिंग स्टार्टअप को भी सहायता देगी।

यह जानकारी एमएसएमई विभाग के आयुक्त पी. नरहरि ने ऑटो शो में आयोजित सेमिनार में दी। उन्होंने बताया, अब स्टार्टअप का क्षेत्र सीमित नहीं है। आईटी, फिनटेक व इनोवेटिव आइडिया को इनक्यूबेट करने वाले स्टार्टअप के साथ उत्पादन क्षेत्र में इनोवेटिव आइडियाज को भी पोषित किया जाएगा। इससे एमएसएमई को नया आयाम मिलेगा।

उन्होंने बताया, नीति में फाइनेंशियल राहत ही नहीं देंगे, एम्प्लायमेंट जनरेशन ग्रांट और अन्य छूट भी दी जाएगी। ऑटो सेक्टर में ईवी टेक्नालॉजी के साथ इनोवेटिव फ्यूल प्रॉडक्शन में क्रांति होने वाली है। नीति का उद्देश्य नवाचार को प्रोत्साहित करना है। स्टार्टअप नीति का प्रकाशन कर दिया गया है। इंदौर में ऑटोमेटिव पार्ट क्लस्टर भी तैयार किया जा रहा है।

मप्र स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज पुरस्कार- सरकारी विभागों की कई समस्याएं है। सरकार सभी विभागों की समस्याएं स्टार्टअप के समक्ष रखेगी। इनके लिए खुले तौर पर हल मांगे जाएंगे। स्टार्टअप द्वारा प्रस्तुत निराकरण का परीक्षण करवाएंगे। यदि यह निराकरण उस विभाग की समस्या के निराकरण पर खरा उतरेगा तो उस पर अमल किया जाएगा। इसके लिए आइडिया जनरेट करने वाले स्टार्टअप को 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार देंगे।

स्टार्टअप मेचिंग फंड- यह फंड सीड फंड की तरह होगा। स्टार्टअप को आरबीआई या सेबी से अधिकृत संस्थान से निवेश मिलता है तो सरकार इसमें 15 प्रतिशत राशि देगी। जैसे-यदि 1 करोड़ का निवेश मिला तो सरकार इस पर 15 लाख रुपए देगी। यह राहत चार बार ली जा सकेगी। महिलाओं को 20 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट मिलेगी। एम्प्लायमेंट जनरेशन ग्रांट का प्रावधान भी पहली बार किया गया है। इसमें सरकार एम्प्लायमेंट जनरेट करने पर कंपनी को प्रति रोजगार 5 हजार रुपए की सहायता देगी। इसके अलावा ट्रेनिंग के लिए भी अलग से राशि दी जाएगी। यह ग्रांट तीन साल के लिए होगी।

● **कुमार विनोद**

अब नौकर नहीं, मालिक बनने का जुनून...

स्टार्टअप की संख्या के मामले में नगर का नाम तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस लिहाज से देश के टॉप 10 नगरों में इंदौर का भी नाम शामिल हो गया है। स्टार्टअप की संख्या नगर में अचानक बढ़ी है। 2020 तक करीब 300 स्टार्टअप हुआ करते थे, लेकिन जनवरी 2022 तक संख्या करीब 700 हो गई है। इस वर्ष की शुरुआत में स्टार्टअप के लिए पहली बार बड़े स्तर पर कार्यक्रम कराने के दौरान पता लगा कि कई स्टार्टअप घरों में शुरू हो गए हैं। अब इनका डाटा तैयार किया जा रहा है। सबसे ज्यादा आईटी क्षेत्र के स्टार्टअप संचालित हो रहे हैं और अब तेजी से इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के लिए भी युवा आगे आ रहे हैं। पीथमपुर में ई-वाहन बनाने के लिए तीन बड़ी परियोजनाएं नगर के युवाओं ने शुरू की हैं। इसमें से एक ई-फाई स्टार्टअप ने खुद से 5 करोड़ रुपए का निवेश किया। पहले तक एक जैसे आइडिया पर काम करने वाले स्टार्टअप अब नवाचार को बढ़ा रहे हैं। इन्वेस्ट इंदौर के सचिव सावन लड्ढा का कहना है कि 700 स्टार्टअप में से करीब 100 ऐसे स्टार्टअप हैं, जिनका निवेश 10 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। कुछ स्टार्टअप एक हजार से दो हजार करोड़ रुपए तक के बन गए हैं। दो ऐसे स्टार्टअप भी हैं, जिनका निवेश 6 हजार करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है। शहर में आईटी क्षेत्र में काम करने वाले 250 से ज्यादा स्टार्टअप हैं। इनमें से कई की शुरुआत कोरोना महामारी के दौरान हुई है। दुनियाभर में ऑटोमेशन की मांग बढ़ने से आईटी क्षेत्र में बूम की स्थिति है।

मप्र सहित देशभर में इस समय कोयला संकट के कारण बिजली की समस्या परेशानी का सबब बनी हुई है। जहां अघोषित बिजली कटौती से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो रहा है, वहीं मप्र में निजी कंपनियां बिना बिजली दिए ही कमाई कर रही हैं। सरकार की गलत नीति के कारण जहां प्रदेश में बिजली संकट खड़ा हो गया है, वहीं निजी कंपनियों ने भी संकट के इस दौर में हाथ खड़े कर लिए हैं।

निजी कंपनियों की फांस में बिजली

मप्र में सरकारी ताप बिजली घरों से पर्याप्त विद्युत उत्पादन होने के बाद भी प्रदेश सरकार ने देश के धन्नासेठों की कंपनियों से बिजली खरीदने का अनुबंध कर प्रदेश पर आर्थिक बोझ तो डाला ही है, अब जब बिजली की जरूरत है तो कंपनियों ने हाथ खड़े कर लिए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि प्रदेश को अंधेरे में धकेलकर सरकार निजी बिजली कंपनियों को मालामाल कर रही है।

प्रदेश में पिछले एक महीने से कोयला संकट होने के कारण अघोषित बिजली कटौती की जा रही है। प्रदेश में 5 से 10 घंटे तक बिजली काटी जा रही है। वहीं ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर दावा कर रहे हैं कि प्रदेश में पर्याप्त बिजली है। फिर सवाल उठता है कि बिजली कटौती की वजह क्या है। निजी कंपनियों से घालमेल का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बिजली खरीदी के 25-25 साल के एमओयू (करार) होने के बावजूद पिछले साल जब कोयला संकट गहराया था, तब बिजली कंपनियों ने निजी सेक्टर से अतिरिक्त बिजली खरीदी थी। गत वर्ष 31 अगस्त और 1 सितंबर को 1,163 मेगावाट अतिरिक्त बिजली खरीदी गई थी। यह बिजली सामान्य से अधिक दर पर खरीदी थी।

बिजली विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार ने अडानी, रिलायंस, टोरेंट पावर, बीएलए पावर, जेपी बीना पावर, एस्सार पावर और लिंको आदि कंपनियों से 2025 तक बिजली खरीदने का करार किया है। संकट में बिजली की गारंटी के लिए सरकार हर साल इन निजी कंपनियों को फिक्स चार्ज के रूप में औसतन 4,000 करोड़ रुपए देती है। यह भारी-भरकम रकम निजी कंपनियों को इसीलिए दी जाती है, ताकि संकट के समय जरूरत के अनुरूप प्रदेश को बिजली मिल सके, लेकिन इसके उलट अब कोयला संकट के बीच निजी सेक्टर की अनुबंध वाली कंपनियों ने भी पर्याप्त आपूर्ति में असमर्थता जता दी है। ऐसे में इनसे मिलने वाली बिजली में कमी आई है। जिसके कारण प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती की जा रही है।

सरकार दावा कर रही है कि प्रदेश में 22,500 मेगावाट बिजली की उपलब्धता है। लेकिन आधी बिजली भी नहीं मिल पा रही है। यही नहीं संकट के समय अनुबंध वाली कंपनियों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। सूत्रों का कहना है कि अनुबंध के अनुसार बिजली पर्याप्त नहीं मिलने पर जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन सरकार निजी बिजली कंपनियों पर जुर्माना लगाने के बजाय उन पर मेहरबानी कर रही है। इससे पहले सितंबर 2021 में जब कोयला संकट छाया था, तब भी बिजली कंपनियों ने पूर्व के अनुबंधों के तहत आपूर्ति में असमर्थता जाहिर की थी। नतीजा यह रहा कि प्रदेश को खुले बाजार से बिजली लेनी पड़ी थी।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार निजी बिजली कंपनियों में टोरेंट पावर, बीएलए पावर, जेपी बीना पावर, एस्सार पावर, अडानी, रिलायंस और लिंको से विभिन्न प्रकार के अनुबंध किए गए हैं। इनमें विभिन्न श्रेणियों में 70 पैसे से 2.10 रुपए प्रति यूनिट तक औसतन फिक्स चार्ज है। प्रदेश सरकार को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन और एनटीपीसी के पॉवर प्लांट्स को भी फिक्स चार्ज देना पड़ता है। इसमें प्रदेश को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन को औसत 516 करोड़ रुपए चुकाने होते हैं। एनटीपीसी के पावर प्लांट्स का 300 से 400 करोड़ रुपए तक का चार्ज बनता है। वर्ष 2020 में इस फिक्स चार्ज को गलत बताकर इसके खिलाफ नियामक आयोग में याचिका भी लगाई गई थी।

वहीं विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ डाटा 2019-20 के मुताबिक, मप्र ने निजी सेक्टर से 2,034 करोड़ रुपए सालाना फिक्स चार्ज देने के करार कर रखे हैं। जबकि हर साल औसत 4,000 करोड़ निजी सेक्टर को दिए जाते हैं। वित्तीय 2020-21 में 4,200 करोड़ रुपए का फिक्स चार्ज निजी सेक्टर को दिया गया है। आर्थिक गणित में फेल होने के कारण ही मप्र में बिजली की दर लगभग हर साल बढ़ जाती है। इसी का परिणाम है कि मप्र देश में सबसे महंगी बिजली देने वाले राज्यों में शुमार है। मप्र में सभी खर्च मिलाकर औसतन 7.10 रुपए प्रति यूनिट बिजली हो चुकी है। इस साल बिजली में 2.64 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इससे सबसे ज्यादा भार घरेलू उपभोक्ताओं पर पड़ा है।

● **श्याम सिंह सिकरवार**

सरकारी की बजाय निजी पर भरोसा

प्रदेश में सरकारी प्लांट की बजाय निजी प्लांट पर भरोसा इस कदर है कि लॉकडाउन में भी निजी सेक्टर से बिजली खरीदी का एमओयू किया गया। 2020 में लॉकडाउन के दौरान अडानी समूह की कंपनी से थर्मल बिजली खरीदी का एमओयू किया गया, जिसमें 4 रुपए 79 पैसे प्रति यूनिट बिजली खरीदी का एमओयू हुआ है। हालांकि सरकार की सरकारी प्लांट की बिजली औसतन 2 रुपए प्रति यूनिट की पड़ती है। जहां फिक्स चार्ज में करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं, वहीं बिजली कंपनियों के घाटे में बढ़ोतरी हो रही है। बिजली कंपनियां 4,000 करोड़ का सालाना घाटा बताती हैं, जबकि कंपनियों का कर्ज ही 50 हजार करोड़ पार हो गया है।

किसानों की आमदनी घटी

केंद्र और राज्य सरकारें 2022 में किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्य पर कार्य कर रही हैं, लेकिन मप्र सहित 4 राज्यों में किसानों की आमदनी घटी है। इसका खुलासा 24 मार्च को कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण पर गठित संसद की स्टैंडिंग कमेटी द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में पेश की गई रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार मप्र में प्रति किसान परिवार की मासिक आय में 1,401 रुपए की कमी आई है। वर्ष 2015-16 में एक किसान परिवार की आय 9,740 रुपए महीने थी, जो 2018-19 में घटकर 8,339 रुपए हो गई। विशेषज्ञों का अनुमान है कि ताजा स्थिति में भी सुधार नजर नहीं आता। यह तब है जब केंद्र सरकार किसानों के हित में 20 से ज्यादा योजनाएं चला रही है।

समिति ने अपनी रिपोर्ट में दो सर्वे के आंकड़े बताए हैं। ये सर्वे 2015-16 और 2018-19 के हैं। इन सर्वे के हवाले से समिति ने बताया है कि 2015-16 में देश के किसानों की महीने की औसत आमदनी 8 हजार 59 रुपए थी, जो 2018-19 तक बढ़कर 10 हजार 218 रुपए हो गई। यानी 4 साल में महज 2 हजार 159 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। सबसे ज्यादा कमाई मेघालय के किसानों की है। यहां के किसान की हर महीने की आमदनी 29 हजार 348 रुपए है। दूसरे नंबर पर पंजाब है, जहां के किसान 26 हजार 701 रुपए एक महीने में कमाते हैं। वहीं, तीसरे नंबर पर 22 हजार 841 रुपए की कमाई के साथ हरियाणा के किसान हैं।

देश में 4 राज्य ऐसे हैं जहां किसानों की आमदनी कम हो गई है। इनमें मप्र, झारखंड, ओडिशा और नागालैंड शामिल हैं। झारखंड के किसानों की हर महीने की कमाई 2 हजार 173 रुपए, वहीं नागालैंड में 1 हजार 551 रुपए तो मप्र में 1400 रुपए और ओडिशा में 162 रुपए की आमदनी घट गई है। कमेटी ने सुझाव दिया है कि सरकार को एक स्पेशल टीम बनानी चाहिए जो इन राज्यों में किसानों की घटती आमदनी के कारणों का पता लगाए। साथ ही इन राज्यों में सही कदम उठाने का सुझाव भी दिया है। किसान और प्रांत प्रचार प्रमुख मध्यभारत भारतीय किसान संघ राहुल धूत का कहना है कि कृषि से जुड़ी मशीनरी, खाद-बीज, दवा, डीजल समेत अन्य चीजों के मूल्य पिछले कुछ सालों में दोगुने से ज्यादा बढ़ गए। इस वजह से खेती की लागत बढ़ती जा रही है। इसकी तुलना में किसान की आमदनी नहीं बढ़ रही है।

किसानों की आमदनी बढ़ी है तो खर्च भी बढ़ गया है। बीते साल नवंबर में सरकार ने बताया था कि हर महीने 10,218 रुपए कमाते हैं तो 4,226 रुपए खर्च हो जाते हैं। किसान हर महीने 2 हजार 959 रुपए बुआई और उत्पादन पर तो 1 हजार 267 रुपए पशुपालन पर खर्च करता है। यानी, किसानों के पास हाथ में 6 हजार रुपए भी पूरे नहीं आते। पिछले साल जुलाई में वित्त मंत्रालय ने बताया था कि 31 मार्च 2021 तक किसानों पर 16.80 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज था। उस समय ये भी साफ कर दिया था कि किसानों की कर्ज माफी करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने मप्र को पिछले तीन साल में 3 हजार करोड़ से ज्यादा की राशि दी है। इसके बाद भी अन्नदाता की माली हालत में सुधार नहीं आया। जिन 4 राज्यों में किसान की मासिक आय कम हुई है उसे लेकर संसद की स्थायी समिति ने रिपोर्ट में लिखा है कि इन राज्यों में राज्य का कृषि विभाग केवल मूक दर्शक बना रहा। यानी जो योजनाएं चल रही हैं, उन्हें जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए प्रयास या मेहनत नहीं की गई। रिपोर्ट में लिखा कि राज्य सरकार की तरफ से कोई जवाब ही नहीं दिया गया। मप्र में एक करोड़ किसान हैं, जिनमें आधे से ज्यादा सीमांत हैं। प्रदेश में करीब 170 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि है, जिसमें 4 लाख करोड़ का उत्पादन होता है।

5700 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबे किसानों को राहत देने के लिए सहकारिता विभाग एकमुश्त समझौता योजना तैयार कर रहा है। इस योजना के तहत कर्ज नहीं चुकाने के कारण डिफाल्टर हुए 14 लाख 57 हजार किसानों को सरकार ब्याज माफी देने जा रही है। इसमें किसानों को मूलधन चुकाने पर लगभग 200 करोड़ रुपए की ब्याज माफी दी जाएगी। गौरतलब है कि वर्ष 2019 में कमलनाथ सरकार ने किसान ऋण माफी योजना लागू की थी लेकिन इसका फायदा किसानों को नहीं मिल पाया। सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने बताया कि योजना के कारण किसानों ने समय पर ऋण नहीं चुकाया और डिफाल्टर हो गए। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद सहकारिता विभाग एकमुश्त समझौता योजना तैयार कर रहा है। डिफाल्टर किसानों के ऊपर 5700 करोड़ रुपए का कर्ज है। प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को ब्याज रहित अल्पावधि ऋण दिया जाता है। प्रतिवर्ष 27-28 लाख किसान खरीफ और रबी फसलों के लिए ऋण लेते हैं और उपज आने पर ऋण चुका देते हैं। यही क्रम चलता रहता है।

● **जितेंद्र तिवारी**

तय सीमा में कर्ज चुकाने पर मिलेगा लाभ

गौरतलब है कि डिफाल्टर किसान को ब्याज देना पड़ता है और आगे ऋण भी नहीं मिलता है। इससे परेशान किसानों की मदद करने के लिए मुख्यमंत्री ने ब्याज माफी की घोषणा की है। इसके लिए सहकारिता विभाग एकमुश्त समझौता योजना ला रहा है। इसमें किसान द्वारा निश्चित समय सीमा में मूलधन चुकाने पर ब्याज माफी दी जाएगी। मूलधन दो या तीन किश्तों में अदा किया जा सकेगा। इसके लिए सहकारिता विभाग एकमुश्त समझौता योजना बना रहा है। इसके पहले भी सरकार किसानों को कर्ज के बोझ से मुक्ति दिलाने के लिए एकमुश्त समझौता योजना लागू कर चुकी है। राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के एक लाख से ज्यादा किसानों के लिए योजना लागू की गई थी। इसमें भी ब्याज माफ किया गया था। 15 हजार से ज्यादा किसानों ने योजना का फायदा उठाया था। घाटे में चलने के कारण सरकार ने बैंक को बंद करने का निर्णय लिया है और परिसमापन की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि, कर्जदार किसानों से ऋण वसूलने का दायित्व जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों को सौंपा जा रहा है क्योंकि किसानों को ऋण नाबार्ड से राशि लेकर दिया गया था।

बर्दाश्त के बाहर महंगाई

आपकी हैसियत चाहे जो हो, हाल के महीनों में महंगाई की चुभन आपने जरूर महसूस की होगी। अगर आप निम्न आय या मध्य वर्ग से हैं तो क्या कहने। संभव है कि आपकी थाली में दो की जगह एक सब्जी रह गई हो, या किसी दिन वह भी नसीब न होती हो। सरकारी आंकड़े भले रिकॉर्ड महंगाई बता रहे हों, लेकिन वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण इसे भी नकारने के अंदाज में कहती हैं, यह बहुत ज्यादा नहीं है। पर आप यह सोचकर अपनी हताशा दूर कर सकते हैं कि इस बार समस्या विश्वव्यापी है। अमेरिका में भी महंगाई चार दशक के रिकॉर्ड स्तर पर है। हां, यह जरूर है कि भारत में लोगों को 5 वर्षों से लगातार कठिन परिस्थितियों से जूझना पड़ रहा है। पहले तो नोटबंदी और जीएसटी के कारण 93 फीसदी रोजगार देने वाले असंगठित क्षेत्र पर मार पड़ी। फिर दो साल पहले आई महामारी ने भी सबसे अधिक नुकसान इसी क्षेत्र को पहुंचाया। अब जब रूस-यूक्रेन युद्ध ने महंगाई को पलीता लगाया है तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने यह कहकर जले पर नमक छिड़कने का काम किया है कि भारत में गरीबी घट गई है।

खुदरा महंगाई मार्च 2022 में 6.95 फीसदी हो गई जो 17 महीने में सबसे ज्यादा है। रिजर्व बैंक ने इसकी ऊपरी सीमा 6 फीसदी तय कर रखी है लेकिन यह तीन महीने से इसके ऊपर है। थोक महंगाई मार्च में 14.55 फीसदी पहुंच गई और यह अप्रैल 2021 से दहाई अंकों में है। थोक महंगाई के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि उसमें सबसे अधिक योगदान कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल और मेटल का है जिनकी सप्लाई रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण बाधित हुई है। वैसे तो हर साल गर्मियों में फल-सब्जियां महंगी होती हैं लेकिन इस बार बात इससे ज्यादा है। विशेषज्ञों का कहना है कि थोक महंगाई लगातार 12 महीने दहाई अंकों में रहना सामान्य नहीं है।

इस महंगाई के पीछे कई कारण हैं। एक तो महामारी की वजह से विश्व स्तर पर जो सप्लाई बाधित हुई, वह अभी तक सामान्य नहीं हो पाई है। दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग हब चीन के शहरों में फिर लॉकडाउन लगने से वहां से निर्यात प्रभावित हुआ है। मेटल और कच्चे तेल के दाम विश्व बाजार में लगातार ऊंचे बने हुए हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध ने स्थिति को और बिगाड़ा है। भारत पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्य तेल, उर्वरक, मेटल आदि के मामले में काफी हद तक आयात पर निर्भर है और रुपया कमजोर होने से भी आयात महंगा हुआ है।

जानकार बताते हैं कि असंगठित क्षेत्र को परेशानी से संगठित क्षेत्र को बहुत फायदा हुआ। डिमांड संगठित क्षेत्र में शिफ्ट हो गई जिसने दाम बेतहाशा बढ़ाए हैं। रिजर्व बैंक के 1,500 कंपनियों के सर्वे के अनुसार इनका मुनाफा 24 फीसदी तक बढ़ गया है, जबकि अर्थव्यवस्था में उतनी तेजी नहीं आई है। बात सिर्फ फल-सब्जियों या ईंधन की नहीं, कॉरपोरेट के पास काफी प्राइसिंग पावर आ गई है। कंपनियां दाम बढ़ाकर ज्यादा मुनाफा कमा रही हैं। एक सर्वे के मुताबिक मार्च तिमाही में कंपनियों का रेवेन्यू 15 फीसदी तक बढ़ा, लेकिन उनका मुनाफा 26 फीसदी बढ़ गया।

रिजर्व बैंक ने भी कहा है कि महंगे ईंधन और खाद्य पदार्थों ने आम लोगों की जेब पर दबाव डाला है और युद्ध के कारण जोखिम बढ़ा है। सूरजमुखी तेल, गेहूं और अन्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ने का अंदेशा है। एल्युमीनियम और निकेल के दाम एक दशक की ऊंचाई पर हैं। रूस एल्युमिनियम के सबसे बड़े उत्पादकों में है जिसका इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में होता है। निकेल का ज्यादा इस्तेमाल हाईग्रेड स्टील बनाने और बैटरी में किया जाता है। रिजर्व बैंक के अनुसार भू-राजनीतिक तनाव से चिप की कमी बढ़ेगी जिससे वाहन और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के दाम बढ़ेंगे।

रूस पर अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिबंध का असर भी महंगाई पर है। युद्ध लंबा खिंचने के आसार दिख रहे हैं, तो महंगाई भी जल्दी नीचे आती लग नहीं रही है। युद्ध के कारण यूक्रेन में गेहूं, मक्का और सूरजमुखी की नई फसल की बुवाई नहीं हो पा रही है। इसलिए आने वाले दिनों में विश्व स्तर पर इनकी कमी होगी। विश्व गेहूं बाजार में भारत कुछ हद तक रूस और यूक्रेन की भरपाई करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इससे घरेलू बाजार में गेहूं महंगा हो गया है। मप्र और राजस्थान समेत कई राज्यों में गेहूं एमएसपी (2015 रुपए प्रति क्विंटल) से 700 रुपए तक ऊपर बिक रहा है। ज्यादा महंगाई का सीधा असर लोगों के रहन-सहन पर पड़ता है, क्योंकि उनकी कमाई महंगाई की रफ्तार से नहीं बढ़ती। अभी तो महामारी के कारण गई सभी नौकरियां ही वापस नहीं आई हैं। ऐसे में तार्किक बात तो यही है कि गरीबी बढ़ेगी। लेकिन आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने भारत में गरीबी घटने की बात कही है।

● **विकास दुबे**

पिछले कई सालों से महंगाई बनी समस्या

वैसे, महंगाई की समस्या पिछले साल से चली आ रही है। मार्केट रिसर्च फर्म नीलसन-आईक्यू के अनुसार दिसंबर तिमाही में दाम बढ़ने से एफएमसीजी उत्पादों की बिक्री मात्रा के लिहाज से 2.6 फीसदी घट गई, लेकिन मूल्य के लिहाज से 9.6 फीसदी बढ़ गई। कारण यह है कि कमोडिटी, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बढ़ने के कारण हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, मेरिको, प्रॉक्टर एंड गैंबल, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जैसी सभी प्रमुख कंपनियों ने अपने उत्पादों के दाम लगातार बढ़ाए हैं। रिटेल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बाइजोम के सर्वे के अनुसार महंगाई के कारण मार्च तिमाही में भी एफएमसीजी प्रोडक्ट की बिक्री धीमी हुई है।

चुनावी सड़कों का खाका तैयार

भाजपा 2023 के विधानसभा चुनाव में विकास को मुख्य मुद्दा बनाएगी। इसलिए सरकार का फोकस विकास योजनाओं पर है। इसी के तहत सरकार प्रदेश में ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराने जा रही है। इसके लिए भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर सहित अन्य जिलों की 2 हजार 480 किलोमीटर लंबाई की 709 सड़कें चिन्हित की हैं। इनका निर्माण लोक निर्माण विभाग करेगा। उल्लेखनीय है कि सत्तारूढ़ दल भाजपा के विधायकों ने सरकार से ग्रामीण क्षेत्रों में कम लंबाई की सड़कें प्राथमिकता के आधार पर बनाने की मांग की थी।

सरकार के दिशा-निर्देश पर योजनाबद्ध तरीके से सड़कों का खाका तैयार किया गया है। जिसके तहत 10 किलोमीटर से कम लंबाई की सड़कों के निर्माण के लिए नई योजना भी तैयार की जा रही हैं। इन्हें भी लोक निर्माण विभाग ही बनाएगा। ज्ञातव्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण के लिए 2018 तक मंडी बोर्ड लगभग 400 करोड़ रुपए सालाना देता था। कमलनाथ सरकार ने यह व्यवस्था बंद कर दी थी। तब से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दायरे में न आने वाली सड़कें नहीं बन पा रही थीं। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए हैं कि वो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के साथ बैठक करके नई योजना तैयार करें।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने विधानसभा के बजट सत्र के पहले विधायकों से 15-15 करोड़ रुपए तक के कामों के जो प्रस्ताव मांगे थे, उसमें भी अधिकांश ने सड़क निर्माण के कार्य को ही प्राथमिकता दी थी। इसके आधार पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की जगह सरकार ने लोक निर्माण विभाग के बजट में 1 हजार 985 करोड़ रुपए का प्रविधान कर दिया है। अभी तक 10 किलोमीटर से कम लंबाई की सड़क मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग बनाता आया है लेकिन इस बार व्यवस्था में परिवर्तन किया है। विभागीय मंत्री गोपाल भार्गव ने पिछले सप्ताह अधिकारियों के साथ बैठक में ग्रामीण इलाकों की सड़कों को प्राथमिकता से बनाने व मरम्मत करने के निर्देश दिए हैं। भोपाल जिले में नजीराबाद से नीमखेड़ी भकवाह, सुनगा से कलैया ब्राह्मण जोड़, झिरनिया से मीठी छापरी, गंगा पिपलिया से बरखेड़ा हासनजोड़, मेगरा कलां से सेमरी-1, सेमरी-2 डुगरिया बरखेड़ा याकूब नरेला दामोदर, छोटी अमरपुर से अंकिया, रातीबड़ से पुराना मंदिर बरखेड़ी बाज्याफ्त, मुडराखुर्द से सेमराखेड़ी होते हुए अनरतपुरा, बरखेड़ा नाथू से वीएनएस कॉलेज, कजलाससे ईटखेड़ी, बरखेड़ी से मेंडोरी आदि सड़कों का निर्माण किया जाएगा।

रोडमैप किया गया तैयार

जानकारी के अनुसार विभिन्न विकास कार्यों के लिए रोडमैप तैयार कर लिया गया है। सड़क निर्माण के तहत इसमें 5000 करोड़ से नेशनल, स्टेट और जिले के मुख्य मार्गों (एमडीआर) के साथ कनेक्टिंग सड़कों का निर्माण होगा। कुछ सड़कों को नए सिरे से बनाया जाना है। इसमें विधायकों द्वारा प्रस्तावित की गई सड़कों के काम भी शामिल कर दिए गए हैं। 3500 करोड़ से बड़े पुल, एलीविटेट फ्लाईओवर व पुलिया बनेंगी। ग्वालियर में 400 करोड़ का स्वर्णरेखा नदी पर बनने वाला एलीवेटेड रोड इसमें शामिल है। भोपाल के बैरागढ़ में बनने वाला एलीवेटेड फ्लाईओवर जल्द ही अनुपूरक बजट में आ जाएगा। एसएफसी की बैठक अब हर सप्ताह के शुक्रवार को पीडब्ल्यूडी प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में होगी। एक बैठक में कम से कम 50 प्रोजेक्ट पर बात होगी। सभी ईई वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए एसएफसी में शामिल होंगे। रिवाइज एस्टीमेट, सीआईआरएफ और बजट के कामों को प्राथमिकता दी जाएगी। एक करोड़ के वो काम जिनका बजट में जिक्र नहीं है, वे बिना मंजूरी के एसएफसी में नहीं रखे जाएंगे। अप्रैल, मई और जून में होने वाले कामों के लिए यह गाइडलाइन जारी की गई है।

प्रदेश सरकार इस समय मिशन मोड में है। इसकी वजह है आगामी विधानसभा चुनाव। भाजपा सरकार आगामी विधानसभा चुनाव में विकास के मुद्दे पर मैदान में उतरेगी। इसके लिए विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं को धड़ाधड़ मंजूरी दी जा रही है। इसी कड़ी में 8,500 करोड़ की सड़कें और पुल बनने का काम शुरू होने वाला है। इसके लिए आगामी दो माह में टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

विकास कार्यों को गति देने के लिए प्रदेश में पहली बार स्थाई वित्त समिति (एसएफसी) की बैठक अब हर शुक्रवार को होगी। ऐसा इसलिए हो रहा है, क्योंकि सरकार चाहती है कि जितने भी सड़कों, भवनों और पुलों के काम हैं, वह विधानसभा चुनाव से पहले न केवल शुरू हो जाएं, बल्कि आधे से ज्यादा पूरे भी हो जाएं। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई का कहना है कि वित्त विभाग पूरा सपोर्ट कर रहा है। सारे काम जल्द ही शुरू होंगे। इसमें एनएचएआई, केंद्रीय सड़क निधि और बजट में प्रस्तावित काम शामिल हैं। हर माह की खर्च लिमिट भी बढ़ा दी गई है। जून तक सभी के कार्यों के टेंडर कर दिए जाएंगे। अब हर सप्ताह एसएफसी होगी। पीडब्ल्यूडी पहली बार इस तरह से काम करेगा।

प्रदेश में विकास कार्यों को गति देने के मद्देनजर सरकार ने पीडब्ल्यूडी की 200 सड़कों, 70 से ज्यादा पुल और भवनों को मंजूरी दे दी है। इसमें केंद्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) के तहत बनने वाली 8 प्रमुख सड़कें शामिल हैं। बजट में 5000 करोड़ की सड़कों और पुल का काम शामिल है। एनएचएआई की 1500 करोड़ की 8 सड़कें बनेंगी। इनमें सीआरएफ के 2000 करोड़ के 8 और प्रोजेक्ट शामिल हैं। वहीं पीडब्ल्यूडी को हर माह खर्च के लिए वित्त विभाग अभी तक 500 करोड़ रुपए की लिमिट देता था, इसे 200 करोड़ रुपए बढ़ाकर 700 करोड़ रुपए कर दिया गया है। जल संसाधन और नर्मदा घाटी विकास विभाग का 500-500 करोड़ है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग का मासिक खर्च लिमिट 507 करोड़ रुपए ही रखा है।

● **बृजेश साहू**

अंधविश्वास के कारण बाघों का शिकार

पूरी दुनिया में वन्य जीवों का शिकार एक बड़ी समस्या है। ये एक जघन्य अपराध तो है ही, साथ ही हमारे ईको सिस्टम के लिए काफी खतरनाक है। भारत वन्य जीवों के शिकार और तस्करी का हॉट स्पॉट बनता जा रहा है। वहीं टाइगर स्टेट का खिताब पाने वाला मप्र टाइगर पोचिंग में अव्वल बनता जा रहा है। इसके पीछे अंधविश्वास बड़ी वजह माना जा रहा है। इसको देखते हुए हाईकोर्ट ने 29 जनवरी को अंधविश्वास से लड़ने के लिए टास्क फोर्स बनाने के निर्देश दिए थे, लेकिन ढाई महीने बाद उसका गठन नहीं किया जा सका।

प्रदेश में अब तक बाघ सहित अन्य वन्य प्राणियों के जितने भी शिकारी पकड़े गए हैं उनमें से अधिकांश ने बताया कि प्रदेश में अंधविश्वास की वजह से उनका शिकार किया जा रहा है। कभी रुपयों की बारिश के भ्रम में पड़कर तो कभी तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए निरीह वन्य प्राणियों की जान ली जा रही है। इन सबसे लड़ने के लिए टास्क फोर्स बनाई जानी थी जिसका काम अंधविश्वास से निपटना था, लेकिन ढाई महीने बाद भी यह फोर्स जमीन पर नहीं उतरी है। फोर्स का गठन वन विभाग व वन्यप्राणी विभाग को करना था। मप्र वन्यप्राणी विभाग के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक शुभरंजन सेन का कहना है कि हाईकोर्ट की मंशा के अनुरूप वन्यप्राणियों को अंधविश्वास से बचाने के लिए काम किया जा रहा है। जल्द ही और मजबूत व्यवस्था बनाई जाएगी। अभी टास्क फोर्स का गठन नहीं किया है। पूर्व से स्थानीय स्तर पर जन जागरूकता संबंधी कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। टास्क फोर्स का गठन भी जल्द से जल्द करने के प्रयास किए जाएंगे।

वर्तमान में वन विभाग के पास अंधविश्वास से लड़ने की कोई सशक्त व्यवस्था नहीं है। केवल टाइगर रिजर्व और सामान्य वन मंडलों में स्थानीय वनकर्मियों द्वारा वन्यप्राणी सप्ताह के अंतर्गत कार्यशाला की जाती है। अलग से कोई विशेष अभियान नहीं चलाया जा रहा है। जबकि हाईकोर्ट ने 29 जनवरी को अंधविश्वास से लड़ने के लिए टास्क फोर्स बनाने के निर्देश दिए थे। दरअसल, प्रदेश में अलीराजपुर कट्ठीवाड़ा के जंगल में दो शिक्षकों समेत आधा दर्जन लोगों ने मिलकर तेंदुए का शिकार किया था। यह घटना वर्ष 2020 में हुई थी। तेंदुए की खाल धार जिले में बेची गई थी। इस मामले की छानबीन स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स इंदौर ने करते हुए सभी शिकारियों को पकड़ा था। जब इन्हें स्थानीय कोर्ट से जमानत नहीं मिली तो जबलपुर हाईकोर्ट में अर्जी दी थी। उस समय मामले की सुनवाई न्यायाधीश सुबोध अभ्यंकर ने की थी और जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। टास्क फोर्स के गठन के सुझाव भी दिए थे। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में मंशा जताई है कि एसटीएसएफ ने जिस तरह बाघ, तेंदुए के शिकार के जुड़े गंभीर मामलों को सुलझाकर वन्यप्राणियों के अवशेषों से जुड़े व्यापार पर रोक लगाई है ठीक उसी तरह अंधविश्वास से लड़ने के लिए टास्क फोर्स बनाई जाए।

वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, प्रदेश में 6 वर्ष में 182 बाघों के शिकार के मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 35 प्रतिशत शिकार की वजह अंधविश्वास ही सामने आई है। अभी तक प्रदेश में अंधविश्वास में शिकार के जो गंभीर मामले सामने आए हैं उनमें मार्च 2022 में एक मामला सामने आया था। बालाघाट सामान्य वन मंडल की टीम ने लालबर्रा वन परिक्षेत्र से एक सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारी और अन्य आरोपितों को पकड़ा था। इनके पास से बाघ के अवशेष बरामद किए गए थे। इन्होंने अवशेष जबलपुर से खरीदे थे। इन्होंने बताया था कि इन अवशेषों के जरिए तांत्रिक अनुष्ठान कर रुपयों की बरसात करने की योजना थी। इन्होंने बाघ का शिकार कर उसके अवशेष तांत्रिक विद्या के लिए उपयोग किए थे। तब मुखबिर की सूचना पर बालाघाट सामान्य वन मंडल की टीम ने कार्रवाई की थी। वहीं अप्रैल 2019 में रायसेन जिले की बिनेका रेंज की बगासपुर बीट में शिकारियों ने बाघ का शिकार किया था। चारों पंजे, दांत और मूंछ के बाल काटकर ले गए थे। वन विभाग की टीम ने तीन शिकारियों को गिरफ्तार किया था। बिनेका रेंज में बाघों का मूवमेंट रहता है। शिकारी इसी का लाभ उठाते हुए इनका शिकार करने की जुगत में रहते हैं। इससे पहले दिसंबर 2018 में रातापानी अभयारण्य में बगासपुर गांव के पास बाघ का शिकार किया गया था। शिकारियों ने उसके पंजे काटकर घर में रख लिए थे। इस मामले में वन विभाग की टीम ने एक चरवाहे को गिरफ्तार किया था। शिकारी का कहना था कि घर में बरकत आने के लिए उसने पंजे काटकर रखे थे।

● **धर्मेंद्र सिंह कथूरिया**

बाघों की सुरक्षा के लिए करोड़ों का बजट

मप्र सरकार हर साल बाघों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन उसके बावजूद प्रदेश में बाघ दम तोड़ रहे हैं। राज्य सरकार ने 2018-19 में बाघों के संरक्षण, सुरक्षा और निगरानी में 283 करोड़ रुपए, 2019-20 में 220 करोड़ और 2020-21 और 2021-22 में क्रमशः 264 करोड़ और 128 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। राष्ट्रीय पशु की सुरक्षा में करोड़ों का बजट व्यय करने के बाद भी 2017 के बाद प्रदेश में बाघों की आईडी नहीं बनी है। आईडी के जरिए ही वन विभाग बाघों की निगरानी करता है, लेकिन 2017 के बाद प्रदेश के कई टाइगर रिजर्व में बाघों की आईडी बनाने का काम बंद हैं। हाल ही में जारी विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार अकेले बांधवगढ़ में 50 से ज्यादा बाघ बिना आईडी के विचरण कर रहे हैं।

सूखे गांव में पहुंची हरियाली

सूखे और पानी की समस्या से ग्रस्त बुंदेलखंड के एक गांव को गांव वालों ने मिलकर हरा-भरा क्षेत्र बना दिया। अब वहां के कुएं और तालाब हर समय पानी से लबालब रहते हैं। गांव वाले अच्छी खेती कर रहे हैं और वहां समृद्धि लौट रही है। उप्र के बुंदेलखंड इलाके में बांदा जिला मुख्यालय से करीब 30 किमी दूर स्थित जखनी गांव में करीब आधे दर्जन बड़े तालाब और कई छोटे तालाब हैं। कुछ तालाब तो इतने बड़े हैं कि वहां नावें चलती हैं। तालाबों में बरसात के पानी को संरक्षित किया जाता है, जिसका उपयोग सिंचाई में तो होता ही है, जलस्तर भी नहीं घटने पाता। यह सब काम करने के लिए गांव के लोगों ने 15 साल पहले जलग्राम समिति नाम की एक कमेटी बनाई थी जिसमें उमाशंकर पांडेय समेत कुल 15 सदस्य हैं। यह समिति इन सबके रख-रखाव और निर्माण पर ध्यान देती है और दूसरे लोगों को प्रेरित करने का भी काम करती है।

सूखे और जल संकट की मार झेल रहे बुंदेलखंड में यह गांव एक हरे टापू जैसा है। गांव में प्रवेश करते ही न सिर्फ हरे-भरे खेत और पेड़-पौधे दिखते हैं बल्कि कुओं और तालाबों में लबालब पानी भी भरा रहता है और कहीं भी सूखे हैंडपैंप नहीं दिखते। इस सूखे इलाके में हरा-भरा यह टापू बनाने का श्रेय गांव के ही रहने वाले उमाशंकर पांडेय को जाता है जिन्हें अब नीति आयोग ने भी अपनी जल संरक्षण समिति का सदस्य बनाया है ताकि उनके जलग्राम बनाने के प्रयासों को और विस्तार दिया जा सके।

उमाशंकर पांडेय बताते हैं, हमने यहां कुछ नहीं किया बल्कि उन चीजों को ढूंढने और बचाने की कोशिश की जो हमारे पुरखे छोड़ गए थे। जल संरक्षण और खेती के लिए हमने खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़ लगाना शुरू किया और आज उसका नतीजा सबके सामने है। दूसरी बात, इस काम में हम सभी गांव वालों ने मिलकर काम किया और आज भी कर रहे हैं। उसी का नतीजा है कि जहां बुंदेलखंड में गर्मी शुरू होते ही पानी के लिए त्राहि-त्राहि होने लगती है, हमारे तालाब और कुएं पानी से भरे रहते हैं। उमाशंकर पांडेय पिछले 25 साल से वर्षा जल संरक्षण के मकसद से खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़ अभियान चला रहे हैं और उनके इस अभियान की प्रशंसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। उनके इस अभियान में उनके गांव वाले पूरा सहयोग देते हैं और आज सभी लोग इसका पूरा लाभ भी ले रहे हैं। इनके प्रयासों का नतीजा यह है कि पूरे बुंदेलखंड में जल स्तर भले ही 200-250 फुट नीचे चला गया हो लेकिन यहां के कुओं में जलस्तर इतना ऊपर है कि हाथ में बाल्टी लेकर भी कोई पानी निकाल सकता है। गांव के कई तालाब झील का आकार ले चुके हैं और सभी तालाबों में सालभर पानी भरा रहता है।

उमाशंकर पांडेय बताते हैं कि 15-20 साल पहले उनके गांव की भी स्थिति वैसी ही थी जैसी कि बुंदेलखंड के दूसरे गांवों की है, लेकिन गांव वालों के सम्मिलित प्रयास और सोच ने सबकुछ बदलकर रख दिया। वो कहते हैं, हमारा गांव कभी गरीबी, भुखमरी, अपराध और तमाम विवादों के कारण पूरे जिले में चर्चित था। आज वर्षा जल बूंदों को रोकने के कारण गांव का जलस्तर ही नहीं बढ़ा बल्कि गांव में समृद्धि आई और लोगों के पास पैसा आया।

इस सूखे इलाके में हम लोग न सिर्फ धान की खेती करते हैं बल्कि दाल, तिलहन और सब्जियां भी उगाते हैं। तालाबों में मछलियां पाली जाती हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि वर्षों से हमारे गांव में अपराध नहीं हुआ है, शिक्षा के मंदिर खुल गए हैं और हिंदू-मुस्लिम भाईचारा बनाए हुए सभी अपने काम में लगे हैं। इस छोटे से गांव में 50 से अधिक ट्रैक्टर हैं, हार्वेस्टर मशीन है, आधुनिक और परंपरागत दोनों तरह के कृषि यंत्र हैं। इन सबकी बदौलत बेहतरीन किस्म का हम बासमती चावल पैदा कर रहे हैं जिसकी मांग न सिर्फ बांदा में है बल्कि इसके बाहर भी है। गांव के ही रहने वाले रामविलास कुशवाहा बताते हैं कि वो हर साल करीब 7-8 लाख रुपए का बासमती चावल बेचते हैं। धान के अलावा कुशवाहा बैंगन, लौकी, तुरई और करेले जैसी सब्जियां भी उगाते हैं, वो कहते हैं, हम लोग इतनी सब्जी उगाते हैं कि जिलेभर में हमारी सब्जी मशहूर है। हमारे गांव का परवल तो बांदा के बाहर भी बिकता है। हम लोग यह खेती इसलिए कर पा रहे हैं कि यहां पानी का संकट नहीं है। हमने पानी की एक-एक बूंद को बचाने का हुनर सीखा है और आज भी वही काम कर रहे हैं। पानी और अपनी मेहनत की बदौलत आज हमें अपने गांव में ही अच्छा काम मिला हुआ है और अच्छी आमदनी हो रही है।

उमाशंकर पांडेय बताते हैं कि जल संरक्षण की प्रेरणा उन्हें गांधीवादी विचारक और प्रसिद्ध पर्यावरणविद अनुपम मिश्र से मिली। वो कहते हैं कि इसके लिए उन्होंने एक सूत्र का पालन किया कि पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं करनी है। पांडेय कहते हैं, दरअसल इसके लिए हमारे पूर्वजों ने जो समाधान ढूंढा था, हमने उसी को अपनाया। हम लोगों ने एक संगठन बनाकर अपने गांव के पुराने तालाबों और कुओं के जीर्णोद्धार का बीड़ा उठाया। कुओं और तालाबों की सफाई की, वहां पड़े अतिक्रमण को खत्म किया, खेतों की मेड़बंदी की और घरों की नालियों के पानी को भी खेतों में पहुंचाया। हमने किसी भी तालाब के किनारे को पक्का नहीं किया बल्कि वो जैसा था, वैसा ही रहने दिया है। करीब दो दशक की मेहनत का नतीजा आज सबके सामने है।

● **सिद्धार्थ पांडे**

पानी बनाया नहीं, सिर्फ बचाया जा सकता है

उमाशंकर पांडेय कहते हैं कि पानी बनाया नहीं जा सकता बल्कि इसे केवल बचाया जा सकता है। वो कहते हैं कि उन लोगों ने यह सब सिर्फ अपने प्रयास से किया, कोई सरकारी मदद नहीं ली। बाद में जखनी गांव की इस हरियाली को अन्य लोगों को दिखाने और प्रेरणा लेने के मकसद से बांदा जिला प्रशासन ने यहां के मेड़बंदी मॉडल को जल संरक्षण के लिए 470 ग्राम पंचायतों में लागू किया। इसके अलावा, उप्र के कृषि उत्पादन आयुक्त ने पूरे प्रदेश के लिए उपयुक्त माना और भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने इसे पूरे देश के लिए उपयुक्त। मंत्रालय ने देश के हर जिले में दो गांवों को जखनी की तरह जलग्राम के लिए चुना है। नीति आयोग ने भी इस जल संरक्षण विधि को मान्यता दी और इस आधार पर इसे आदर्श गांव माना है।

मप्र में ओबीसी आरक्षण की फांस में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव इस कदर फंस गए हैं कि इससे पार पाना सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए मप्र सरकार को बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने का निर्देश दिया है। जिसके खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगाया है। दरअसल, मप्र ही नहीं देशभर में आरक्षण राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बन गया है।

● राजेंद्र आगाल

मप्र सहित कई राज्यों में ओबीसी आरक्षण की वजह से लंबित स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को **लंबित निकाय चुनाव** कराने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद कई राज्यों खासतौर से मप्र में ओबीसी आरक्षण के बिना निकाय चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश में राज्य चुनाव आयोग को दो हफ्ते के अंदर अधिसूचना जारी करने को कहा है। कोर्ट ने ये भी कहा कि ओबीसी आरक्षण की शर्तों को पूरा किए बगैर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मप्र सरकार ने कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगाया है, जिस पर 17 मई को सुनवाई होनी है। सवाल यह उठता है कि आखिर क्या वजह है कि आजादी के 75 साल के बाद भी हमारा देश आरक्षण की **फांस** में फंसा हुआ है। दरअसल, सरकारों ने आरक्षण को केवल वोट का आधार बनाया है, विकास का नहीं।

62 साल बाद भी बेहाल

भारत में समानता के अधिकार के तहत 1960 में पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को 10 साल के लिए आरक्षण दिया गया था, ताकि इस दौरान ये जातियां अन्य ऊंची एवं संपन्न जातियों के लोगों के बराबर का दर्जा प्राप्त कर सके। आरक्षण का दायरा दिन पर दिन बढ़ता गया, लेकिन जरूरतमंदों को इसका फायदा नहीं मिला। आज 62 साल बाद आरक्षण एक ऐसा नासूर बन गया है कि इससे देश कब मुक्त होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। आज जब भारत तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है तो उसे फिर से पीछे धकेलने की साजिश है ये। समाज को दो हिस्सों मे बांटने की साजिश है। आजादी के 6 दशक बाद भी यदि हम आरक्षण की राजनीति करते रहे तो लानत है हम पर। निश्चित रूप से जब डॉ. अंबेडकर ने ही यह कहा कि आरक्षण वैसाखी नहीं है तो फिर आज 10-10 साल के अंतराल पर समीक्षा होने के बजाय पुन: आरक्षण की सीमा को आगे बढ़ा दिया जाता है। आज देश में एक व्यक्ति एक संविधान क्यों नहीं लागू होता? आरक्षण से दलित वर्ग को आज तक कितना लाभ हुआ? हम हर जगह **खुली प्रतियोगिता** की बात करते है, तो फिर सभी नागरिकों को समान प्रतियोगिता का अवसर क्यों नहीं देते? कब तक हम वर्ग विशेष को आरक्षण प्लेट में रखकर देते रहेंगे? सामाजिक न्याय के नाम पर हम कब तक योग्य प्रतिभा का गला घोंटते रहेंगे? कब तक ये वोट की गंदी राजनीति चलती रहेगी? आरक्षण के नाम पर लगभग सभी पार्टियां एकमत हैं। और अब तो प्रमोशन में रिजर्वेशन के लिए भी संसद में बिल पास कराकर लागू कराए जाने की साजिश चल रही है। जबकि सुप्रीम कोर्ट इस प्रमोशन में **रिजर्वेशन की व्यवस्था** को पहले खारिज कर चुका था। मगर राजनीतिक दल विशेषकर बसपा की सुप्रीमो मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही संसद में बदलने के लिए राजनीतिक हथकंडे अपनाए जिसका समर्थन सपा को छोड़कर सभी दलों ने किया था। राजनीतिक दल कभी नहीं चाहते हैं कि आरक्षण की व्यवस्था खत्म हो क्योंकि यही उनका सबसे बड़ा वोट बैंक है।

आरक्षण के लाभ का हकदार होने के बावजूद भारत में सफाई पेशा समुदाय आज भी श्रम के बदले रोटी और जूठन तथा रोजगार के नाम पर मल-मूत्र ढोने और गटर में जान देता है। तो आखिर आरक्षण का लाभ किस दिशा में जा रहा है? भारत सरकार ने मैला ढोने के काम को नागरिक समाज में एक अपराध और अमानवीय प्रथा करार देते हुए इसके खात्मे के लिए 1993 में एक कानून पारित किया था और इसे भी अत्याचार और शोषण की श्रेणी में रखा था, बावजूद इसके आज भी हजारों दलित व दलित महिलाएं मैला ढोने जैसे अमानवीय कार्य करने को मजबूर हैं। डॉ. अंबेडकर के नाम पर दलितों की राजनीति करने वाले तथाकथित अंबेडकरवादियों ने इनके हक और अधिकारों की आवाज संसद या सड़क पर नहीं उठाई। सामाजिक न्याय का पैमाना सफाई पेशा जातियां ही हैं। मैला **ढोना और गटर** में उतरना, मानवता की सारी हदें पार कर जाता है। संसद में सामाजिक न्याय के पैरोकार और संविधान की दुहाई देने वालों ने इन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी है। सत्ता की लालसा में अंधे और दलित बहुजन ब्राह्मणवाद और मनुवाद कोसते जरूर हैं, लेकिन इन्हीं के सहयोग और आशीर्वाद से सत्ता-सुख भोगने, मंत्री, मुख्यमंत्री बनने और सत्ता के लिए दलितों के अधिकारों से खिलवाड़ करने से भी गुरेज नहीं करते। सत्ता-सुख के लिए विचारधारा इनके लिए कोई मायने नहीं रखती। जिन महापुरुषों के चित्र इनके बैनर और पोस्टरों पर दिखाई देते हैं यह एक छलावा मात्र है। भारत में जाति आधारित भेदभाव जीवित है तो इसके लिए जिम्मेदार तथाकथित दलित नेता और राजनीतिक आरक्षण पर **काबिज जातियां** ही हैं। जिन्होंने राजनीतिक सत्ता के लिए नागरिक अधिकारों को बलि चढ़ा दिया। इन्हीं के नकारापन की बदौलत 21वीं सदी में और आजादी के 70 साल बाद भी रोजगार के नाम पर दलित मल-मूत्र ढोने और गटर में मरने के लिए विवश हैं।

52 साल बाद भी आरक्षित वर्ग बेहाल

भारत सरकार द्वारा भारतीय संविधान में निहित समता के अधिकार (अनु. 14-18) के तहत पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को आरक्षण देने का सिर्फ एक उद्देश्य था और वह यह कि इनको अन्य ऊंची एवं संपन्न जातियों के लोगों के बराबर का दर्जा दिया जा सके। अन्य सभी उच्च जातियों एवं वर्गों के साथ-साथ इन पिछड़े एवं शोषित लोगों का भी इस देश के विकास में बराबर का योगदान हो। आरक्षण की व्यवस्था शुरू में 1960 में शुरू की गई और डॉ. अंबेडकर ने स्वयं कहा था कि- हर 10 साल में यह समीक्षा हो जिनको आरक्षण दिया जा रहा है क्या उनकी स्थिति में कुछ सुधार हुआ या नहीं? उन्होंने यह भी स्पष्ट रूप में कहा कि यदि आरक्षण से किसी वर्ग का विकास हो जाता है तो उसके आगे की पीढ़ी को इस व्यवस्था का लाभ नहीं देना चाहिए, क्योंकि आरक्षण का मतलब वैसाखी नहीं है जिसके सहारे आजीवन जिंदगी जिया जाए, यह तो मात्र एक आधार है विकसित होने का। संविधान द्वारा दलितों को लोकसभा, विधानसभाओं और स्थानीय निकायों में प्रदत्त आरक्षण का उपयोग न्यायसंगत तरीके से न किए जाने के कारण दलितों में ही असंतोष पैदा हो रहा है। अनुसूचित जातियों/जनजातियों की एक लंबी सूची है। बावजूद इसके कुछ चुनिंदा दलित जातियां और उनके परिवार ही पूरे राजनीतिक आरक्षण पर लंबे समय से काबिज हैं। इस कारण राजनीतिक आरक्षण का लाभ सभी अनुसूचित जातियों/जनजातियों को समान रूप से नहीं मिल पाया है। इसी कारण कई दलित जातियां राजनीति के हाशिए पर चली गई हैं। इसलिए समय आ चला है कि राजनीतिक आरक्षण का न्यायोचित लाभ अनुसूचित जातियों/जनजातियों को समान रूप से मुहैया कराने के लिए कास्ट रोटेशन पॉलिसी अर्थात् जाति फेर-बदल नीति की आवश्यकता है।

सियासी घाटे-फायदे का गणित शुरू

प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के बिना पंचायत व नगरीय निकाय चुनाव कराए जाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब राजनीतिक दल घाटे-फायदे के गणित में उलझे हुए हैं। कोर्ट के इस आदेश से भाजपा को पिछड़ा वर्ग के नाराज

होने की चिंता सता रही है तो दूसरी ओर कांग्रेस भाजपा के सिर पर ठीकरा फोड़कर लाभ उठाने की फिराक में है। कांग्रेसियों का मानना है इस आदेश का लाभ कांग्रेस को न केवल पंचायत व निकाय चुनावों में मिलेगा, बल्कि विधानसभा चुनाव में भी फायदा होगा। वहीं भाजपा का शीर्ष नेतृत्व भी आरक्षण के आदेश को लेकर तत्कालीन सरकार को जिम्मेदार मान रहा है।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने प्रदेश में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए जाने के आधार संबंधी रिपोर्ट पेश की थी। इसमें ओबीसी को 35 प्रतिशत आरक्षण देने की अनुशंसा की गई है। वहीं सरकार की ओर से कहा गया कि हम न्यायालय के निर्देशानुसार चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। प्रदेश में त्रिस्तरीय (ग्राम, जनपद और जिला) पंचायत और नगरीय निकाय (नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम) में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए कोर्ट ने अध्ययन कराने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद राज्य सरकार ने राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग गठित किया था, जिसने मतदाता सूची का परीक्षण कराने के बाद दावा किया कि प्रदेश में 48 प्रतिशत मतदाता ओबीसी हैं। इस आधार पर रिपोर्ट में त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव में ओबीसी को 35 प्रतिशत आरक्षण देने की अनुशंसा करते हुए सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई।

मप्र में नगरीय निकायों और पंचायतों में पिछड़े वर्ग (ओबीसी) को ज्यादा आरक्षण को लेकर चली राजनीति और कानूनी दांव पेंच का लुब्बो लुआब यह है कि प्रदेश में अब ये चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के होंगे, लेकिन चुनाव का मुख्य मुद्दा ओबीसी आरक्षण ही होगा। मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी भाजपा और कांग्रेस ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण न दे पाने के लिए एक-दूसरे को कोसेंगे। फैसला जनता करेगी कि उसके लिए असली मुद्दा क्या है? ओबीसी आरक्षण, महंगाई, बेरोजगारी या स्थानीय विकास? हालांकि ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में कानूनी मात खाने के बाद शिवराज सरकार ने इस मुद्दे को राज्य में ओबीसी को न्याय दिलाने के संकल्प में तब्दील करने का ऐलान किया है तो विपक्षी कांग्रेस इसे राज्य में ओबीसी हितों की उपेक्षा के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है।

गौरतलब है कि मप्र में कुल 378 नगरीय निकाय हैं, जिनमें 16 नगर निगम, 98 नगर पालिकाएं तथा 264 ग्राम पंचायतें हैं। इसी तरह कुल 23 हजार 59 पंचायतें हैं, जिनमें 51 जिला पंचायतें, 313 जनपद पंचायतें और 22 हजार 525 ग्राम पंचायतें हैं। राज्य में पिछले नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों में ओबीसी को 14 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था। लेकिन बीच में सवा साल सत्ता में रही कांग्रेस ने इसे बढ़ाकर 27 फीसदी करने का दांव चला ताकि ओबीसी वोट को कांग्रेस की तरफ खींचा जा सके। यही नहीं कांग्रेस ने नगरीय निकायों और पंचायतों का नए सिरे से परिसीमन करने की चाल चली और नगरीय निकायों में महापौर-अध्यक्ष के चुनाव की **अप्रत्यक्ष प्रणाली लागू** की। इन्हीं बदलावों के चलते कांग्रेस ने नियमानुसार 2019 में होने वाले नगरीय निकाय और पंचायतों के चुनाव टाले और उसके बाद तो उसकी सरकार ही चली गई।

चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे या नहीं फैसला 17 को

मप्र में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे या नहीं, यह 17 मई को तय होगा। शिवराज सरकार सुप्रीम कोर्ट में राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की वार्डवार रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुकी है। साथ ही पुनर्विचार आवेदन में 2022 के परिसीमन से चुनाव कराने की अनुमति मांगी है। इस पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को राज्य निर्वाचन आयोग को दो सप्ताह के भीतर चुनाव की अधिसूचना जारी करने के आदेश दिए हैं। आयोग अपने स्तर पर तैयारी कर चुका है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग से उन निकायों की जानकारी मांगी गई है, जहां कार्यकाल पूरा हो चुका है और चुनाव कराए जाने हैं। वहीं, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से नए परिसीमन के आधार पर आरक्षण करने के लिए कहा गया है। दोनों विभागों ने अपने स्तर पर तैयारियां भी कर ली हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई का इंतजार किया जा रहा है। दरअसल, सरकार ने चुनाव कराने के लिए आरक्षण सहित अन्य प्रक्रिया करने के लिए दो-तीन सप्ताह का समय मांगा है। सूत्रों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट यदि राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट को मान्य कर लेता है तो फिर ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराए जा सकते हैं। आयोग ने सरकार से ओबसी को 35 प्रतिशत आरक्षण देने की अनुशंसा की है। आयोग का दावा है कि प्रदेश के कुल मतदाताओं में 48 प्रतिशत ओबीसी हैं।

कांग्रेस सरकार व ओबीसी आरक्षण

खास बात यह रही कि कमलनाथ सरकार ने ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण की घोषणा तो कर दी, लेकिन गजट अधिसूचना जारी नहीं की। यानी उस घोषणा का कानूनी दृष्टि से कोई मतलब नहीं था। उसके बाद कोविड में दो साल निकले। जबकि संविधान के 73 व 74वें संशोधन के मुताबिक राज्यों को हर पांच साल में नगरीय निकायों और पंचायतों के चुनाव कराना जरूरी है। इन्हें अधिकतम 6 माह तक टाला जा सकता है। लेकिन राजनीतिक कारणों से मप्र में ये चुनाव करीब ढाई साल टल चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद ये बहुप्रतीक्षित चुनाव जून में होने जा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह ने कहा कि चुनाव दो चरणों में होंगे। इनकी अधिसूचना 24 मई तक जारी कर दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से और पंचायत चुनाव मतपत्र पद्धति से होंगे। चुनाव प्रक्रिया 30 जून तक संपन्न कर ली जाएगी।

इस बीच ओबीसी आरक्षण के सवाल को लेकर कोर्ट में मात खा चुकी मप्र सरकार जनता

को समझाने के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। उसने सर्वोच्च अदालत में सुधारात्मक याचिका दायर की है। हालांकि इससे कोई खास फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं लगता। कानूनी लड़ाई के बरक्स कांग्रेस राज्य में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण न दिला पाने के लिए शिवराज सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है तो जवाब में भाजपा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की तर्ज पर विपक्ष में बैठी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है।

चुनाव पर कितना होगा असर?

बहरहाल, मप्र में नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण न दे पाने का मुद्दा चुनाव में कितना असर डालेगा, यह देखने की बात है। इस मुद्दे का चुनावी लाभ लेने की नीयत से कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि वो इन चुनावों में 27 फीसदी टिकट पिछड़े वर्ग को देगी। जवाब में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि भाजपा कांग्रेस से ज्यादा टिकट ओबीसी को देगी। ध्यान रहे कि सुप्रीम कोर्ट के ताजा निर्णय के तहत ओबीसी के लिए अलग से कोई आरक्षण न होने से पिछड़ी जातियों के प्रत्याशियों को टिकट भी सामान्य सीट पर ही देने होंगे। इससे नया घमासान मचने की आशंका है। वहीं प्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण न दे पाने के मुद्दे पर कांग्रेस अपनी जीत देख रही है। हालांकि भाजपा इस स्थिति से निराश नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इन चुनावों में 'महाविजय का संकल्प' दिलाते हुए कहा कि हम ओबीसी व अन्य सभी वर्गों को न्याय देकर आगे बढ़ेंगे।

उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस कोर्ट की शरण में इसलिए गई, क्योंकि उसे चुनाव में अपनी पराजय का डर था। उसी के 'महापाप' के कारण राज्य में ओबीसी आरक्षण रुका। उन्होंने तो यह भी कहा कि ये भाजपा है, जिसने मप्र को 3-3 मुख्यमंत्री ओबीसी से दिए। खुद शिवराज भी ओबीसी हैं। सवाल यह कि कौन सी पार्टी ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण न दे पाने का राजनीतिक फायदा उठा पाएगी? दूसरा, यह कि राज्य में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण का औचित्यपूर्ण आधार क्या है? पहले सवाल का जवाब यह हो सकता है कि संगठनात्मक दृष्टि से भाजपा कांग्रेस की तुलना में बहुत ज्यादा मजबूत और फोकस्ड है। उसका प्रचार और दुष्प्रचार तंत्र भी कांग्रेस के मुकाबले बहुत बड़ा है। वो पूरी कोशिश करेगी कि ओबीसी मुद्दे पर कोर्ट में सरकार की नाकामी का ठीकरा वह कांग्रेस पर ही फोड़े। यानी यह संदेश देने की कोशिश होगी कि भाजपा तो पिछड़ों को 27 फीसदी आरक्षण देने जा रही थी, लेकिन कांग्रेस ने ही फच्चर मार दिया। इसकी तैयारी हो चुकी है। उधर कांग्रेस की पूरी कोशिश रहेगी कि 27 फीसदी आरक्षण न दे पाने के लिए वह भाजपा को कोसे और यह संदेश देने की कोशिश करे कि पिछड़ों की असली हितैषी वही है, भले ही उसने सत्ता में रहते हुए एक भी ओबीसी मुख्यमंत्री न बनाया हो।

यहां 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण में राजनीति के साथ-साथ सरकारी नौकरियों में आरक्षण का मसला भी शामिल है। कोर्ट द्वारा राज्य में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण अमान्य करने का असर सरकारी नौकरियों पर भी पड़ेगा। राज्य में अभी शासकीय सेवाओं में पिछड़ों को 14 फीसदी आरक्षण मिला हुआ है, जिसे बढ़ाकर 27 फीसदी किया जाना है। लेकिन सवाल यह है कि मप्र में पिछड़ों की आबादी वास्तव में है कितनी? और इस 27 फीसदी आरक्षण का आधार क्या है? ऐसा करने पर कुल आरक्षण 63 फीसदी हो जाएगा, उसका क्या?

आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं कई राज्य

देश के आधा दर्जन राज्य ऐसे हैं, जो 50 फीसदी आरक्षण का दायरा बढ़ाने के पक्ष में खड़े हैं। इनमें मप्र, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, झारखंड और कर्नाटक जैसे राज्य शामिल हैं, जो आरक्षण के दायरे को बढ़ाकर अपने राजनीतिक और सामाजिक समीकरण को मजबूत करना चाहते हैं। दरअसल, साल 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए जाति-आधारित आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 फीसदी तय कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले के बाद कानून ही बन गया कि 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इसके चलते राजस्थान में गुर्जर, हरियाणा में जाट, महाराष्ट्र में मराठा, गुजरात में पटेल जब भी आरक्षण मांगते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आड़े आ जाता है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से आगे बढ़ाने के पक्ष में है। इसके लिए बाकायदा गहलोत सरकार सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर अपना पक्ष मजबूत से रखेगी, जिसके लिए पिछले दिनों कैबिनेट में इस पर चर्चा भी हुई। राजस्थान सरकार इस बात से सहमत है कि आरक्षण की 50 फीसदी सीमा पर पुनर्विचार करना चाहिए और उसे बढ़ाया जाना चाहिए। तमिलनाडु में काफी पहले से ही आरक्षण का दायरा 50 फीसदी से कहीं ज्यादा है। यहां पर रिजर्वेशन संबंधित कानून की धारा-4 के तहत 30 फीसदी रिजर्वेशन पिछड़ा वर्ग, 20 फीसदी अति पिछड़ा वर्ग, 18 फीसदी एससी और एक फीसदी एसटी के लिए रिजर्व किया गया है। इस तरह से तमिलनाडु में कुल 69 फीसदी रिजर्वेशन दिया जा रहा है। तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट 69 फीसदी रिजर्वेशन की बात करता है, जिसे लेकर कोर्ट में याचिका भी पड़ी है। याचिका में कहा गया है कि इंदिरा साहनी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बेंच ने कहा था कि रिजर्वेशन के लिए 50 फीसदी की सीमा है। झारखंड की हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार भी राज्य में 50 फीसदी से अधिक आरक्षण बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखेगी। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से आरक्षण की सीमा बढ़ाने पर उनका पक्ष मांगा है। इसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा सदन में आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से अधिक बढ़ाने की बात कही है। इसके पीछे असल वजह यह है कि झारखंड में काफी लंबे समय से ओबीसी समुदाय 14 फीसदी आरक्षण को बढ़ाकर 27 फीसदी करने की मांग कर रहा है, जिसे लेकर हेमंत सोरेन चुनाव में वादा भी कर चुके हैं।

दरअसल राज्य में ओबीसी की आबादी वास्तव में कितनी है, इसका कोई प्रामाणिक आंकड़ा न तो शिवराज सरकार के पास है और न ही कमलनाथ सरकार के पास था।

सुप्रीम कोर्ट के साफ दिशा निर्देश हैं कि पहले पिछड़ों की वास्तविक आबादी के प्रामाणिक आंकड़े सरकार पेश करे, उसी के बाद तय होगा कि ओबीसी वास्तव में कितने फीसदी आरक्षण के हकदार हैं। शिवराज सरकार ने जल्दबाजी में कोर्ट में जो आंकड़े प्रस्तुत किए, उसमे राज्य में ओबीसी आबादी 48 फीसदी होने, तदानुसार राज्य में ओबीसी को 35 प्रतिशत आरक्षण देने का दावा किया गया। ये आंकड़े भी किन प्रामाणिक स्रोतों से जुटाए गए, स्पष्ट नहीं है। उधर, कांग्रेस का मानना है कि मप्र में ओबीसी कुल आबादी का करीब 52 फीसदी हैं। कोर्ट ने कहा था कि ओबीसी के आंकड़े ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले से जुटाए जाएं, लेकिन वो एक जटिल, गहरी और लंबी प्रक्रिया है। राज्य सरकार वादे के मुताबिक यह प्रक्रिया भी समय पर पूरी नहीं कर पाई। इसके अलावा आरक्षण के इस फॉर्मूले में बड़ा पेंच सर्वोच्च न्यायालय का वो निर्णय है, जिसमें कहा गया है कि (कतिपय अपवादों को छोड़कर) देश में कुल आरक्षण 50 फीसदी से अधिक नहीं हो सकता।

ओबीसी का कोटा पूरा

मप्र में ओबीसी को पहले से दिए गए 14 फीसदी आरक्षण से यह कोटा पूरा हो चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि चूंकि सरकार के पास ओबीसी आबादी के प्रामाणिक आंकड़े नहीं हैं, इसलिए नगरीय निकायों और पंचायतों के ताजा चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के ही होंगे। यानी चुनाव में आरक्षण केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग को ही मिलेगा, जो कुल मिलाकर 36 फीसदी होता है। अब चुनाव नतीजे जो भी हों, लेकिन इन नतीजों से राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के संकेत जरूर मिलेंगे, यह तय है। सरकार ने 49 प्रतिशत आबादी बताते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मप्र में 35 प्रतिशत आरक्षण मांगा था, लेकिन रिपोर्ट तैयार करने में लापरवाही की गई। निकायवार रिपोर्ट ही नहीं बनाई। अंतत: सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए अधूरी रिपोर्ट खारिज कर दी। वैसे तो इसका सीधा असर सरकार, लोकल चुनाव और राजनीतिक दलों पर पड़ेगा, लेकिन इस फैसले के दो साइड इफेक्ट भी हैं। इसमें सरकारी नौकरियों में सामान्य वर्ग को फिलहाल राहत मिलते दिख रही है कि वहां भी 27 प्रतिशत आरक्षण लागू होगा या नहीं, यह तय नहीं है। लेकिन, राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले सामान्य वर्ग के लोगों को नुकसान होगा क्योंकि पार्टियां तो अब सामान्य वर्ग की सीटों पर भी ओबीसी चेहरे उतारने के मूड में है। पहले यह 14 प्रतिशत ही होता था, अब तो 27 प्रतिशत सीटों पर ओबीसी चेहरे उतारना ना चाहते हुए भी मजबूरी बन सकती है।

मंत्रालय सूत्रों की मानें तो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने ट्रिपल टेस्ट के लिए तय प्रक्रियाओं को पूरा किए बिना अधूरी रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी। इसकी वजह यह है कि सरकार कोर्ट में लिखित में कह चुकी थी कि 30 मई तक ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, लिहाजा इसके बाद चुनाव कराए जा सकते हैं, लेकिन सरकार ने ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट में यह जरूर कहा कि इस वर्ग की प्रदेश में आबादी 49 प्रतिशत है। इसलिए 35 प्रतिशत सीटें इस वर्ग के लिए आरक्षित की जाएं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस रिपोर्ट को ही खारिज कर दिया। जानकार कहते हैं कि मप्र सरकार ने ओबीसी वर्ग को चुनाव में आरक्षण देने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इसके लिए संवैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया। जानकारी के मुताबिक तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 69 प्रतिशत आरक्षण लागू है। इसके लिए 1990 की तत्कालीन जयललिता सरकार ने एक प्रस्ताव संसद में पेश किया था। उस समय राजीव गांधी सरकार ने इसे पारित कर मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेजा था। इसके बाद संवैधानिक मान्यता मिली। जिसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है।

मप्र में 3 साल से अटके नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के ही कराने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि आरक्षण के लिए तय शर्तों को पूरा किए बिना ओबीसी को आरक्षण नहीं मिल सकता। दरअसल, 1994 से पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू है। 2014 का आखिरी पंचायत चुनाव भी ओबीसी आरक्षण के साथ ही हुआ था। 2014 तक प्रदेश की पंचायतों में अनुसूचित जाति की 16 प्रतिशत सीटें, अनुसूचित जनजाति की 20 प्रतिशत और ओबीसी के लिए 14 प्रतिशत सीटें रिजर्व थीं। लेकिन, पेंच तब फंस गया, जब 2019 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने रोटेशन और परिसीमन की कार्रवाई की। इसमें आरक्षण का पेंच इस कदर फंस गया कि अब इससे निकलना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव कराने का फैसला देकर राजनीतिक पार्टियों को बैकफुट पर ला दिया है।

जातीय आधार पर आरक्षण देने से जरूरतमंदों का हक मारा जा रहा है

हमारे देश में आरक्षण जन्म के आधार पर दिए जा रहे हैं, जरूरत के आधार पर नहीं। इसकी वजह से सरकार में अयोग्यता और पक्षपात को प्रश्रय मिलता है और करोड़ों वंचित लोग अपने नारकीय जीवन से उबर नहीं पाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर जातीय आरक्षण के औचित्य पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया है। 5 जजों की इस पीठ ने अपनी ही अदालत द्वारा 2004 में दिए गए उस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है, जिसमें कहा गया था कि आरक्षण के अंदर (किसी खास समूह को) आरक्षण देना अनुचित है यानी आरक्षण सबको एकसाथ दिया जाए। उसमें किसी भी जाति को कम या किसी को ज्यादा न दिया जाए। सभी आरक्षित समान हैं, यह सिद्धांत अभी तक चला आ रहा है। ताजा फैसले में भी वह अभी तक रद्द नहीं हुआ है, क्योंकि उसका समर्थन 5 जजों की बेंच ने किया था। अब यदि 7 जजों की बेंच उसे रद्द करेगी तो ही आरक्षण की नई व्यवस्था को सरकार लागू करेगी। यदि यह व्यवस्था लागू हो गई तो पिछड़ों और अनुसूचितों में जो जातियां अधिक वंचित, अधिक उपेक्षित, अधिक गरीब हैं, उन्हें आरक्षण में प्राथमिकता मिलेगी। लेकिन कई लोगों का मानना है कि सरकारी नौकरियों में से जातीय आरक्षण पूरी तरह से खत्म किया जाना चाहिए।

क्या पीके बन पाएंगे केजरीवाल?

बीते दिनों कांग्रेस में शामिल होने को लेकर चर्चाओं में रहे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के एक ट्वीट ने हलचल मचा दी है। दरअसल, प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर संकेत दिए हैं कि वह अपनी नई पार्टी बना सकते हैं। और, इसकी शुरुआत बिहार से होगी। वैसे, प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर लिखा है कि लोकतंत्र में एक सार्थक भागीदार बनने और और जन-समर्थक नीति को आकर देने की उनकी खोज के 10 सालों का सफर उतार-चढ़ाव वाला रहा है। आज जब इस यात्रा के पन्ने पलटते हैं, तो ऐसा लगता है कि अब असली मालिकों यानी जनता के बीच जाने का समय आ गया है। जिससे उनकी समस्याओं को बेहतर तरीके से समझने और जन सुराज यानी जनता के सुशासन को बेहतर ढंग से समझा जा सकेगा।

प्रशांत किशोर की कही गई बातों पर गौर किया जाए, तो ये काफी हद तक आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की याद दिलाता है। लोकतंत्र में सार्थक भागीदारी और जन-समर्थक नीति जैसे शब्द अन्ना आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी की बदलाव की राजनीति से काफी मिलते-जुलते नजर आते हैं। आम आदमी पार्टी का स्वराज का नारा प्रशांत किशोर ने जन सुराज के कलेवर में लपेटकर लोगों के सामने पेश किया है। आम आदमी पार्टी ने इसी सपने के सहारे दिल्ली में लगातार तीन बार सरकार बनाई। जनता के मन में फ्री बिजली-फ्री पानी जैसी योजनाओं के सहारे आम आदमी पार्टी ने अपनी पैठ को गहराई दी। अब प्रशांत किशोर भी ऐसी ही बातें कर रहे हैं।

अन्ना आंदोलन से पहले अरविंद केजरीवाल लंबे समय तक केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ सिविल सोसाइटीज के जरिए अधिकारों की लड़ाई लड़ते नजर आए थे। आसान शब्दों में कहा जाए, तो अरविंद केजरीवाल राजनीति में आने से पहले आंदोलन और धरनों के जरिये सियासत के दांव-पेंच सीख रहे थे। 2013 के अन्ना आंदोलन ने अरविंद केजरीवाल को एक मंच उपलब्ध कराया। और, उन्होंने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया। पहली बार दिल्ली में अल्पमत सरकार बनाने के बाद इस्तीफा देकर लोकसभा चुनाव में सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देकर अरविंद केजरीवाल ने खुद को स्थापित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया था। जिसका नतीजा ये है कि दिल्ली में लगातार तीन बार सरकार बनाने के साथ ही पंजाब में भी आम आदमी पार्टी का शासन हो चुका है। प्रशांत किशोर का हालिया ऐलान भी काफी हद कर ऐसा ही है। 2012 से लेकर अब तक आधा दर्जन मुख्यमंत्री बना चुके पीके चुनावी रणनीतियां बनाते हुए राजनीतिक दांव-पेंचों में पारंगत हो चुके हैं। और, अब राजनीति में एंट्री करने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आते हैं।

इससे इतर अरविंद केजरीवाल की बात करें, तो बदलाव की राजनीति का सपना दिखाने वाला आम आदमी पार्टी का ये नेता अब पूरी तरह से सियासत में रंग चुका है। बीते कुछ सालों में क्षेत्र, जाति, धर्म जैसे मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल ने खुद को राजनीतिक रूप से करेक्ट करने की कोशिश की है। लेकिन, अपने पिछले बयानों को लेकर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल हमेशा अंतर्विरोधों से घिरे रहते हैं। वहीं, प्रशांत किशोर की पार्टी की बात की जाए, तो अभी तक उनकी ओर से किसी भी तरह का विवादास्पद बयान नहीं दिया गया है। जो भविष्य में पीके या उनकी पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। प्रशांत किशोर की पार्टी को अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का अपडेटेड वर्जन कहना ज्यादा सही होगा। जो नई तरह की राजनीति का सपना दिखा रही है। और, उसके अतीत में ऐसे कोई पक्ष भी नहीं है, जो उसकी राजनीतिक करेक्टनेस पर सवाल खड़े करें, जबकि अरविंद केजरीवाल अब तक धारा 370 से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक पर अपने दिए गए बयानों से जूझते हुए खुद को गैर-हिंदू विरोधी और गैर-मुस्लिम समर्थक साबित करने में जुटे हुए हैं। देखा जाए तो प्रशांत किशोर की अलग-अलग पार्टियों के लिए अब तक बनाई गई चुनावी रणनीतियों का आधार भाजपा का विरोध ही रहा है। आसान शब्दों में कहा जाए, तो अरविंद केजरीवाल की वर्तमान राजनीति जिस भाजपा विरोध पर टिकी है। प्रशांत किशोर 2015 से ही उस भाजपा विरोधी राजनीति के ब्रांड एंबेसेडर रहे हैं। वैसे, प्रशांत किशोर को नरेंद्र मोदी के आलोचक के तौर पर देखा जाता है। और, उन्होंने अपनी चुनावी रणनीतियों से साबित भी कर दिया है कि पीके चाहे, तो भाजपा को हार का स्वाद चखा सकता है।

प्रशांत किशोर ने अपने ट्वीट के अंत में लिखा है कि शुरुआत बिहार से। जिसका सीधा सा मतलब है कि पीके का इरादा बिहार से ही राजनीति में पदार्पण करने का है। बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव की राजनीतिक प्रयोगशाला कहा जा सकता है। जेपी आंदोलन के दौरान बिहार ने इसे साबित भी किया है। खैर, प्रशांत किशोर का पार्टी बनाने का संकेत एक सीधा इशारा है कि प्रबल जातिगत राजनीति वाले बिहार में पीके की जन सुराज एक नया विकल्प दे सकती है।

● **अक्स ब्यूरो**

बिहार में कितनी संभावनाएं

बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश कुमार की प्रशांत किशोर से नजदीकी किसी से छिपी नहीं है। इसी साल दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद भी तमाम कयासों का दौर जारी हो गया था। वहीं, बिहार के वर्तमान राजनीतिक हालात इशारा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की भाजपा से दूरी बढ़ती जा रही है। हालांकि, नीतीश कुमार ने इस बारे में खुलकर अपनी बात नहीं रखी है। लेकिन, राजनीति में संकेतों के मायने किसी से छिपे नहीं हैं। बीते दिनों आरजेडी की ओर से आयोजित इफ्तार पार्टी में नीतीश कुमार ने शिरकत की थी। इसके बाद जेडीयू की इफ्तार पार्टी में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव नजर आए थे। संभव है कि जेडीयू और आरजेडी के बीच एक बार फिर से गठबंधन की खिचड़ी पक रही हो। लेकिन, प्रशांत किशोर के नई पार्टी बनाने के ऐलान के बाद माना जा रहा है कि पीके अब बिहार में आम आदमी पार्टी की तरह ही एक नया विकल्प बनने की कोशिश करेंगे।

उदयपुर में तीन दिन तक चले चिंतन शिविर में पार्टी की दिशा और दशा पर मंथन किया गया। जहां एक ओर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं का उत्साहवर्धन किया, वहीं कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। लेकिन पार्टी संक्रमण के इस काल से कैसे बाहर निकलेगी, इसका कोई फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। ऐसे में अभी भी यह सवाल खड़े हैं कि कांग्रेस किस ओर जाएगी। आगामी दिनों में यह बात साफ हो जाएगी कि कांग्रेस की भविष्य की रणनीति क्या है।

किस ओर कांग्रेस ?

भी तरी दुविधाओं और भाजपा के गांधी परिवार के खिलाफ लगातार हमलों के बीच फंसी कांग्रेस की चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर (पीके) से भी बात नहीं बन पाई। मसला 2024 के लोकसभा चुनाव और उससे पहले राज्यों में पार्टी को खड़ा करने का था। प्रशांत किशोर सीधे अध्यक्ष सोनिया गांधी को रिपोर्ट करते हुए हर फैसले में हस्तक्षेप चाहते थे; लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को यह मंजूर नहीं था। प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे। लेकिन इसके बावजूद पीके कांग्रेस को एक तटस्थ रणनीतिकार के रूप में सुझाव दे सकते हैं या पार्टी उनकी सेवाएं ले सकती है। हालांकि इसका पता भविष्य में ही चलेगा। पार्टी में कई वरिष्ठ और युवा नेता इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कांग्रेस को राज्यों में खड़ा करना पड़ेगा, जबकि प्रशांत लोकसभा चुनाव के लिए राज्यों के बड़े क्षत्रपों ममता बनर्जी, चंद्रशेखर राव, चंद्रबाबू नायडू जैसे नेताओं से मिलकर पार्टी की रणनीति बनाने के हक में थे। कांग्रेस को लगता था इससे राज्यों में उसका अपना बचा-खुचा संगठन और आधार भी खत्म हो जाएगा। पीके के अलग होने के बाद कांग्रेस ने अब अपने तौर पर अगले विधानसभा चुनावों और 2024 के चुनावों के लिए तैयार करने की कोशिश संगठन में फेरबदल करके शुरू कर दी है। राज्यों में नए अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। वहीं 13 से 15 मई तक उदयपुर में मंथन कर आगामी रणनीति बनाई गई।

कांग्रेस में शामिल होने और पार्टी की 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति बुनने का जिम्मा प्रशांत किशोर की आईपैक कंपनी को मिलने की खत्मों के बाद जब मीडिया में यह कयास लग रहे थे कि पीके को क्या पद मिलेगा? तभी यह बात सामने आई कि प्रशांत तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव के साथ भी चुनाव पर बात कर रहे हैं। राव वह नेता हैं, जो हाल में काफी सक्रिय हुए हैं और राष्ट्रीय राजनीति में उन्होंने दिलचस्पी दिखाई है। हालांकि वह कांग्रेस को किसी भी संभावित तीसरे मोर्चे का जरूरी हिस्सा बताते रहे हैं; लेकिन यह भी खत्में रही हैं कि उनकी अपनी **राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं** हैं। हाल में जब राहुल गांधी तेलंगाना के दौरे पर गए थे, तो उन्होंने राव की

कांग्रेस में बुजुर्ग नेताओं की छुट्टी तय

उदयपुर चिंतन शिविर में कांग्रेस में बड़े बदलाव को लेकर सिफारिशों पर मुहर लग गई है। इसके तहत अब अगले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में कई बुजुर्ग नेताओं के टिकट कटने तय हैं। युवाओं को संगठन से लेकर चुनाव टिकट वितरण में प्रायोरिटी मिलेगी। ये बदलाव 2024 के लोकसभा चुनाव और इसके बाद होने वाले विधानसभा चुनावों से लागू होंगे। लोकसभा चुनावों में 50 प्रतिशत टिकट 50 साल से कम उम्र के नेताओं को मिलेंगे। लोकसभा चुनावों से पहले होने वाले चुनावों में यह प्रावधान लागू नहीं होगा। युवाओं से जुड़े हुए समूह की इन सिफारिशों को लागू करने पर सभी ने सहमति जताई है। बुजुर्ग नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में भेजने की तैयारी है। कांग्रेस के संगठन में टॉप-टू-बॉटम हर स्तर पर 50 फीसदी पद 50 साल से कम उम्र के नेताओं को देने का प्रावधान होगा। चिंतन शिविर में मंथन के बाद तैयार किए उदयपुर डिक्लेरेशन में इसे लागू करने का फैसला किया है। कांग्रेस के युवाओं से जुड़े ग्रुप की सिफारिशों में नेताओं की रिटायरमेंट की उम्र तय करने का सुझाव दिया है।

कुछ नीतियों की आलोचना की थी। लेकिन इसके बावजूद पीके कांग्रेस को एक तटस्थ रणनीतिकार के रूप में सुझाव दे सकते हैं या पार्टी उनकी सेवाएं ले सकती है।

क्या अब यह माना जाए कि प्रशांत किशोर के बिना कांग्रेस का काम नहीं चलेगा? कांग्रेस से बाहर कुछ लोगों ने ऐसी राय जाहिर की है। लेकिन शायद यह सच नहीं है। कांग्रेस सत्ता में लंबे समय तक और सन् 2004 से सन् 2014 तक बिना प्रशांत किशोर के ही रही। हां, प्रशांत किशोर ने उनके और कांग्रेस के बीच किसी गठबंधन के न होने के बाद जाते-जाते एक बात सच कही कि 'कांग्रेस को आज एक अदद अध्यक्ष की जरूरत है।' उनका यह भी सुझाव था कि पार्टी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार अलग-अलग हो। अर्थात् पार्टी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार यदि गांधी परिवार से हो, तो पार्टी अध्यक्ष गैर-गांधी हो।

शुरू में प्रशांत किशोर और कांग्रेस में काफी चीजें मंजूरी की तरफ बढ़ती दिख रही थीं। लेकिन दो मसलों पर पेच ऐसा फंसा कि बातचीत ही टूट गई। पहला बड़ा मसला था कि प्रशांत किशोर ने अपने सुझावों में (जिसकी स्लाइड्स उन्होंने पार्टी को दी थीं) पार्टी अध्यक्ष प्रियंका गांधी को बनाने का सुझाव दिया था और प्रधानमंत्री का किसी और को बनाने का। इसके उलट कांग्रेस हर हालत में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाना चाहती है। यह भी कहा जाता है कि प्रशांत कांग्रेस को बिहार (राजद आदि), महाराष्ट्र (एनसीपी, शिवसेना आदि) और जम्मू-कश्मीर (नेशनल कॉन्फ्रेंस आदि) जैसे राज्यों में वर्तमान सहयोगियों से अलहदा होने का सुझाव दे रहे थे।

तमाम बातों के बीच प्रशांत किशोर के कांग्रेस से अलग होने को लेकर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा- 'प्रशांत किशोर के साथ बैठक और चर्चा के बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा चुनाव 2024 को फोकस करते हुए एक समिति (ईएजी) का गठन किया था, जिसमें चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को शामिल होने को कहा था। लेकिन किशोर ने ऑफर को ठुकराते हुए कांग्रेस में शामिल होने से इनकार कर दिया। हम उनके सुझावों और प्रयास के लिए उनकी सराहना करते हैं।'

प्रशांत किशोर ने इसे लेकर कहा- 'मैंने ईएजी के हिस्से के रूप में पार्टी में शामिल होने और चुनावों की जिम्मेदारी लेने के कांग्रेस के उदार प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। मेरी विनम्र राय में परिवर्तनकारी सुधारों के माध्यम से गहरी जड़ें जमाने वाली संरचनात्मक समस्याओं को ठीक करने के लिए पार्टी को मुझसे अधिक नेतृत्व और सामूहिक इच्छाशक्ति की जरूरत है।' हाल में उनके कांग्रेस में शामिल होने को लेकर दो बार चर्चा हुई। हालांकि दोनों बार प्रशांत कांग्रेस में नहीं जा पाए।

क्या चाहते थे प्रशांत किशोर?

प्रशांत किशोर चाहते थे कि सोनिया गांधी पूर्णकालिक कांग्रेस अध्यक्ष बनें। एक कार्यकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर का बने। राहुल गांधी को संसदीय दल का नेता बनाया जाए। गैर-गांधी कार्यकारी या उपाध्यक्ष वरिष्ठ नेतृत्व के आदेशों के तहत हो। कांग्रेस आम लोगों के बीच पैठ मजबूत करे। पार्टी गांधीवाद के अपने सिद्धांतों पर ही चले। गठबंधन साथियों को बराबर भरोसे में रखे। पार्टी एक परिवार-एक टिकट के फॉर्मूले पर सख्ती से चले। सिर्फ चुनाव के जरिए ही पार्टी के संगठन प्रतिनिधि चुने जाएं। अध्यक्ष और कार्यकारी समिति सहित हर पोस्ट के लिए एक समय सीमा (कार्यकाल) तय किया जाए। करीब 15,000 जमीनी नेताओं के साथ एक करोड़ कार्यकर्ता मैदान में मजबूती से काम करें। करीब 200 प्रभावी लोगों, कार्यकर्ताओं और सिविल सोसायटी के लोगों का ग्रुप बनाया जाए। प्रशांत का सुझाव गठबंधन से जुड़े मुद्दे को सुलझाने और पार्टी के संवाद सिस्टम में बदलाव पर जोर के अलावा देश की जनसंख्या, मतदाता, विधानसभा सीटें, लोकसभा सीटों तक के आंकड़े तैयार रखने पर था।

कांग्रेस के भीतर वरिष्ठ नेताओं का एक ऐसा मजबूत वर्ग है, जो प्रशांत की सब कुछ उनके जरिए किए जाने वाली मांग के कतई समर्थन में नहीं था। यही नहीं, इनमें से कुछ वरिष्ठ नेताओं का नेतृत्व को सुझाव था कि पार्टी की सारी रणनीति एक ऐसे व्यक्ति के सामने उजागर नहीं की जा सकती, जो दूसरे विरोधी दलों के लिए भी काम करता हो। यही कारण रहा कि पीके की इस बात पर पार्टी में सहमति नहीं बन पाई कि चुनाव की सारी रणनीति उनके जरिए बुनी जाए।

कांग्रेस देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है। आज भी उसके पास **रणनीतिकार** वरिष्ठ नेताओं और ऊर्जावान युवा नेताओं की कमी नहीं। हाल फिलहाल पार्टी नेतृत्व काफी सक्रिय दिख रहा है और उसने राज्यों में नया नेतृत्व सामने लाने के लिए अध्यक्षों और टीमों की नियुक्ति की है। शायद उसने अपने स्तर पर खुद को हार की धूल झाड़कर उठाने की तैयारी कर ली है।

चुनाव हारने के बाद पंजाब और इस साल चुनाव में जाने वाले राज्य हिमाचल प्रदेश और पड़ोसी हरियाणा में अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नए अध्यक्षों और टीम की नियुक्तियां की हैं। पंजाब में विधानसभा चुनाव में झटका देने वाली हार के बाद अमरिंदर सिंह राजा वारिंग, हिमाचल में पूर्व मुख्यमंत्री और कद्दावर नेता रहे दिवंगत राजा वीरभद्र सिंह की तीसरी बार सांसद बनी पत्नी प्रतिभा सिंह और हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विश्वस्त उदय भान को अध्यक्ष बनाया गया है।

पार्टी के संगठन चुनाव से पहले, जिसमें पार्टी अध्यक्ष का चुनाव होना है; कांग्रेस की यह बड़ी कवायद है। कांग्रेस में हाल के महीनों में एक नई परम्परा शुरू हुई है। पंजाब में उसने अध्यक्ष के अलावा कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए थे, जिसके बाद हिमाचल और हरियाणा में भी यही करते हुए चार-चार कार्यकारी अध्यक्ष बनाए हैं। शायद ऐसा करने के पीछे उसका मकसद राज्यों में सभी क्षेत्रों में नेताओं को प्रतिनिधित्व देकर शांत करना हो; लेकिन इससे यह भी होगा कि एक से अधिक शक्ति केंद्र स्थापित हो जाएंगे। वैसे कई नेता इस विचार को सही ठहराते हैं। उनका कहना है कि इससे संगठन मजबूत होगा; क्योंकि इन नेताओं को जिम्मेदारी के अहसास के कारण काम करने की प्रेरणा मिलेगी।

● **विपिन कंधारी**

देश के बड़े वोट बैंक बहुजन समाज के लिए हर पार्टियां नीति-रणनीति बनाई हैं, लेकिन उनका ठीक से क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। इस कारण आज भी ये जातियां विकास के हाशिए पर खड़ी हैं। जब भी चुनाव का मौका आता है, राजनीतिक पार्टियां इनके विकास के लिए बड़े-बड़े दावे तो करती हैं, लेकिन उसके बाद उसे भुला दिया जाता है। ये जातियां केवल पॉलिटिकल मैटेरियल बनकर रह गई हैं।

केवल पॉलिटिकल मैटेरियल बहुजन!

बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद मान्यवर कांशीराम इकलौते ऐसे नेता हुए हैं, जिन्होंने दलितों के लिए जीवन लगा दिया। कांशीराम ने तो न सिर्फ दलितों के लिए, बल्कि पिछड़ों के लिए भी एक लंबा संघर्ष किया और अपने लिए एक कमरे तक का घर नहीं बनाया, न ही परिवार वालों के लिए कभी कुछ किया। पूरे देश के दलितों और पिछड़ों के उत्थान के लिए बहुजन समाज की पताका लिए वह जब घर से निकले, तो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आखिरकार उप्र में वह सबसे ज्यादा मजबूती में दिखे और मायावती को आगे कर बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा की सरकार बनाने में कामयाब भी रहे। मायावती इस दौर में इस कदर उभरीं कि वह चार बार उप्र की मुख्यमंत्री बनीं। यह वो दौर था, जब बसपा न सिर्फ उप्र में, बल्कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और बिहार की तरफ भी बढ़ी। लेकिन इन राज्यों में राजनीतिक दखल के बावजूद कोई **खास मुकाम** हासिल नहीं कर सकी।

बता दें कि आजाद भारत में अंबेडकर ने साल 1956 में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। इस पार्टी ने साठ के दशक में महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तर भारत में अपना मजबूत जनाधार बनाया था। इस पार्टी के जरिए दलित राजनीति का गढ़ महाराष्ट्र में विदर्भ बना और उप्र में आगरा। हालांकि अंबेडकर के निधन के बाद इस पार्टी में फूट पड़ गई। लेकिन बाद में पंजाब में जन्मे कांशीराम ने अंबेडकर के दलित उत्थान मिशन को आगे बढ़ाया, जिसमें उन्होंने दलितों के साथ ही पिछड़ों के हक की भी बात की। हालांकि कांशीराम का सपना था कि बहुजन समाज पार्टी एक मजबूत और नेशनल पार्टी बनकर उभरे। लेकिन राजनीति में उनके द्वारा लाई गईं मायावती उनके इस सपने को बहुत दिनों तक जीवित नहीं रख सकीं। हालांकि जब मायावती राजनीति में चमक रही थीं, तो वह केंद्र में आने और प्रधानमंत्री बनने के सपने जरूर देखती रहीं। हालांकि यह अलग बात है कि उन्होंने बाद में सवर्णों को साथ लेकर भी उप्र में सरकार बनाई; लेकिन उसके बाद से उनके पैर उप्र से उखड़ते चले गए और अब तो हाल यह है कि बसपा की नाव तकरीबन डूबती नजर आ रही है। इसकी कई वजह हैं। पहली यह कि मायावती की टक्कर का कोई नेता बसपा में दूसरा नहीं है, जो बहुजनों की इस पार्टी का केवल नेतृत्व ही नहीं कर सके, बल्कि बहुजनों को भरोसे में भी ले सके। दूसरी वजह यह है कि मायावती के अब वो तेवर नहीं रह गए हैं, जो 2012 तक रहे हैं। तीसरी यह कि अब वह उप्र के लिहाज से शारीरिक स्वास्थ्य से भी जूझ रही हैं। चौथी यह कि बसपा में मायावती के बाद सतीश मिश्र की तूती बोलती है, जिसे दलित और पिछड़ा, दोनों ही वर्ग स्वीकार नहीं करना चाहते। और पांचवीं व आखिरी वजह यह है कि अब दलित और पिछड़ों की राजनीति हर पार्टी करने लगी है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कोई अन्य क्षेत्रीय दल हो।

गौरतलब है कि गत माह 14 अप्रैल को डॉ. अंबेडकर की 131वीं जयंती मनाई गई, जिसे हर राजनीतिक दल ने धूमधाम से मनाया। जाहिर है इसमें वो पार्टियां भी शामिल रहीं, जो विशुद्ध रूप से सवर्णों की राजनीति करती हैं; क्योंकि अंबेडकर की जयंती और पुण्यतिथि मनाने का सबका एक ही प्रयोजन है कि किसी तरह दलित और पिछड़ा मतदाता (वोटर) उनका पक्का मतदाता हो जाए। कई दल काफी हद तक इसमें सफल भी हुए हैं, जिनमें भाजपा शीर्ष पर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अंबेडकर कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। उन्होंने तो दिल्ली के स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का नाम बदलकर अंबेडकर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस तक

जाति के नाम पर मिलता रहा है केवल धोखा

कहा जाता है कि राजनीति में अगले पल क्या होगा? यह भी दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। हर कोई मौके की नजाकत देखकर चाल चलता है और उसका फायदा उठाता है। रही बात जातिगत खेल की, तो यह तो राजनीतिक लोगों का बहुत पुराना पैंतरा रहा है। सच तो यह है कि आम लोगों को उन्हीं की जाति के नेता धोखा देते रहते हैं और लोग भी अपनी जाति के नेताओं के नाम की माला जपते रहते हैं। जिस दिन यह बात लोगों की समझ में आ गई, उस दिन लोग जाति देखकर नहीं, बल्कि ईमानदारी और काबिलियत देखकर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे। फिर चाहे वे दलित हों, या पिछड़े हों या सवर्ण हों।

कर दिया है। वहीं मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने तो अंबेडकर की जन्मस्थली महू को तीर्थ दर्शन योजना में शामिल करने की घोषणा तक कर डाली। उन्होंने यह भी कहा कि लोग वहां मुफ्त में सफर कर सकेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी अंबेडकर जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। लेकिन इस मुहिम में प्रधानमंत्री मोदी सबसे आगे हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद से अंबेडकर जयंती हर साल मनाई। पिछले दिनों तो वह संत रविदास जयंती पर अचानक दिल्ली स्थित रविदास मंदिर पहुंच गए और वहां महिलाओं के बीच बैठकर खड़ताल बजाते दिखे। जानकारों का मानना है कि इसका असर उन दिनों चल रहे पांच राज्यों के चुनावों पर कुछ-न-कुछ तो जरूर पड़ा और बसपा का वोट भाजपा को ट्रांसफर हुआ।

वहीं दूसरी ओर बहुजन आंदोलन से निकली बसपा ने इस बार अंबेडकर जयंती पर बड़े पैमाने पर हर संभाग में कार्यक्रम आयोजित किए। इस दौरान लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में बसपा प्रमुख मायावती ने बड़े तल्ख लहजे में कहा कि जातिवादी सरकारें उपेक्षित वर्ग के नेताओं को अपने समाज का भला करने की छूट नहीं देती हैं। दलितों के लिए यदि कोई कुछ करने का प्रयास करता है, तो उसे भी दूध की मक्खी की तरह निकालकर बाहर कर दिया जाता है।

प्रधानमंत्री मोदी से पहले कांग्रेस ने, खासकर इंदिरा गांधी ने दलितों को अपने साथ लेने की राजनीति की थी। यह वो दौर था, जब दलितों का अपना कोई नेता केंद्र सरकार में ही नहीं, राज्यों में भी उतने कद का नहीं था, जो कि उनका प्रतिनिधित्व कर सके। पिछड़ों के तो कई नेता तब तक केंद्र की राजनीति में आ चुके थे; लेकिन अंबेडकर के बाद दलितों का ऐसा कोई नेता केंद्र में नहीं था, जो ईमानदारी से उनके हक की लड़ाई लड़ सके। इक्का-दुक्का नेता राज्यों में था भी, तो वो या तो बड़े कद का नहीं था या अपने स्वार्थों की पूर्ति में लग गया था। ऐसे में दलितों के पास कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं था और स्वाभाविक तौर पर वो कांग्रेस की तरफ लंबे समय तक झुके रहे। लेकिन जैसे ही उन्हें कांशीराम जैसा सच्चा दलित हितैषी नेता मिला उनका कांग्रेस से मोहभंग होने लगा। इतना ही नहीं, कांशीराम ने पिछड़ों का भी ध्यान अपनी ओर खींचा और उनका कांग्रेस से काफी हद तक मोहभंग कराया। अब दलितों की राजनीति में कई पार्टियां कूद पड़ी हैं और वो उन्हें अपने खेमे में करने में लगी हैं।

लेकिन सवाल यह है कि क्या ये नेता और इनकी पार्टियां दलितों और पिछड़ों को वो सब दे सकेंगे, जो करने का सपना इन वर्गों के लिए बाबा साहब डॉ. अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम ने देखा था? यह सवाल इसलिए भी जरूरी है कि जब राजनीति की फिसलन भरी जमीन पर आने के बाद खुद मायावती, जो कि खुद दलित और पिछड़े वर्ग से हैं, उनका ख्याल नहीं रख सकीं, तो दूसरों से इन वर्गों के लिए क्या उम्मीद की जा सकती है? सवाल यह भी है कि मायावती के बाद क्या दलितों और पिछड़ों को कोई ऐसा नेता मिल सकेगा? जो उनकी समस्याओं के लिए जूझ सके, उनके हक उन्हें दिलवा सके?

हालांकि अब तक इस मामले में तकरीबन सभी दलित नेता फेल ही रहे हैं; लेकिन मायावती से एक दौर में उम्मीद थी कि वह बहुजनों के हक दिलवाकर रहेंगी। हालांकि अब इस तरह की उम्मीद करना व्यर्थ ही है; क्योंकि मायावती अब दलितों के मुद्दों और देश में हो रही राजनीति पर खामोश ज्यादा रहती हैं। एक और दलित नेता इन दिनों उप्र में उभरकर सामने आया है और वह हैं चंद्रशेखर आजाद 'रावण'। चंद्रशेखर दलित युवाओं के काफी प्रिय नेता हैं; लेकिन मायावती के कद को वह न तो छू सके हैं और न भविष्य में इसकी संभावना दिखती है। इसकी एक वजह यह है कि **चंद्रशेखर राजनीतिक पैंतरेबाजी** में अभी उतने मंजे हुए खिलाड़ी नहीं हैं, जितनी की मायावती। दूसरी वजह यह है कि चंद्रशेखर की पहचान पूरे प्रदेश में भी अभी नहीं बन सकी है, जबकि मायावती की छवि राष्ट्रीय स्तर की है। लेकिन अब दलित और पिछड़े वोट बैंक पर सबसे ज्यादा कब्जा सत्ताधारी दल भाजपा का है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी की वजह से है। यह अलग बात है कि आज की राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी का विकल्प ठीक उसी तरह दिखाई नहीं दे रहा है, जिस तरह एक दौर में इंदिरा गांधी का कोई विकल्प नजर नहीं आता था।

● **इन्द्र कुमार**

2023 में चुनाव के केंद्र में होगी अनुसूचित जाति

मप्र में होने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां दोनों दलों के भीतर तेज हो गई। भाजपा और कांग्रेस का खास फोकस इस बार ग्वालियर-चंबल अंचल पर लगा हुआ है। दोनों दलों की निगाहें अनुसूचित जाति वर्ग के वोटों पर टिकी हुई हैं। 2018 के चुनाव में कांग्रेस को दलित वर्ग का भरपूर सहयोग मिला था, यही वजह है कि विशेषकर ग्वालियर-चंबल अंचल में कांग्रेस ने भाजपा की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हुए विधानसभा की 34 सीटों में से 26 सीटों पर जीत का परचम लहराया था। 2023 में कांग्रेस वापस इस प्रदर्शन को दोहराना चाहती है, लेकिन भाजपा भी अपना प्रदर्शन सुधारना चाहती है। ऐसे में दोनों दलों में अंदर खाने दलित वोट बैंक को साधने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। दरअसल, ग्वालियर-चंबल अंचल में विधानसभा की 34 सीटें आती हैं, जिनमें से 7 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 34 में से 26 सीटें जीत ले गई थी। खास बात यह है कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 7 सीटों में 6 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया था, जबकि भाजपा को केवल 1 ही सीट मिली थी। हालांकि उस वक्त कांग्रेस के स्टार प्रचारक ज्योतिरादित्य सिंधिया का इसमें बड़ा योगदान था जो अब भाजपा में हैं। सिंधिया के भाजपा में शामिल होने के बाद यहां के समीकरण बदल गए। उपचुनाव के बाद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 7 सीटों में 5 सीटों पर भाजपा और 3 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है।

मोदी भरोसे भाजपा

छत्तीसगढ़ में अगले साल यानी 2023 में विधानसभा चुनाव होना है। इसको लेकर यहां की सियासत गर्माई हुई है। भाजपा और कांग्रेस दोनों दल तैयारियों में जुटे हैं। इसी बीच 15 सालों तक छत्तीसगढ़ में राज करने वाली भाजपा ने अपने चुनावी चेहरे की घोषणा भी कर दी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा के चेहरे वाले सवाल पर विराम लग गया है। भाजपा के सह प्रभारी नितिन नवीन ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा का चेहरा नरेंद्र मोदी होगा। नवीन के इस बयान के बाद भाजपा में भूचाल सा आ गया है। माना जा रहा है कि नितिन नवीन के इस बयान के बाद उन नेताओं की टेंशन बढ़ गई है जो खुद को भाजपा का चेहरा बनाने की जुगत लगा रहे थे।

दरअसल छत्तीसगढ़ भाजपा की लगातार हुई चुनावी हार, संगठन की कमजोरी, आपसी गुटबाजी केंद्रीय नेतृत्व की रडार में बना हुआ है। वहीं भाजपा सह प्रभारी के इस बयान से मानो सत्ताधारी दल कांग्रेस की बांछे खिल गई हैं। कांग्रेस की ओर से संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि 15 साल शासन के बाद छत्तीसगढ़ भाजपा की ऐसी दुर्गति हो गई है कि भूपेश बघेल का मुकाबला करने के इनके पास कोई चेहरा ही नहीं बचा है। नितिन नवीन के बयान के बाद छत्तीसगढ़ भाजपा की राजनीति में कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। सवाल यह है कि क्या सच में भाजपा के भीतर कोई चेहरा नहीं बचा है। क्या सच में रमन-धरम और साय की तिकड़ी जनता का विश्वास खो चुकी है। या फिर 15 साल के शासन के बाद चेहरे इतने दागदार हो गए हैं कि उन पर विश्वास जताकर 2023 का चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है।

इन तमाम सवालों के बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारी प्राथमिकता 2023 का चुनाव जीतना है। कांग्रेस की कमियों को उजागर करना है ना कि चेहरे की। वहीं इसी सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि भाजपा कभी भी चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ती है। हमेशा चुनाव जीतने के 1 घंटे के भीतर चेहरा तय करती है। साथ ही यह भी कहा कि कांग्रेस अपनी चिंता करे मेरी चिंता करके अपना खून ना जलाए।

बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के लिए रणनीति तैयार होने लगी है। दोनों ही दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। चेहरे को लेकर भाजपा के भीतर धुंध छूटने लगा है। इस धुंध के साथ ही छटने लगा है बड़े नेताओं के चेहरे का विश्वास। क्योंकि बीते विधानसभा चुनाव में हारे तमाम बड़े चेहरे इस जुगत में जुटे थे कि इस चुनाव में अपने चेहरे के दम पर मिशन फतेह करेंगे। लेकिन नितिन नवीन के एक बयान ने सारे नेताओं के चेहरों पर हवाइयां उड़ा दी हैं और भाजपा को फिर से संगठन आधारित पार्टी पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है।

उधर, आगामी 10 जून को राज्यसभा की 57 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। छत्तीसगढ़ में भी 2 सीटों पर चुनाव होना है। ऐसे में राज्यसभा के संभावित उम्मीदवारों को लेकर चर्चा, लॉबिंग का दौर चल रहा है। अब इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। दरअसल भाजपा ने कहा है कि बोरे-बासी खाने वाले व्यक्ति को ही राज्यसभा भेजा जाना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा है कि राज्यसभा कौन जाएगा, यह तय करने का अधिकार जनता ने कांग्रेस को दिया है। बता दें कि राज्य में विधायकों की संख्या को देखते हुए तय माना जा रहा है कि राज्यसभा की दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जाएंगी। ऐसी चर्चाएं हैं कि कांग्रेस एक सीट पर किसी स्थानीय नेता को और दूसरी सीट पर किसी राष्ट्रीय नेता को राज्यसभा भेज सकती है। इस पर भाजपा ने निशाना साधा है और स्थानीय नेता को राज्यसभा भेजने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा है कि कांग्रेस ने पिछले दिनों यूनिवर्सिटी में कुलपति की नियुक्ति पर स्थानीय का मुद्दा चलाया था। अब राज्यसभा में भी बोरे-बासी खाने वाले छत्तीसगढ़ के व्यक्ति को ही राज्यसभा भेजा जाना चाहिए। बता दें कि बोरे-बासी छत्तीसगढ़ की स्थानीय डिश है।

छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चरणदास महंत खुले तौर पर राज्यसभा जाने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर प्रियंका गांधी, कपिल सिब्बल और पी. चिदंबरम के नामों की चर्चा है। बता दें कि पी. चिदंबरम और कपिल सिब्बल का कार्यकाल खत्म हो रहा है। बता दें कि राज्यसभा चुनाव में जितनी सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उसमें एक जोड़कर कुल विधायकों की संख्या से भाग देने पर जो संख्या आती है, उसमें एक जोड़कर जो संख्या मिलेगी, उतने विधायकों की जरूरत एक सीट जीतने के लिए चाहिए होगी। ऐसे में छत्तीसगढ़ में 2 सीटों पर चुनाव होना है। ऐसे में इसमें एक जोड़कर यह संख्या 3 हो गई। छत्तीसगढ़ की कुल सीटों की संख्या 90 है, जिसे 3 से भाग देना पड़ेगा। इससे जो संख्या मिलेगी, वो 30 है और इस 30 में एक और जोड़कर जो 31 की संख्या मिलेगी, सीट जीतने के लिए इसी फॉर्मूले की जरूरत होगी।

● **रायपुर से टीपी सिंह**

कांग्रेस और भाजपा की राजनीति अब हिंदुत्व के रास्ते पर

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा की राजनीति अब हिंदुत्व के रास्ते पर उतर गई है। कभी भाजपा का मुद्दा रहा राम मंदिर अब कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश के दौरे में राम वनगमन पथ का जिक्र कर रहे हैं, तो मंदिरों में मत्था टेकने भी पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री के इस कदम को लेकर भाजपा अब निशाना भी साध रही है। भाजपा के बूथ विस्तार अभियान में भाजपा नेता इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि भाजपा जिस हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ रही है, अब मजबूरी में कांग्रेस और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी इसी रास्ते पर चलना पड़ रहा है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद गाय, गोबर और गौमूत्र को लेकर कई योजनाएं लॉन्च की गई। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में राम वनगमन पथ है और उन स्थानों के विकास के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च भी कर रही है।

राजनीति का केंद्र बना राजस्थान

राजस्थान इस समय देश की राजनीति का केंद्र बिंदु बना हुआ है। देश की दो सबसे बड़ी पार्टियां भाजपा और कांग्रेस इस महीने राजस्थान में अपने-अपने दल की बड़ी बैठकें कर रही हैं। कांग्रेस ने अपनी पार्टी की दशा-दिशा सुधारने के लिए राजस्थान के उदयपुर में 13 से 15 मई के बीच तीन दिवसीय चिंतन शिविर बैठक की, तो इसके अगले सप्ताह 20-21 मई को भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों और संगठन को मजबूत बनाने की रणनीति पर विचार-विमर्श करने के लिए राजस्थान के ही जयपुर में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक करने जा रही है।

एक मायने में देखा जाए तो दोनों ही राजनीतिक दल राजस्थान में बैठक कर 2022 और 2023 में होने वाले 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करेंगे, लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत के सपने को साकार करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भाजपा कांग्रेस शासित दो राज्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर खास ध्यान दे रही है। भाजपा आलाकमान की इसी मंशा को समझते हुए राजस्थान भाजपा की कद्दावर नेता मानी जाने वाली वसुंधरा राजे ने भाजपा आलाकमान के साथ मेल-मिलाप का सिलसिला शुरू कर दिया है। राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी और वर्तमान में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर कार्य कर रही वसुंधरा राजे और आलाकमान के रिश्ते जगजाहिर रहे हैं, लेकिन पिछले डेढ़ महीनों के दौरान इसे सुधारने के लिए वसुंधरा राजे ने अपनी तरफ से पहल की है।

मुलाकातों के सिलसिले की बात करें तो पिछले डेढ़ महीनों के दौरान वसुंधरा राजे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत पार्टी के कई आला नेताओं से मुलाकत कर अपनी बात रखी है। 24 मार्च को वसुंधरा राजे ने नई दिल्ली में संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, निर्मला सीतारमन और राजस्थान भाजपा के प्रभारी अरुण सिंह के साथ मुलाकात की थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में देहरादून गई वसुंधरा राजे और गृहमंत्री अमित शाह के बीच उसी दिन एयरपोर्ट पर महत्वपूर्ण मुलाकात हुई। वसुंधरा ने 29 मार्च को नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। जाहिर तौर पर इन मुलाकातों के दौरान राजस्थान के राजनीतिक हालात को लेकर चर्चा हुई और दोनों ने एक-दूसरे को समझने की कोशिश भी की।

ऐसे में सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिर राजस्थान को लेकर वसुंधरा राजे सिंधिया की कोशिशों का क्या परिणाम निकला? भाजपा आलाकमान राजस्थान को लेकर आखिर क्या सोच रहा है? क्या भाजपा मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के नाम के साथ अशोक गहलोत के खिलाफ विधानसभा चुनाव में उतरेगी या सामूहिक नेतृत्व के आधार पर चुनाव लड़ेगी? इन सवालों का जवाब देते हुए भाजपा के एक बड़े नेता ने बताया कि फिलहाल भाजपा आलाकमान की सबसे बड़ी कोशिश राज्य संगठन में घर कर चुकी गुटबाजी को पूरी तरह से खत्म करना है। इसीलिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वयं पहल करते हुए 19 अप्रैल को अपने आवास पर राजस्थान भाजपा के सभी नेताओं को बुलाकर गुटबाजी को खत्म कर मिलकर गहलोत सरकार के खिलाफ लड़ने की नसीहत दी।

उस दिन नड्डा के आवास पर लगभग पौने पांच घंटे तक चली बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के अलावा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, राजस्थान से लोकसभा सांसद एवं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, प्रदेश संगठन महासचिव चंद्रशेखर और राजस्थान विधानसभा में नेता विपक्ष गुलाबचंद कटारिया सहित राज्य के कई अन्य दिग्गज नेता भी शामिल हुए थे। राजस्थान भाजपा के लिए कितना अहम बन गया है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि 20-21 मई को जयपुर में होने वाली राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक से पहले जेपी नड्डा ने 10 मई को राज्य में दो दिवसीय दौरा किया है। अमित शाह भी इसी महीने राज्य के आदिवासी इलाकों के दौरे पर रहेंगे तो वहीं राजस्थान भाजपा प्रभारी अरुण सिंह एक सप्ताह के लिए राज्य के दौरे पर जा रहे हैं।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

फिलहाल जोर गुटबाजी दूर कर एक होने का

भाजपा के एक बड़े नेता ने पार्टी की रणनीति के बारे में कहा कि वसुंधरा राजे राज्य की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो भाजपा की कद्दावर नेता हैं और इसलिए पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व भी दे रखा है, लेकिन जहां तक विधानसभा चुनाव में चेहरे का सवाल है, यह राज्य विशेष की राजनीतिक परिस्थिति पर निर्भर करता है। भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके पास मजबूत संगठन और नरेंद्र मोदी जैसा लोकप्रिय नेता है। दरअसल, यह बताया जा रहा है कि भाजपा में ज्यादातर लोगों की राय राजस्थान में सामूहिक नेतृत्व के आधार पर ही चुनाव लड़ने की है। यानी राजस्थान के सभी नेता गुटबाजी दूर कर और मिलकर केंद्र सरकार के जनकल्याणकारी योजनाओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय चेहरे और गहलोत सरकार की नाकामियों को सामने रखकर चुनावी मैदान में उतरें और मुख्यमंत्री का चयन चुनाव जीतने के बाद किया जाए। हालांकि, चेहरे को लेकर भाजपा के अंतिम फैसले और आखिरी घोषणा के लिए चुनाव के समय तक का इंतजार करना पड़ेगा।

उद्धव की अग्निपरीक्षा

बालासाहेब ठाकरे का राजनीतिक मंत्र था कि दुश्मन बनाओ, सेना खुद खड़ी हो जाएगी। इस मंत्र को उद्धव ठाकरे ने अपनाते हुए जब भाजपा को दुश्मन बनाया तो ठाकरे के शिवसैनिकों को सत्ता दिलाने के लिए कांग्रेस और राकांपा ही सहयोगी हो गए, जो 2019 से पहले शिवसेना के साथ खड़ा भी नहीं होना चाहते थे। लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह शिवसेना के खिलाफ भाजपा मोर्चाबंदी कर रही है उससे उद्धव ठाकरे की अग्निपरीक्षा होनी है।

दरअसल, बालासाहेब ठाकरे से उद्धव ठाकरे की शिवसेना में सबसे बड़ा बदलाव मातोश्री से मंत्रालय शिफ्ट होना भी है और मातोश्री की ताकत बरकरार रखने के लिए मंत्रालय की ताकत का इस्तेमाल करना भी है। लेकिन दुश्मन बनाने के तरीकों में कोई बदलाव नहीं आया है। 1995 में जब भाजपा के साथ मिलकर शिवसेना ने सरकार बनाई तो बालासाहेब ने शिवसेना की रणनीति साफ करते हुए कहा, शिवसेना में आपको हमेशा प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहना होता है। एक अर्थ में आपका दुश्मन आपका निर्माण करता है। दुश्मन कौन है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। असल में यहां दुश्मन वक्त-वक्त पर बदलता रहता है। लेकिन इस पूरी कड़ी में उग्र हिंदुत्व का चोगा कभी बालासाहेब ने शिवसेना से उतरने नहीं दिया और उद्धव ठाकरे ने भी राजनीतिक हिंदूवादी चेहरे को ही शिवसेना की ढाल बनाया। मातोश्री की पहचान भी यही रही और ताकत भी इसी से मिली। तभी तो 5 जून 2019 को जब अमित शाह 50:50 के फॉर्मूले पर मुहर लगाने मातोश्री पहुंचे तो उद्धव ठाकरे ने भाजपा का नाम लिए बगैर कहा, आरएसएस तय करे कि जो भगवान राम के पदचिन्हों पर न चले, झूठ बोले, क्या उसे हिंदूवादी पार्टी कहा जा सकता है? अब यही सवाल भाजपा उठा रही है, जो हनुमान चालीसा पाठ करने वाले पर राजद्रोह का मुकदमा ठोंक दे, क्या वह हिंदूवादी पार्टी हो सकती है।

दरअसल शिवसेना ने जिस रास्ते मुंबई और महाराष्ट्र में अपनी ताकत बढ़ाई और विस्तार किया, अब वह उस रास्ते चल नहीं सकती। सांप्रदायिक हिंसा हो या दंगे, जहां-जहां शिवसेना की भागीदारी हुई, वहां वह राजनीतिक तौर पर मजबूत हुई। 1970 के दशक में महाड, भिवंडी, जलगांव, 1984 में भिवंडी से ठाणे और मुंबई तक। 1989 में पनवेल, नासिक, औरंगाबाद और अमरावती तक। ध्यान दें तो नवनीत राणा अमरावती से ही चुनाव जीतीं। जिस अमरावती पर 1996 से 2014 तक शिवसेना का कब्जा (1998 में रिपब्लिकन) रहा, उस अमरावती में 20 साल बाद निर्दलीय नवनीत राणा ने शिवसेना के सासंद आनंद राव अड्सूल को 37 हजार वोटों से हराया। नवनीत राणा 2014 में राकांपा के टिकट पर शिवसेना से सवा लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव हार गई थीं। तो क्या भाजपा ने शिवसेना को खत्म कराने के लिए ही 2019 के विधानसभा चुनाव में अपने वोट नवनीत राणा को ट्रांसफर कराए और 2022 में भाजपा हनुमान चालीसा के सवाल पर खुलकर निर्दलीय सासंद नवनीत के पीछे खड़ी हो गई। यानी भाजपा जानती है कि शिवसेना अगर सफल हो गई तो महाराष्ट्र में वह कभी सत्ता में वापस लौट नहीं पाएगी। दिल्ली में सत्ता में रहने के बावजूद अगर मुंबई पर कब्जा नहीं है तो यह उसकी सबसे बड़ी हार है, क्योंकि बड़े कॉरपोरेट हों या गुजराती व्यापारियों का समूह दोनों की जरूरत मुंबई है।

मुंबई पर राज शिवसेना ने किया है। मातोश्री ने किया है। यानी शिवसेना की राजनीतिक फंडिंग कॉरपोरेट और गुजराती व्यापारियों के आसरे ही होती रही। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने 2014 में शिवसेना को खुले तौर पर वसूली पार्टी कहा और बड़े कॉरपोरेट से लेकर गुजरातियों तक को आसरा दिया कि अब उसे शिवसेना को फंडिंग करने की जरूरत नहीं है। 2019 तक तो यह चल गया लेकिन शिवसेना के सत्ता में आने के बाद फंडिंग को लेकर भी दिल्ली-मुंबई के बीच टकराव है। तीसरा सवाल पावर शिफ्ट का है, क्योंकि शिवसेना न तो अपने बूते महाराष्ट्र की सत्ता में है और न ही वह शरद पवार की राकांपा और कांग्रेस की विचारधारा के साथ खड़ी है। यानी सत्ता की चाबी और मोदी विरोध ने ही शिवसेना, कांग्रेस और राकांपा को साथ ला खड़ा किया है। लेकिन इस कड़ी में उद्धव ने बालासाहेब की शिवसेना को गंवाया और मोदी-अमित शाह की जोड़ी जिस रास्ते राजनीति साध रही है उसमें बालासाहेब की सोच ही दिल्ली से उभरती दिखाई देती है। 19 अगस्त 1967 को नवाकाल में पत्रकार प्रभाकर वैद्य ने बालासाहेब ठाकरे के उस वक्तव्य को छापा, जिसमें वे खुद को हिटलर मानने से नहीं कतराते। लिखा, हां, मैं तानाशाह हूं। इतने शासकों की हमें क्या जरूरत है। आज भारत को तो हिटलर की आवश्कता है। भारत में लोकतंत्र क्यों होना चाहिए? यहां तो हमें हिटलर चाहिए। अब उद्धव ठाकरे खुले तौर पर मोदी-शाह को हिटलर कहने से नहीं कतराते। तो, सियासी बदलाव के इस दौर में समझना यह भी होगा कि शरद पवार हों या शिवसेना या भाजपा, सभी को सत्ता चाहिए।

● **बिन्दु माथुर**

मातोश्री समानांतर सत्ता का प्रतीक

मुंबई जानती है सत्ता किसी की रहे, मातोश्री समानांतर सत्ता का प्रतीक है। इसलिए एक वक्त बहुराष्ट्रीय कंपनी एनरॉन की चेयरमैन रेबेका मार्क को भी आना पड़ा। अमेरिकी विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर भी मातोश्री पहुंचे। हथियारों के अंतरराष्ट्रीय व्यापारी अदनान खागोशी हो या चंद्रास्वामी या पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा, या मौजूदा गृहमंत्री अमित शाह, सभी को हिंदू पादशाही के संस्थापक ठाकरे के मातोश्री जाना ही पड़ा। पहली बार उसी मातोश्री को हनुमान चालीसा के नाम पर चुनौती दी गई, तो आग दिल्ली तक पहुंची है। दिल्ली शिवसेना को शहीद बनाए बगैर सत्ता से हटाना चाहती है। उद्धव ठाकरे मंत्रालय नहीं तो मातोश्री से मुंबई को हांकने की ताकत बरकरार रखना चाहते हैं। टकराव मुंबई पर कब्जे भर का नहीं, बल्कि 2024 से पहले हर हाल में महाराष्ट्र में नए राजनीतिक समीकरण बनाने का है जिसकी जरूरत अगले लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों में भाजपा को सबसे ज्यादा है।

विकास का रोडमैप

उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार मिशन मोड में नजर आ रहे हैं। इसीलिए सरकार के गठन के बाद दूसरे ही महीने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक-एक करके कई योजनाओं की घोषणा कर दी है। इन योजनाओं का फायदा शहरों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक के लोगों को होने वाला है। विकास कार्य करने में लगी योगी सरकार ने अलग-अलग योजनाओं की घोषणा भी कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत नई नहरों का निर्माण कराएगी तथा तालाबों व पुरानी नहरों का गहरीकरण व सौंदर्यीकरण का काम कराने में जुट गई है। इसके अतिरिक्त सरकार मनरेगा पशु बाड़ा निर्माण का कार्य भी तेज गति से पूरा कर रही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में रोजगार सेवक राजीव ने बताया कि मौजूदा योगी सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए अच्छे कदम उठाए हैं। अब गांवों में पुरानी परम्परा को जीवंत किया जा रहा है। ग्रामीण जीवन में तालाब और नहरों का बड़ा महत्व है, क्योंकि कृषि और पशुधन ग्रामीण क्षेणों का सबसे बड़ा व्यवसाय और जीवनयापन का जरिया है और इन्हें जीवित रखने के लिए पानी सबसे पहली जरूरत है। इसलिए सिंचाई और पशुओं के पीने के लिए, साथ ही बारिश के पानी का संचयन करने के लिए पानी एकत्र करने का सबसे अच्छा माध्यम तालाब ही होते हैं, जिनका पानी साल भर लोगों, पशुओं और कृषि के काम आता है। साथ ही नहरों के बनने से उनमें पानी रहेगा, जो किसानों के लिए बड़ी राहत प्रदान करेगा।

योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश के रोगियों को अच्छी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आयुष्मान योजना को उत्तम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। रोगियों को अच्छी चिकित्सा सुविधाएं देने के लिए योगी सरकार ने आयुष्मान योजना में जांच के बजट को भी बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस सुविधा के तहत रोगियों की एमआरआई पैट स्कैन तथा रेडियोलॉजिकल जांचों समेत कई महंगी जांचें भी निशुल्क की जाएंगी। एक निजी अस्पताल के डॉक्टर हरीश का कहना है कि सरकार रोगियों को सुविधाएं देगी ये तो अच्छी बात है, मगर इससे सरकारी अस्पतालों में रोगियों की भीड़ बढ़ेगी, जो कि पहले से ही बहुत अधिक रहती है। अगर सरकारी अस्पतालों से रोगियों की इस भीड़ को सरकार कम करना चाहती है, तो उसे चाहिए कि वो निजी अस्पतालों को भी काम सौंपे। इस प्रक्रिया में निजी अस्पताल जो भी स्वास्थ्य लाभ रोगियों को दें, उसका भुगतान सरकार सीधे अस्पतालों को कर दे। इससे सरकारी अस्पतालों में भी डॉक्टरों को आसानी होगी और निजी अस्पतालों में रोगियों को अच्छा स्वास्थ्य लाभ मिल जाएगा।

शिक्षा व्यवस्था ठीक करने के लिए प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार सरकारी स्कूलों की दशा सुधारेगी। इस बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक करके विचार मंथन कर लिया है। अब वे सरकारी स्कूलों के कायाकल्प के लिए भी जुट गए हैं तथा ऑपरेशन कायाकल्प के तहत स्कूलों को स्मार्ट बना रहे हैं। गौंटिया के प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक हरीश गंगवार ने बताया कि प्रदेश में विद्यालयों की दशा सुधरने के बारे में जानकर बहुत खुशी हुई। बच्चे तो देश का भविष्य होते हैं। सरकार वही अच्छी, जो बच्चों का भविष्य संवारे। इसके लिए मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने प्रदेश में दुर्दशा की हालत में पहुंचे विद्यालयों की दशा सुधारने का बीड़ा उठाया है।

विदित हो कि योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों का कायाकल्प करने जा रही है। इसके लिए योगी सरकार ने हर तरह की पूरी तैयारियां कर ली हैं। अब उप्र के सभी प्राथमिक विद्यालय देश के विद्यालयों की नाक होंगे, जिनमें बच्चों के लिए शिक्षा की उत्तम व्यवस्थाएं और अच्छी हालत की मेजें तथा बेंचें होंगी। हाल-फिलहाल में योगी सरकार लगभग 30 हजार माध्यमिक विद्यालयों के बुनियादी ढांचे का नवीनीकरण करने का विचार बना रही है। सरकारी सूत्रों की मानें तो सरकारी विद्यालयों में निजी विद्यालयों की तरह ही ऑडियो-वीडियो प्रोजेक्ट के साथ स्मार्ट क्लास रूम बनाए जाएंगे। कहा जा रहा है कि यह विद्यालय इतने अच्छे होंगे कि निजी और कान्वेंट विद्यालयों को टक्कर देंगे। क्योंकि अब सरकारी विद्यालयों में पुस्तकालय, कम्प्यूटर लैबोरेटरी, साइंस लैब, आर्ट रूम के अतिरिक्त वाईफाई की व्यवस्था भी होगी। इसके अतिरिक्त योगी सरकार बच्चों के लिए उत्तम शिक्षा देने की व्यवस्था भी करेगी। बताया जा रहा है कि कई विद्यालयों में तो खेल के मैदान भी बनाए जाएंगे। कई विद्यालयों का कायाकल्प हो भी चुका है।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

कुछ कर दिखाने की मंशा

विकास न करने के तमाम आरोपों के बाद भी दोबारा सत्ता में आने वाली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार मार्च में फिर बन चुकी है। अब उसके पास प्रदेश का विकास करने के लिए पूरे 5 साल हैं। यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार लोगों को खुश करना चाहते हैं और विपक्ष को ताना कसने का कोई अवसर नहीं देना चाहते। विदित हो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2019 में ऑपरेशन कायाकल्प का शुभारंभ किया था, जिसके तहत प्रदेश के लगभग 1.33 लाख परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले लगभग 1.64 लाख बच्चों को अत्यधिक आधुनिक परिवेश के साथ स्वच्छ, स्वास्थ्यवर्धक तथा सुरक्षित माहौल देने का प्रयास किया जा रहा है। इस योजना के तहत विद्यालयों का सौंदर्यीकरण तो होगा ही, उनमें बच्चों और अध्यापकों के लिए पीने योग्य पानी, साफ-सुथरे शौचालय, स्वच्छ और प्रसन्नचित वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा।

विरासत की जंग

चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच छिड़ी विरासत की जंग के बाद अब लालू प्रसाद यादव के घर में भी जंग शुरू हो गई है। तेज प्रताप यादव बगावत के मूड में नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप ने अपना सरकारी बंगला छोड़ दिया है। पहले दोनों भाई, मां राबड़ी देवी के साथ 10, सर्कुलर रोड पर ही रहते थे, लेकिन बाद में तेज प्रताप यादव अपने नए बंगले में शिफ्ट हो गए थे। शादी के बाद भी तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी राजश्री, राबड़ी देवी के साथ ही रह रहे हैं। अब तेज प्रताप यादव फिर से 10, सर्कुलर रोड यानी मां राबड़ी देवी के घर पर पहुंच गए हैं। मां के साथ रहने के फैसले के पीछे वो खास वजह भी बता रहे हैं। तेज प्रताप यादव का कहना है कि उनके खिलाफ उसी घर में साजिश रची जा रही है और इसीलिए वो मां के पास पहुंच गए हैं।

लेकिन उसी जगह को लेकर तेज प्रताप यादव पर बहुत बड़ा आरोप लगा है। आरोप भी उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के यूथ विंग के ही एक पदाधिकारी ने लगाया है। झगड़ा सुलझाने और इंसाफ दिलाने के लिए अब लालू यादव के जेल से छूटकर पटना पहुंचने का इंतजार हो रहा है। लालू यादव को हाल ही में चारा घोटाले के एक मामले में जमानत मिली है। तेज प्रताप पर युवा आरजेडी नेता ने इफ्तार पार्टी के दिन ही बंद कमरे में नंगा करके पीटने का इल्जाम लगाया है। मामला इतना गंभीर हो चला है कि दोनों भाइयों में तनाव गहरा हो चुका है। तेजस्वी यादव बड़े भाई की हरकत से बेहद खफा बताए जाते हैं। और तेज प्रताप यादव ने आरजेडी छोड़ देने का ही ऐलान कर दिया है। लालू यादव के परिवार का ये झगड़ा गंभीर तो पहले ही लगता था अब ये खतरनाक शक्ल अख्तियार करने लगा है।

वैसे अपनी तरफ से लालू यादव ने ऐसा इंतजाम कर रखा था कि दोनों भाइयों में झगड़े की नौबत ही नहीं आए। लालू यादव ने बहुत पहले ही तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में तो तेजस्वी यादव पार्टी के मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी रहे। अब नए सिरे से तेज प्रताप यादव ने जो बवाल शुरू किया है, वो लालू यादव के परिवार के लिए नई मुसीबत बन चुका है लालू यादव फिलहाल जेल में हैं और तेज प्रताप ने ऐसी हरकत कर दी है जिस पर तेजस्वी यादव के लिए स्टैंड लेना मुश्किल हो रहा है और आगे की राह ज्यादा ही खतरनाक दिखाई दे रही है। तेज प्रताप यादव पर लगे आरोपों को लेकर न तो तेजस्वी यादव को कुछ बोलते बन रहा है, न बिहार आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह को। मीडिया के पूछने पर तेजस्वी यादव मामले को ये कहकर इधर-उधर टालते नजर आए कि देखते हैं और देखेंगे।

जगदानंद सिंह ने तो हाथ ही खड़े कर दिए हैं। कहते हैं, मेरे हाथ मे कुछ नहीं है जिससे मैं कोई एक्शन ले सकूं। जगदानंद सिंह का कहना है, रामराज यादव से मैंने देखने की बात कही थी, लेकिन तेज प्रताप यादव पर एक्शन लूं, ये मेरे हाथ में नहीं है सबका मालिक जनता है और जनता सब फैसला करती है। जगदानंद सिंह की मजबूरी समझी जा सकती है। काफी दिनों से वो तेज प्रताप यादव के निशाने पर रहे हैं। एक बार तो हालत ये हो गई थी कि वो नाराज होकर घर ही बैठ गए थे। बाद में लालू प्रसाद को फोन करके मनाना पड़ा था। लेकिन तब दफ्तर आते ही जगदानंद सिंह ने तेज प्रताप यादव के करीबी आकाश यादव की छुट्टी कर दी। कामकाज संभालते ही जगदानंद सिंह ने गगन कुमार को युवा आरजेडी का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया था। जब तेज प्रताप ने शोर मचाना शुरू किया तो जगदानंद सिंह ने अध्यक्ष के अधिकारों का हवाला दिया और कहा कि उन्होंने किसी को हटाया ही नहीं, बल्कि खाली पड़े पद पर नियुक्ति की है।

तेज प्रताप ने अपनी तरफ से जगदानंद सिंह को हटाने के लिए मुहिम चलाई और शोर भी खूब मचाया, लेकिन जिसके रूठ जाने पर लालू यादव को मनाना पड़ा हो और जिसके साथ तेजस्वी खड़े हों, फिर तेज प्रताप कर भी क्या सकते हैं? कुछ ही दिनों बाद तेज प्रताप यादव ने नया शिगूफा छोड़ दिया। कहने लगे कि उनके पिता लालू यादव को बंधक बना लिया गया है। तेज प्रताप के इस आरोप के दायरे में तेजस्वी यादव के साथ मीसा भारती भी आ गईं क्योंकि लालू यादव तब उनके ही घर पर रहे थे। पहले देखा जाता रहा कि मीसा भारती हमेशा ही तेज प्रताप के पक्ष में खड़ी रहती थीं, लेकिन भाई की इस हरकत के बाद वो भी अपना हाथ पीछे खींच लीं। इफ्तार पार्टी वाले दिन मीसा भारती भी भाई तेजस्वी यादव के साथ काफी सक्रिय देखी गईं। लालू यादव के परिवार में वर्चस्व की ये लड़ाई अक्सर ही किसी न किसी रूप में देखने को मिलती रही है। पहले एक दावेदार मीसा भारती भी हुआ करती थीं, लेकिन तेजस्वी यादव के कद बढ़ते जाने के बाद वो संयम से काम लेने लगीं। बाद में काफी दिनों तक तेज प्रताप का भी सपोर्ट किया, लेकिन अब उस मामले में भी हाथ पीछे खींच लिया है।

● **विनोद बक्सरी**

परिवार की नयी मुश्किल काफी गंभीर है लालू

तेज प्रताप यादव पर नेताओं और कार्यकर्ताओं से दुर्व्यवहार के आरोप पहले भी लगते रहे हैं, लेकिन ये मामला ज्यादा ही गंभीर हो गया है। ये आरोप सिर्फ तेज प्रताप पर ही नहीं लगा है। दरअसल, राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर पार्टी के ही एक नेता ने बंद कमरे में नंगा करके पीटे जाने का आरोप लगाया है और ये तब हुआ है जब राबड़ी देवी के साथ-साथ तेजस्वी प्रताप भी अपने परिवार के साथ वहीं रह रहे हैं। लालू यादव के सामने पहली बार चुनौती तब सामने आई थी जब पप्पू यादव ने उनकी विरासत पर दावा ठोक दिया था। तब लालू यादव ने साफ किया था कि वारिस तो बेटा ही होगा क्योंकि बेटा वारिस नहीं होगा तो क्या भैंस चराएगा। लालू यादव ने विरासत छोटे बेटे को सौंप दी, लेकिन बड़ा बेटा उसे आज तक हजम नहीं कर पा रहा है। सुनने में आता है कि तेज प्रताप के करीबी सलाह दे देते हैं कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं तो पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी पर तो उनका ही हक बनता है और ये बात सुनकर वो खुश हो जाते हैं।

संकट में इमरान

हर बीतते दिन के साथ इमरान खान की मुसीबत में इजाफा

बहरहाल, इमरान की बातों में कितना सच है और कितना झूठ इसका जवाब वक्त देगा लेकिन जो वर्तमान है और जिस तरह का पाकिस्तान का इतिहास रहा है जब तक पाकिस्तान में शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री के रूप में सत्ता में काबिज हैं हर बीतते दिन के साथ इमरान की मुसीबत में इजाफा ही होगा और कोई न कोई बहाना करके उन्हें सलाखों के पीछे किया जाएगा। गौरतलब है कि पाकिस्तान में राजनीति बेहद घिनौनी है। यदि कल की तारीख में इमरान को कुछ हो जाता है तो हमें आश्चर्य में नहीं पड़ना चाहिए। पाकिस्तान की वही परंपरा है और व्यक्ति की राजनीति भी तब ही पूरी मानी जाती है।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान इन दिनों संकट के दौर से गुजर रहे हैं। सत्ता जाने के बाद से ही उनकी परेशानियां बढ़ गई हैं। शहबाज शरीफ के सत्ता संभालने के बाद पाकिस्तान में जारी सियासी नाटक इमरान खान की गिरफ्तारी की खबर के बाद अपने क्लाइमेक्स पर आ गया है। पूर्व प्रधानमंत्री और तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के मुखिया इमरान खान पर गंभीर आरोप लगे और वो सलाखों के पीछे जाएं, इसलिए रूलिंग पार्टी की तरफ से ईशनिंदा को हथियार बनाकर इमरान पर जाल फेंका गया है। हालांकि, पाकिस्तान में सियासी दुश्मनों को ठिकाने लगाने के लिए किसी भी हद तक चले जाने की परंपरा रही है। ऐसे इमरान खान के साथ जो भी हो रहा है, वह आश्चर्यजनक नहीं है।

चाहे वो मुल्क के प्रधानमंत्री रह चुके मुहम्मद जिया उल हक रहे हों या फिर नवाज शरीफ और अब इमरान खान, पाकिस्तान में प्रथा ही कुछ ऐसी है। जैसे ही दूसरा कोई सत्ता की कमान संभालता है पहले वाले को या तो जेल होती है या फिर उसे मार दिया जाता है। इमरान का भविष्य क्या होगा? पाकिस्तान में अपनी पॉलिटिकल इनिंग वो कितनी लंबी खेल पाते हैं? ये सभी सवाल अपनी जगह हैं लेकिन जिस बात का जिक्र होना चाहिए वो ये कि गिरफ्तारी की इस खबर ने इस बात की तस्दीख कर दी है और ये बता दिया है कि समय का चक्र सदैव अपनी गति से चलता है और एक समय वो भी आता है जब वो ठीक वहीं पहुचंता है जहां से शुरुआत हुई।

दरअसल, अभी बीते दिनों ही अपनी सऊदी अरब यात्रा पर गए पाकिस्तान के मौजूदा वजीर ए आजम शाहबाज शरीफ मदीना स्थित पवित्र मस्जिद-ए-नबवी में थे जहां उनके खिलाफ नारेबाजी हुई। आरोप इमरान खान और उनके समर्थकों पर लगे। अब जबकि मामले ने तूल पकड़ लिया, ये नारेबाजी इमरान को महंगी पड़ी है। फैसलाबाद में इमरान खान और उनके 5 साथियों पर मामला दर्ज किया है।

मामले पर अपना पक्ष रखते हुए पाकिस्तान के गृहमंत्री राणा सनाउल्लाह ने भी तमाम तरह की बड़ी बातें की हैं और मदीना और स्जिद-ए-नबवी को बड़ा मुद्दा बनाते हुए कहा है कि मदीना जैसी पवित्र इबादतगाह पर सियासी नारेबाजी करना ऐसा जुर्म है जिसे माफ नहीं किया जा सकता। मदीना जैसी पवित्र जगह पर हुई इस नारेबाजी से सिर्फ पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरान ही नहीं स्वयं सऊदी भी खूब नाराज है। बताया तो यहां तक जा रहा है कि सऊदी हुकूमत भी इस मामले पर सख्त कदम उठाने वाली है।

जिक्र इमरान के खिलाफ लिखे मुकदमे और उनके साथियों का हुआ है तो बता दें कि इमरान के अलावा फवाद चौधरी, शहबाज गिल, कासिम सूरी, शाहबजादा जहांगीर खान, अनील मुसर्रत और शेख रशीद का भी नाम एफआईआर में है। चूंकि पूरी बात अब ईशनिंदा पर आ गई है तो शहबाज सरकार भी इसे हलके में नहीं ले रही है। मदीना में नारेबाज कर सुर्खियां बटोरने वाले शेख रशीद को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर अरेस्ट कर लिया गया है। ध्यान रहे यदि आरोप साबित हो गए तो इमरान और उनके संगी साथियों दोनों को 5 से 8 साल की सजा हो सकती है साथ ही उन्हें मोटा जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

मामले के मद्देनजर एक वीडियो क्लिप इंटरनेट पर जंगल में लगी आग की तरह फैली है। यदि इस वीडियो क्लिप को देखें तो तीर्थयात्री जिन्हें कथित तौर पर इमरान खान का समर्थक बताया जा रहा है, जैसे ही शहबाज शरीफ और उनके प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्य मदीना स्थित मस्जिद ए नबवी पहुंचे उन्होंने चोर-चोर और गद्दार-गद्दार के नारे लगाने शुरू कर दिए। कहा ये भी जा रहा है कि पाकिस्तानी तीर्थयात्रियों ने प्रतिनिधिमंडल के खिलाफ कथित तौर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। वहीं मामले पर मदीना पुलिस भी सख्त नजर आई। पुलिस की तरफ से दावा किया गया है कि नारेबाजी में शामिल पांच पाकिस्तानियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

चूंकि इस मामले ने पाकिस्तान में एक बड़ी बहस का आगाज कर दिया है और विषय ईशनिंदा है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी सफाई दी है और अपने को बेकसूर बताया है। इमरान ने अपने को आरोपी तीर्थयात्रियों से दूर करते हुए कहा है कि, वो किसी को भी पवित्र स्थान (मस्जिद ए नबवी) पर नारे लगाने के लिए कहने की कल्पना भी नहीं कर सकते। उधर, पाकिस्तान के पूर्व गृहमंत्री और अवामी मुस्लिम लीग (एएमएल) के अध्यक्ष शेख रशीद अहमद ने चेतावनी दी कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो पाकिस्तान श्रीलंका में बदल जाएगा। अहमद ने कहा कि पीटीआई ने स्थिति से निपटने के लिए पहले ही रणनीति तैयार कर ली है, लेकिन अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है तो देश राजनीतिक संकट में फंस जाएगा और श्रीलंका जैसी स्थिति का गवाह बनेगा। वर्तमान में, श्रीलंका आजादी के बाद से सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, जिसमें भोजन और ईंधन की कमी, बढ़ती कीमतों और बड़ी संख्या में नागरिकों को प्रभावित करने वाली बिजली कटौती शामिल है।

● **ऋतेन्द्र माथुर**

यूक्रेन ने 'अकड़' छोड़ सबकुछ गंवाया

किस प्रकार राष्ट्राध्यक्ष जानबूझकर अपने देश को जलती आग में झोंक कर उसका अहित कर बैठते हैं, इसका सटीक उदाहरण रूस-यूक्रेन युद्ध को ध्यान में रखकर सोचा जा सकता है। दोनों देशों के बीच किस कारण से युद्ध की शुरुआत हुई और आज ढाई महीने बाद क्या स्थिति बन गई है, यह पूरी दुनिया के सामने है। नाटो देशों को रूस के विरुद्ध और यूक्रेन का साथ देने के लिए जिस प्रकार का अभियान अमेरिका ने चलाया, वह अब परवान चढ़ने लगा है।

इसी अमेरिकी बहकावे में आकर पोलैंड और बुल्गारिया रूस के विरुद्ध अभियान छेड़कर यूक्रेन को युद्ध के लिए हथियारों की सप्लाई करने लगे थे। परिणाम स्वरूप रूस ने प्राकृतिक गैस की आपूर्ति बंद कर दी है। चूंकि, इन दोनों देशों का तापमान प्राय: शून्य से नीचे रहता है, इसलिए इस गैस का उपयोग घर और फैक्ट्रियों के तापमान को नियंत्रित और सामान्य बनाए रखने के लिए किया जाता है। इसलिए प्राकृतिक गैस की आपूर्ति बंद होने के कारण अब ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि इन दोनों देशों की फैक्ट्रियों का कामकाज ठप होने के कगार पर है और ठंड से लोगों का जीना दुश्वार हो रहा है।

पता नहीं, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किस सोच के तहत, किस वजह से तथा किसके बहकावे में आकर रूस की सामरिक शक्ति को चुनौती दे दी, यह समझ से परे है। रही बात अमेरिका की, तो अपनी राजनीति करने और विश्व में अपनी शक्ति को साबित करने के लिए वह इसका एहसास सार्वजनिक रूप से कराता रहता है। उसकी शुरू से ही यही नीति रही है। लेकिन, छोटी सी बात पर रूस के विरुद्ध युद्ध में लोहा लेने वाला यूक्रेन भी शायद भूल गया कि ढाई महीने के युद्ध के बावजूद रूस की सामरिक शक्ति में अब भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई है, जबकि वह अब संयुक्त सोवियत संघ नहीं रहा है। अब तक सामान्य नागरिक और सैनिक कितने काल के गाल में समा गए हैं, इस पर दोनों देशों की गणना अलग-अलग है। किस देश को जान-माल का कितना नुकसान हुआ है, यह सच भी युद्धोपरांत ही विश्व को पता चल पाएगा। रूस-यूक्रेन के युद्ध दौरान अपनी तीन दिवसीय यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बर्लिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोर देकर कहा कि भारत शांति के पक्ष में है। यूक्रेन संकट के शुरुआत से भारत ने शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आव्हान किया था।

दरअसल, इन दोनों देशों के बीच इस भयंकर युद्ध का कारण क्या रहा है, इसे जानने की कोशिश करते हैं। फरवरी 2014 में शुरू हुआ यह एक निरंतर और लंबा संघर्ष है, जिसमें मुख्य रूप से एक तरफ रूस और उसकी समर्थक सेनाएं और दूसरी ओर यूक्रेन शामिल हैं। युद्ध क्रीमिया की स्थिति और डोनबास के कुछ हिस्सों पर केंद्रित है, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव विशेष रूप से वर्ष 2021 से 2022 तक भड़क उठा, जब यह स्पष्ट हो गया कि रूस, यूक्रेन पर सैन्य आक्रमण शुरू करना चाह रहा है।

फरवरी 2022 में संकट गहरा गया और रूस को वश में करने के लिए राजनयिक वार्ता विफल हो गई, इसकी परिणति रूस में 22 फरवरी को अलगाववादी नियंत्रित क्षेत्रों में सेना के स्थानांतरण के रूप में हुई। रूस और यूक्रेन की सेना के बीच राजधानी कीव ही नहीं, बल्कि और भी कई बड़े शहरों में कब्जे को लेकर जंग जारी है। यूक्रेन के बड़े शहरों में रूस की सेना लगातार मिसाइल हमले कर रही है। इसी बीच कीव पर कब्जे के लिए रूस ने अतिरिक्त सेना भी भेज दी है। यूक्रेन की राजधानी कीव सहित कई प्रमुख शहरों- कीव, खारकीव, लीव, चेरनीहिव, ओडेसा और मारियुपोल तबाह कर दिए गए हैं। इन शहरों पर हमलों का क्या असर हुआ है, इसे देखने के बाद ही महसूस किया जा सकता है। इन शहरों की बड़ी-बड़ी इमारतों, सरकारी दफ्तरों को इस तरह तहस-नहस कर दिया गया है कि फिर से उसे बसने और बनाने में वर्षों लग जाएंगे।

ताजा घटनाक्रम में बताया गया है कि यूक्रेन के बंदरगाह वाले शहर ओडेसा में अमेरिका और यूरोपीय देशों से आए हथियारों की खेप को रूसी मिसाइलों ने अपना निशाना बनाया, साथ ही शहर के हवाई अड्डे को भी नष्ट कर दिया है। आगे युद्ध की विभीषिका कैसी होगी इसका अनुमान इससे भी लगाया जा सकता है कि पोलैंड में नाटो के 18 हजार सैनिकों ने युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। अभ्यास कर रहे सैनिक पूर्वी यूरोप के कई देशों से यहां आए हुए हैं। यूक्रेन युद्ध के चलते इस युद्धाभ्यास को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अमेरिका, भारत तथा नाटो सहित विश्व के कई देशों को इस बात के लिए धमका चुका है कि वह रूस को किसी भी तरह की सहायता देने से बाज आए। भारत से भी अमेरिका यही चाहता है, लेकिन भारत अपनी रूसी दोस्ती के प्रति प्रतिबद्ध है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से इसका जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से करके बता भी दिया है।

● **कुमार विनोद**

बुरे फंसे पुतिन

फिनलैंड और स्वीडन की जल्द से जल्द नाटो सदस्यता के लिए आवेदन करने की घोषणा इस बात का सबूत है कि यूक्रेन युद्ध ने यूरोपीय देशों की मनोदशा को बहुत गहरा प्रभावित किया है। ध्यान रहे रूस के पड़ोस में स्थित इन दोनों देशों ने शीत युद्ध के लंबे चले दौर में भी अपनी तटस्थता बनाए रखी थी। वजह यह भी हो सकती है कि वे पड़ोस की महाशक्ति को नाराज नहीं करना चाहते थे। मगर बदले हालात में अब ऐसा लगता है कि सुरक्षा की चिंता रूस की संभावित नाराजगी पर भारी पड़ गई है। खासकर फिनलैंड की तो 1300 किलोमीटर लंबी सीमा रूस के साथ लगती है। वहां सरकार पर जनमत का भी जबर्दस्त दबाव है। पिछले सप्ताह हुए एक ओपिनियन पोल के मुताबिक 76 फीसदी लोग नाटो की सदस्यता लेने के पक्ष में हैं। सिर्फ 12 फीसदी लोगों ने इसका विरोध किया। हालांकि दोनों देशों ने अभी तक इस फैसले की औपचारिक घोषणा नहीं की है। लेकिन न केवल दोनों देश अपनी मंशा जता चुके हैं बल्कि नाटो के सेक्रेटरी जनरल भी कह चुके हैं कि इन दोनों के आवेदन पर जल्द ही पॉजिटिव फैसला लिया जाएगा। अमेरिका भी इसके पक्ष में है। ऐसे में तय माना जा रहा है कि जल्द ही ये दोनों देश नाटो के सदस्य बन जाएंगे। यह रूस के प्रभाव क्षेत्र में नाटो के विस्तार का अगला चरण है, जिसे रूस हर कीमत पर रोकने की बात करता रहा है। यूक्रेन पर हमले के पीछे भी उसकी यही आशंका रही है कि नाटो उसके पड़ोस के देशों तक पहुंचना चाहता है।

हाउसवाइफ को वीकली ऑफ लेने का हक है या नहीं?

कल्पना कीजिए, घर की महिलाएं एक दिन किचन से छुट्टी ले लें तो...और मदर्स दे पर सोशिल मीडिया पर प्यार लुटाने वाले बच्चे उनके हिस्से का काम करें तो? पत्नियों को उनके पति एक दिन आराम करने का ऑफर दें तो? अब कल्पना से बाहर आकर, हकीकत में इसे फॉलो करने का वक्त आ गया है। असल में, हम ऑफिस में काम करते हैं तो हमें वीकली ऑफ मिलता है। किसी दिन तबियत खराब हो जाने पर हमें छुट्टी भी मिल जाती है, लेकिन गृहिणी की कभी छुट्टी नहीं होती, उनका कभी ऑफ नहीं होता।

मां को तो हमने महान होने की उपाधि देकर हमेशा के लिए ऑन ड्यूटी पर लगा दिया। वो ठहरी ममता की मूरत, तो अब वे यह कैसे कह सकती हैं कि आज उनका काम करने का मन नहीं कर रहा है। वह तो बीमार होने के बाद भी रसोई में बच्चों के लिए रोटी बनाती दिख जाएगी, बच्चे इस तस्वीर को बड़े गर्व के साथ सोशल मीडिया पर शेयर भी कर देते हैं। वे कैप्शन देते हैं मां का प्यार... अरे तो बच्चे कब मां की तरह बनेंगे, क्या उन्हें बीमार मां से काम करवाना चाहिए? क्या वे अपने लिए एक दिन रोटी नहीं बना सकते या चावल नहीं खा सकते?

संडे के दिन ऑफिस जाने वाले छुट्टी पर होते हैं। वे आराम करते हैं और हाउसवाइफ उनके आराम का पूरा ध्यान रखती हैं। बाहर काम करने वालों के लिए संडे का दिन स्पेशल होता है। उस दिन वे देर से सोकर उठते हैं, उनके लिए स्पेशल नाश्ता बनता है। लंच भी खास होता है और रात का खाना भी लजीज होता है। दोस्त और रिश्तेदार आ गए तो उनकी खातिरदारी की जिम्मेदारी भी गृहिणी के ऊपर ही होती है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि बाहर काम करने वाले को आराम नहीं करना चाहिए।

वहीं घर की महिला को किसी दिन जब बाहर जाना होगा तो सबसे पहले उसे यह चिंता सताएगी कि सब काम जल्दी-जल्दी खत्म करना है। वह दोपहर का खाना बनाकार जाएगी और शाम के खाने की तैयारी करके जाएगी। वहीं उसे शाम को जल्दी घर आने की टेंशन भी लगी रहेगी, क्योंकि अगर वह लेट हुई तो शाम की चाय और डिनर का क्या होगा? इस तरह वे बाहर जाकर भी एंजॉय नहीं कर पाती हैं।

हम तो बस यह पूछ रहे हैं कि क्या हाउसवाइफ को हफ्ते में एक दिन भी आराम करने का हक नहीं? घरवाले तो यही समझते हैं कि वह महिला है, उसने पुरुष से शादी की है। वह पत्नी, बहू और मां है इसलिए उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वह सुबह जल्दी उठकर रसोई संभाल ले और सबका ख्याल रखे। तो क्या सभी घरावालों को मिलकर उसके आराम के बारे में नहीं सोचना चाहिए? कहना आसान है कि घर में काम ही क्या है? जवाब चाहिए तो एक दिन गृहिणी का किरदार निभाकर देखें।

सोचिए, क्या होगा अगर वह एक दिन वह देर से सोकर उठें? क्या हुआ कि किसी दिन उसका किचन में काम करने का मन न करे। क्या हुआ कि किसी दिन वह भी बेड पर लेटी रहे। कोई उसे चाय बनाकर दे दे, कोई नाश्ता बना दे और कोई खाने की तैयारी कर दे। कोई उसे कह दे कि आज तुम किचन में कदम मत रखना क्योंकि आज तुम्हारी छुट्टी है। यहां तो जब सोकर जगो तो मां या पत्नी किचन में मिलती है। पिता और पति को जैसे देर तक सोने का अधिकार विरासत में मिला है। स्कूल से घर आने पर हम मां-मम्मी करते किचन की तरफ ही भागते थे, क्योंकि पता है कि मां वहीं मिलेगी। असल में हमें गृहिणियों को किचन में देखने की आदत है। तभी को जब कोई त्योहार पड़ता है तो सभी लोग त्योहार मनाते हैं और घर की महिला रसोई में ही रह जाती है। हमने ईद और होली दोनों त्योहारों में अलग-अलग घरों में मां और पत्नी को किचन में ही देखा है।

कहा जाता है कि घर की महिला मां अन्नपूर्णा का रूप है। क्या कभी हमने उस अन्नपूर्णा को हमारा पेट भरने के लिए धन्यवाद कहा है? हम तो उसके बनाए खाने में मीन-मेक निकालते रहते हैं। हमें हर दिन खाने में कुछ नया स्वाद चाहिए होता है और वह हर दिन हमारे लिए नए-नए व्यंजन बनाने की कोशिश करती रहती है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि जब वह कहे आज मेरा काम करने का मन नहीं है तो आप इस बात को सामान्य रूप में लें। आपको नहीं लगता है कि हफ्ते में एक छुट्टी लेने का अधिकार तो उसका भी बनता है?

● **ज्योत्सना अनूप यादव**

अकेली महिला खुली तिजोरी की चाबी नहीं है

दरअसल, हमारे समाज में कई लोग महिलाओं को हमेशा कमजोर माना गया है। तभी तो औरतों को लेकर ऐसी मुहावरें प्रचलित हैं कि अकेली महिला तो लोगों के लिए खुली तिजोरी के समान होती है। किसी महिला के साथ कोई पुरुष नहीं है मतलब उसके साथ कुछ भी किया जा सकता है। कई लोगों के मन में यह धारणा है कि जो महिला अपनी सुरक्षा के लिए पुरुषों पर आश्रित रहती है वह भला अकेले अपनी बेटी की रक्षा कैसे करेगी? पुरुष भले बुजुर्ग हो, लेकिन अगर वह दरवाजे पर रहता है तो लोग कहते हैं कि वहां की महिलाएं अकेली नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि महिलाएं अकेले जी नहीं सकतीं, बच्चे नहीं पाल सकतीं लेकिन पुरुष समाज की सोच रखने वाले लोगों को लगता है कि अकेली महिला अबला होती है और उसे आसानी या जबरदस्ती से हासिल किया जा सकता है। वहीं समाज के लोग उस पर लांक्षन लगाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। वह भले ही काम करके देर रात घर आए, लेकिन लोग उसे जज करने में जरा भी देरी नहीं करते। उसे किसी से बात करता देखा नहीं कि तुरंत उसके चरित्र पर उंगली उठा देते हैं।

सभी कर्म यज्ञ हैं

गीता के अनुसार जो कर्म निष्काम भाव से ईश्वर के लिए जाते हैं वे बंधन नहीं उत्पन्न करते। वे मोक्षरूप परमपद की प्राप्ति में सहायक होते हैं। इस प्रकार कर्मफल तथा आसक्ति से रहित होकर ईश्वर के लिए कर्म करना वास्तविक रूप से कर्मयोग है और इसका अनुसरण करने से मनुष्य को अभ्युदय तथा नि:श्रेयस की प्राप्ति होती है। गीता के अनुसार सभी कर्म यज्ञ हैं। जीवन में श्रद्धा की महत्ता है। इससे अवसाद नहीं होता। गीता में स्वाध्याय महान तप है। कर्तव्य भावना से युक्त प्रतिफल न पाने की आशा में सुप्राप्य को दिया गया सहयोग सात्विक है। गीता में वैज्ञानिक विवेक है। सार-असार और संसार को समझने वाली बुद्धि है। वेदांत और व्यवस्थित योग दर्शन है। प्रेम परिपूर्ण भक्ति है। भरा-पूरा भौतिकवाद है। कर्म सिद्धि के सूत्र हैं। श्रीकृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सांख्य के अनुसार कर्म की सिद्धि के 5 कारण अधिष्ठान, कर्ता, साधन, प्रयास और दैव हैं। पांचवां कारण दैव है। यह ईश्वर या विधाता नहीं है। समस्त ब्रह्मांडीय शक्तियों की अनुकूलता या प्रतिकूलता दैव है। गीता में उसकी मान्यताओं के मानने पर जबरदस्ती नहीं। सारा जोर जानने पर है। रिलीजन, मजहब का जोर विश्वासी होने पर है। अविश्वासी दंडनीय है। ऐसे में गीता की तुलना रिलीजन या मजहब से नहीं हो सकती।

तुलना बराबर वालों के बीच होती है। गीता, बाइबल और कुरान समतुल्य नहीं है, लेकिन कर्नाटक में गीता और बाइबल की तुलना राष्ट्रीय चर्चा में है। राज्य के एक स्कूल ने अभिभावकों से कहा है, 'आप सुनिश्चित करें कि आपका बच्चा सभी अवसरों पर उपस्थित रहेगा और साथ में बाइबिल रखने पर आपत्ति नहीं करेगा।' हिंदू जनजागृति मंच ने इसका विरोध किया है। आर्चबिशप ने इसका खंडन किया है। उक्त स्कूल ईसाई अल्पसंख्यक सुविधा के अंतर्गत संचालित है। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा है कि धार्मिक पाठ शैक्षिक पाठ्यक्रम का भाग नहीं हो सकते। उनसे गीता के बारे में पूछा गया। उन्होंने कहा, 'गीता सामाजिक मूल्यों व उत्कृष्ट जीवन का संदेश देती है। गीता में धार्मिक कर्मकांड नहीं है, जबकि बाइबल कहती है कि ईसाई होने के लिए बाइबल पर विश्वास जरूरी है। गीता में ऐसे कथन नहीं हैं।' गीता कोई निर्देश नहीं देती। गीता में श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा, 'मैंने सभी रहस्यों वाला ज्ञान दिया है। इस पर गहन विचार करो और जैसी इच्छा हो, वैसा करो।' यहां कोई आज्ञा नहीं। पूर्ण कर्म स्वतंत्रता है।

धर्म, रिलीजन, पंथ और मजहब एक नहीं। पंथ, मजहब और रिलीजन विश्वास हैं। सबके एक-एक देवदूत हैं और सबके एक-एक पवित्र ग्रंथ हैं। उनके कथन मानना अनिवार्य है। न मानने पर दंड की व्यवस्था है। उनकी मान्यताओं पर तर्क नहीं होते। धर्म भारतीय जीवनशैली की आचार संहिता है। यह किसी देवदूत की उद्घोषणा नहीं है। धर्म का न एक आस्था ग्रंथ है और न एक देवदूत। इसका सतत् विकास हुआ है। वैदिककाल में पूर्वजों ने प्रकृति की शक्तियों में नियमबद्धता देखी थी। जल प्रवाह ऊपर से नीचे प्रवाहमान है और अग्नि नीचे से ऊपर। वसंत, हेमंत, शिशिर और मेघ नियमबद्ध हैं। पूर्वजों ने प्रकृति के इस संविधान को 'ऋत' कहा। ऋग्वेद के वरुण, धर्म-अनुशासन के देवता हैं। धरती आकाश इन्हीं के नियमों से धारण किए गए हैं-वरुणस्य धर्मणा। प्राकृतिक नियम धारण करना धर्म है। वैदिक साहित्य में ऋत और धर्म पर्यायवाची हैं। ऋत कर्म बनता है, तब धर्म बनता है। प्रकृति की सभी शक्तियां ऋत का पालन करती हैं। मनुष्य का आचरण भी नियमबद्ध होना चाहिए। ऋत सत्य है। सत्य का अनुसरण धर्म है। कालक्रम में धर्म में बहुत कुछ जुड़ता रहा। धर्म जड़ नहीं। गतिशील आचार संहिता है।

धर्म में आस्था और विश्वास से भी संवाद की परंपरा है। परंपरा वैदिक ऋषियों ने दी। उत्तर वैदिक काल में नई परंपराएं जुड़ीं। आस्था और धर्म से संवाद जारी रहा। गीता आस्था और विश्वास से संवाद का ग्रंथ है। गीता के चौथे अध्याय में प्राचीन ज्ञान परंपरा का उल्लेख है। श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा कि 'प्राचीन काल में मैंने यह ज्ञान सूर्य को दिया था, लेकिन कालक्रम में यह ज्ञान नष्ट हो गया।' वह कहते हैं कि जब धर्म का पराभव होता है, तब अव्यवस्था आती है और धर्म की स्थापना के लिए ही मैं बार-बार प्रकट होता हूं। गीता में ज्ञान योग है, कर्म योग है। संसार को सुंदर बनाने की अभिलाषा है। महाभारत युद्ध में परिजनों को युद्ध तत्पर देखकर अर्जुन को विषाद हुआ। वह पलायन को कर्तव्य समझ रहा था। कर्म विमुख हो रहा था। सो गीता में अर्जुन के प्रश्न हैं। जीवन की समस्याओं के समाधान हैं। मार्क्सवादी डीडी कोसांबी ने लिखा, 'क्या कोई संस्कृत कृति नहीं थी, जिसने भारतीय चरित्र को उसी प्रकार आकारित किया, जिस प्रकार सर्वतीज डान क्विजोत ने स्पेनी विद्वानों को प्रभावित किया है। एक पुस्तक काफी हद तक इसी कोटि की है। वह गीता है।' बंगाल में चार्ल्स विल्किंस ने गीता का अनुवाद किया। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने प्रशंसा की। जर्मन भाष्यकार जेडब्ल्यू होवर ने लिखा, 'यह सब कालों में सब प्रकार के सार्वजनिक जीवन के लिए प्रामाणिक है।'

असल में सारी कठिनाइयां एक से अनेक धर्म मानने की हैं। लोग हिंदू, इस्लाम और ईसाइयत को धर्म कहते हैं। ईसाई और इस्लाम धर्म नहीं हैं। धर्म एक है। स्वयंपूर्ण है। प्राकृतिक है। सतत् विकासशील है। अंधविश्वास से मुक्त है। गांधीजी परिपूर्ण धार्मिक थे। उन्होंने धार्मिक आदर्शों के अनुरूप 'ईश्वर अल्लाह तेरे नाम' कहा था, लेकिन इस्लाम अल्लाह के अलावा किसी को ईश्वर नहीं मानता। गांधी जी की बात इस्लाम अनुयायी नहीं मान पाए। भारतीय राजनीति में भी सभी धर्म समान कहे जाते हैं, परंतु वास्तविकता यह नहीं है। धर्म एक है और वह अन्य पंथों से तुलनीय नहीं है। गीता निष्काम कर्म योग का ग्रंथ है। गीता में ऋग्वेद के विराट पुरुष का विश्वरूप है। उसमें सबके लिए उपयोगी विषयों का भी विवेचन है। ज्ञान और बुद्धि की प्रतिष्ठा है। आहार के गुणधर्म की अर्थपूर्ण चर्चा है।

● ओम

संतुष्टि

एक लगभग 12-13 साल का बच्चा अपने घर के पास एक दुकान में गया और दुकानदार से बोला- अंकल, क्या मैं एक फोन कर सकता हूं? दुकानदार ने सहमति जताई, तो वह बच्चा फोन के पास गया और उसने एक नंबर डायल किया, उधर से एक महिला की आवाज आई।

दुकानदार ध्यान से उस बच्चे की बात सुनने लगा। बच्चे ने पूछा- मैडम, मुझे पता चला है कि आप अपने बगीचे की देखभाल के लिए कोई आदमी ढूंढ रही है, मैं आपके बगीचे में काम करना चाहता हूं, क्या आप मुझे मौका देंगी? महिला ने जवाब दिया नहीं मैंने कुछ समय पहले एक लड़के को रख लिया है, अब मुझे किसी नए आदमी की कोई जरूरत नहीं।

बच्चे ने कहा, मैडम यदि आप मुझे मौका दें तो मैं उस लड़के को दी जाने वाली सैलरी से आधी सैलरी पर काम कर सकता हूं। महिला ने जवाब दिया- नहीं, मैं उस लड़के के काम से बहुत संतुष्ट हूं और अब कोई आदमी बदलना नहीं चाहती।

बच्चे ने फिर कहा, मैडम, मैं उसी वेतन में आपके बगीचे के चारों तरफ के रास्ते को भी साफ कर दिया करूंगा। महिला ने उत्तर दिया- नहीं, मुझे कोई नया आदमी नहीं चाहिए, धन्यवाद। इतना कहकर महिला ने फोन रख दिया।

बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई लेकिन दुकानदार को उस बच्चे पर जैसे दया सी आई। दुकानदार ने कहा- बच्चे मैं तुम्हारी बात ध्यान से सुन रहा था, मैं तुम्हारी बात से बहुत प्रभावित हुआ। तुम्हें काम की तलाश है और मुझे तुम्हारे जैसे आदमी की ही तलाश थी, मैं तुमको अपनी दुकान पर काम देता दूं।

बच्चे ने कहा, नहीं अंकल, मुझे कोई नौकरी नहीं चाहिए। दरअसल, मैं ही वह लड़का हूं, जो उस महिला के यहां काम करता है। मैं तो केवल यह देखना चाहता था कि क्या वह मेरे काम से संतुष्ट है या नहीं, मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता हो रही कि वह मैडम मेरा काम पसंद कर रही हैं। दुकानदार उस बच्चे की बात सुन कर दंग रह गया।

- अनाम

आघात कितना भी गहरा हो

तुमने भले ही ठगा हो हमको,
हम बदले में ठगी न करते।
आघात कितना भी गहरा हो,
हम रिश्तों में बदी न करते।।
तुमने भले ही हमें फंसाया।
हमने तुम पर प्यार लुटाया।
नहीं उजाड़ा कभी किसी को,
प्रेमी संग है तुम्हें बसाया।
अपने बंधन काट रहे हम,
तुमसे कोई हंसी न करते।
आघात कितना भी गहरा हो,
हम रिश्तों में बदी न करते।।
धोखे से नहीं रिश्ते बनते।
कानूनों से विश्वास न पलते।
विश्वासघात कर प्रेम चाहतीं,
तलवारों से पुष्प न खिलते।
जिसकी थीं, उसको ही सौंपी,
किसी की चीज कभी न हरते।
आघात कितना भी गहरा हो,
हम रिश्तों में बदी न करते।।
समय बहुत अब बीत गया है।
हमारा नहीं कोई मीत भया है।
तुम्हारी चोट थी इतनी गहरी,
धोखा तुम्हारा जीत गया है।
कपट-कपट का मित्र न होता,
कपटी से भी कपट न करते।
आघात कितना भी गहरा हो,
हम रिश्तों में बदी न करते।।

- डॉ. संतोष गौड़

प्रौढ़ बालक

परिस्थितियों का मारा रतन बाल्यावस्था से तरुणावस्था और युवावस्था के बजाय सीधे प्रौढ़ावस्था में कदम रखने को विवश था।

पिता और मां के बीच टकराव और एक-दूसरे को नीचा दिखाने की जिद ने परिवार का माहौल बिगाड़ दिया। जिस समय उसे मां की ममता और पिता का प्यार मिलना चाहिए, उस समय उसे उपेक्षा संग जीने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा था।

पिता की अकर्मण्यता और असंवेदनशील कार्यशैली में अब तो मां-बेटे की जान को भी खतरा सा महसूस होने लगा।

आखिर में रतन ने मां के साथ घर छोड़ना ही उचित समझा और समय, परिस्थिति के अनुसार मां के साथ खुद के भविष्य का ताना-बाना बुनते और सपनों को पूरा करने की ख्वाहिशों ने उसे समय से बहुत पहले ही प्रौढ़ ही नहीं जिम्मेदार भी बना दिया।

आज रतन के लिए पिता का कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि पिता का दायित्व उसने अपने कंधों पर जो रख लिया था। समय पूर्व प्रौढ़ जो बनने लिए विवश हो गया था।

- सुधीर श्रीवास्तव

आईपीएल के फ्लॉप स्टार

किसी प्रोफेशनल शिक्षण कोर्स की तरह इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) दुनियाभर के क्रिकेटरों के लिए आवश्यक हो गया है। वे क्रिकेट खिलाड़ी जो टी-20 क्रिकेट के सफेद गेंद वाले फॉर्मेट में एलीट खिलाड़ी का दर्जा हासिल करना चाहते हैं उनकी भी यह चाहत होती है कि वे आईपीएल खेलें। ऐसा आखिर क्यों न हो क्योंकि इसकी नीलामी में खिलाड़ियों के लिए करोड़ों रुपए की बोली लगती है। इन्सेंटिव और दुनिया के श्रेष्ठ खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिलता है सो अलग। वर्ष 2008 में आईपीएल की शुरुआत के बाद इसका लगातार विस्तार होता जा रहा है। यह विस्तार सिर्फ टीम की संख्या के मामले में नहीं बल्कि पैसे के मामले में भी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने मौजूदा सत्र में दो नई टीमें जोड़ी हैं, जिससे उसे 12,715 करोड़ रुपए मिले। यह बताता है कि क्रिकेट का यह टूर्नामेंट कितना 'अमीर' हो गया है।

बीसीसीआई को अधिक पैसे मिलने का मतलब है कि फ्रेंचाइजी टीमों को पुरस्कार के रूप में अधिक राशि मिलेगी। इससे फ्रेंचाइजी के मालिक अपनी पसंद के क्रिकेटर की सेवाएं लेने के लिए ज्यादा खर्च कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करते वक्त कई बार वे क्रिकेटर के मौजूदा स्टेटस पर ध्यान नहीं देते। इसका नतीजा यह होता है कि कई मौकों पर उन्हें हताशा में अपने नाखून चबाने पड़ते हैं। 2015 में युवराज सिंह से लेकर 2020 में क्रिस मॉरिस और मौजूदा सत्र में ईशान किशन तक, खिलाड़ी अपनी भारी-भरकम कीमत के टैग के बोझ तले दब गए। यहां हम कुछ ऐसे ही आईपीएल के करोड़पति खिलाड़ियों के बारे में चर्चा करेंगे जिनका प्रदर्शन फ्लॉप रहा। शुरुआत आईपीएल के 2022 के मौजूदा सीजन से करते हैं।

इस साल आईपीएल की नीलामी में ईशान किशन पर काफी पैसा लगा लेकिन उनके फॉर्म ने इस पर सवाल उठा दिए हैं। ईशान ने शुरुआती दो मैचों में 81 नॉट आउट और 54 रन बनाए, लेकिन उसके बाद उनका स्कोर 14, 26, 3, 13 और 0 रहा। इससे सवाल उठने लगे हैं कि इस बल्लेबाज पर क्या 15.25 करोड़ रुपए की कीमत का टैग भारी पड़ रहा है। दिल्ली कैपिटल्स के सहायक कोच शेन वाटसन ने यह कहकर आलोचना की, कि वे निश्चित रूप से काफी प्रतिभाशाली और कुशल खिलाड़ी हैं, लेकिन इतने भी नहीं कि आप पूरा वेतन एक ही खिलाड़ी को दे दें।

5 बार की आईपीएल विजेता टीम के कप्तान के नाम इस टूर्नामेंट में 5,500 रन हैं। लेकिन 2022 के सीजन में रोहित शर्मा का फॉर्म खराब चल रहा है। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पहले मैच में 41 रन बनाने के बाद उन्होंने क्रमश: 10, 3, 26, 28, 6 और 0 का स्कोर किया है। इसका नतीजा टीम को भुगतना पड़ा है। 24 अप्रैल तक मुंबई इंडियंस ने 8 मैच खेले और एक भी जीत दर्ज नहीं कर सकी। रोचक बात है कि पिछले साल भारतीय टीम का पूर्णकालिक कप्तान नियुक्त किए जाने के बाद रोहित ने विभिन्न फॉर्मेट में खेले गए सभी 14 मैच जीते। आईपीएल 2022 में उनका प्रदर्शन इतना निराशाजनक है कि इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने टिप्पणी की, 'रोहित भारतीय टीम की कप्तानी का इस्तेमाल अपना भरोसा बढ़ाने और खेल को नई ऊंचाई पर ले जाने में नाकाम रहे।'

पिछले साल यूएई में खेले गए आईपीएल से पहले वेंकटेश अय्यर का नाम बहुत कम लोगों ने सुना था। लेकिन उस टूर्नामेंट में विश्वस्तरीय गेंदबाजी आक्रमण को उन्होंने जिस तरह खेला उसकी काफी सराहना हुई। उन्होंने 10 मैच में 370 रन बनाए थे जिसकी बदौलत उन्हें भारतीय टीम में जगह मिली और दो बार की आईपीएल चैंपियन केकेआर ने 8 करोड़ रुपए देकर उन्हें रिटेन किया। लेकिन इंदौर के इस खिलाड़ी ने आईपीएल के मौजूदा सीजन में 7 मैचों में सिर्फ 109 रन बनाए। 4 बार तो वे पावरप्ले के दौरान ही आउट हो गए। मुंबई इंडियंस के खिलाफ 50 नॉट आउट को छोड़ दें तो बाकी 6 मैचों में 20 रनों का आंकड़ा भी नहीं पार कर सके।

वेंकटेश अय्यर की तरह ऋतुराज गायकवाड़ भी आईपीएल के 2021 के सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स की बैटिंग की रीढ़ साबित हुए। पिछले साल सबसे अधिक रन बनाने वाले गायकवाड़ को ऑरेंज कैप मिला था। इसलिए 2022 के सीजन में सीएसके मैनेजमेंट के लिए उन्हें रिटेन करना लाजिमी था। लेकिन सबको निराश करते हुए मप्र के दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने अभी तक 7 मैचों में सिर्फ 108 रन बनाए हैं। गुजरात टाइटंस के खिलाफ 73 रन को छोड़ दें तो ऋतुराज का बाकी मैचों में स्कोर 0, 1, 1, 16, 17 और 0 रहा है।

अगर आप आरसीबी के फैन हैं तो आप निश्चित रूप से भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली के आईपीएल 2022 के प्रदर्शन को यथाशीघ्र भुला देना चाहेंगे। टीम ने उन्हें 15 करोड़ रुपए में रिटेन किया लेकिन रनों से रूठे कोहली के बल्ले ने सबको निराश किया है। आधुनिक क्रिकेट के महान खिलाड़ियों में कोहली ने 8 मैचों में कुल मिलाकर सिर्फ 119 रन बनाए हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ लगातार दो पारियों में वह शून्य पर आउट हुए।

● आशीष नेमा

5 साल की उम्र से संगीत सीखने लगे थे संतूर वादक पंडित शिवकुमार शर्मा

मशहूर संतूर वादक पंडित शिवकुमार शर्मा का हाल ही में मुंबई में कार्डियक अरेस्ट के चलते निधन हो गया है। पंडित शिवकुमार की उम्र 84 साल थी और वह किडनी से रिलेटेड बीमारी से जूझ रहे थे। वह पिछले छह महीने से डायलिसिस पर थे। पं. शिवकुमार शर्मा का जन्म 13 जनवरी 1938 को जम्मू में हुआ था। उनके पिता पं. उमादत्त शर्मा भी जाने-माने गायक थे, संगीत उनके खून में ही था। पांच साल की उम्र में पं. शर्मा की संगीत शिक्षा शुरू हो गई। पिता ने उन्हें सुर साधना और तबला दोनों की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी थी। 13 साल की उम्र में उन्होंने संतूर सीखना शुरू किया। संतूर जम्मू-कश्मीर का लोक वाद्ययंत्र था, जिसे इंटरनेशनल फेम दिलाने का श्रेय पं. शिवकुमार को ही जाता है।

1955 में महज 17 साल की उम्र में पं. शिवकुमार शर्मा ने मुंबई में संतूर वादन का अपना पहला शो किया। इसके बाद उन्होंने संतूर के तारों से दुनिया को संगीत की एक नई आवाज से वाकिफ कराया। क्लासिकल संगीत में उनका साथ देने आए बांसुरी वादक पं. हरिप्रसाद चौरसिया। दोनों ने 1967 से साथ में काम करना शुरू किया और शिव-हरि के नाम से जोड़ी बनाई।

...जब पिता के कहने पर 9 साल फिल्मों से दूर रहे महेश बाबू

साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सबसे कामयाब एक्टर में से एक महेश बाबू अपने बयान के चलते सुर्खियों में आ गए हैं। मेजर के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में महेश ने कहा, ऐसा नहीं है कि मुझे ऑफर्स नहीं मिले, लेकिन मुझे लगता है कि वो लोग मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं हिंदी में काम करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता, जो मुझे अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर दिया महेश का ये बयान बहस की आग में घी जैसा साबित हो रहा है।

ये वही महेश हैं जिनकी पत्नी नमृता शिरोडकर बॉलीवुड फिल्मों से देशभर में पहचान हासिल कर चुकी हैं। वहीं पिछले कुछ सालों से महेश के बॉलीवुड डेब्यू की खबरें भी सुर्खियों में रहती हैं। महेश फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े खानदान से ताल्लुक रखते हैं, जिसके चलते उन्होंने महज 4 साल की उम्र में ही एक्टिंग शुरू कर दी थी। आज महेश साउथ इंडस्ट्री के सबसे कामयाब और पॉपुलर एक्टर्स में से एक हैं। महेश बाबू का जन्म 9 अगस्त 1975 में तेलुगू एक्टर

घटामानेनी सिवा रामा कृष्णा के घर चेन्नई में हुआ था। फिल्मी खानदान से होने पर महेश को महज 4 साल की उम्र में नीड़ा फिल्म में काम करने का मौका मिला। दरअसल महेश अपने पिता के साथ नीड़ा फिल्म के सेट पर पहुंचे थे, लेकिन जब डायरेक्टर दसारी नारायण राव ने उन्हें देखा तो उन्हें फिल्म में हिस्सा दे दिया। जब महेश ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मों में काम करना शुरू किया तो उन्हें लगातार बड़ी फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। लेकिन इनके पिता चाहते थे कि वो फुल टाइम एक्टिंग करने की बजाए पढ़ाई में ध्यान दें। महेश पिता की बात से राजी हो गए और उन्होंने 9 सालों तक किसी फिल्म में काम नहीं किया।

कभी बोर्डिंग स्कूल में थे, फिर राउडी राठौर से रातोंरात स्टार बने विजय

साउथ इंडियन सिनेमा के राउडी यानी विजय देवरकोंडा की एक्टिंग और लुक्स से यूथ सेंसेशन बने रहते हैं। 2019 में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले साउथ इंडियन एक्टर हैं। विजय ने कई फिल्मों में काम किया है। उनकी फिल्म अर्जुन रेड्डी बड़ी हिट थी। इसी का रीमेक बॉलीवुड में भी बना जो शाहिद कपूर स्टारर कबीर सिंह थी।

9 मई 1989 को हैदराबाद में टेलिविजन डायरेक्टर गोवर्धन राव के घर जन्में विजय की पढ़ाई एक बोर्डिंग स्कूल में हुई थी। विजय ने कॉमर्स में बैचलर्स डिग्री हासिल की है। उनके छोटे भाई भी एक्टर हैं। विजय अपनी बोर्डिंग स्कूल की पढ़ाई को उनकी सक्सेस का क्रेडिट देते हैं। उनके अनुसार जो उन्होंने बोर्डिंग स्कूल में सीखा है शायद वो घर में नहीं सीख पाते।

विजय के फिल्मी कैरियर की शुरुआत 2011 में आई फिल्म नौविला से हुई थी। जिसके बाद उन्हें फिल्म लाइफ इज ब्यूटीफूल में काम मिला। साइड रोल में तो विजय का

कैरियर चल रहा था लेकिन लीड रोल में पहली बार उन्हें पहचान मिली उनकी फिल्म पेल्ली चोपुलु से। 29 जुलाई 2016 को रिलीज हुई ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी। जिसे बेस्ट तेलुगु फिल्म के दो नेशनल अवॉर्ड, दो फिल्मफेयर अवॉर्ड और तीन सीमा अवॉर्ड से नवाजा जा चुका है। जिसके बाद उनकी फिल्म आई द्वारका लेकिन अब तक विजय को वो पहचान नहीं मिली थी जो वो चाहते थे। लेकिन वो भी ज्यादा दूर नहीं थी उनकी फिल्म अर्जुन रेड्डी ने विजय को एक अलग पहचान दिलाई। ये फिल्म 2017 में रिलीज हुई थी। जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर के फिल्मफेयर अवॉर्ड से नवाजा गया था।

आओ जाति-जाति खेलें...

हम सब अपने को इंसान कहते हैं। पशु-पक्षियों, कीड़े-मकोड़ों से भी बहुत महान। इस धरती माता की शान। ज्ञान और गुणों की आकाश जैसी अनंत खान। मियां मिट्ठू अपने ही आप इंसान। जंगल में खड़े होकर अपनी मूंछें रहा है तान। इस बात से कौन रहा है अनजान! परंतु इस मानव के सभी खेल हैं बड़े निराले। समझ नहीं सकता कोई इसकी चालें। जो बन जाएं किस क्षण इसकी कुचालें! कोई नहीं जानता।

यों तो मनुष्य ये कहते हुए नहीं थकता कि मनुष्य पहले पशु है, बाद में मनुष्य। किंतु मुझे यह पहले और बाद में भी पशु ज्यादा और बीच-बीच में मनुष्य दिखलाई पड़ता है। यत्र-तत्र इसकी मानवता का देव स्वरूप दिखाई दे जाता है, अधिकांश में वह पशु ही दिखाई पड़ता है। उसकी पाशविकता उसके सिर चढ़कर ही नहीं बोलती, पूरे शरीर, मन और मस्तिष्क पर ही सवार होकर चीखती, चिल्लाती, गाती और बजाती है। अपने अस्तित्व और अपनी खुशी के लिए किसी को भी फूटी आंखों पसंद नहीं करता। यहां तक कि एक ही छत के नीचे साथ-साथ रहने वाली नारी, जिसे सहधर्मिणी, पत्नी, भार्या, देवी, कांता, लक्ष्मी और न जाने कितने सुनहरे नामों से अभिहित करता है, उससे नित्य निरंतर महाभारत करना इसका प्रियतम खेल है। अपनी अभिजात्यता, देह की शक्ति, दिमाग की असीम पावर को सिद्ध करने के किसी भी अवसर को छोड़ना तो मानो किसी ने उसे क्लीव कह दिया हो। भला कोई क्लीव कहे, और वह सहज स्वीकार कर ले, कभी हो सकता है ऐसा? ये तो एक छत के नीचे के संग्राम और संगम की बात। जहां प्यार है, वहीं रार है, तकरार भी है। सब कुछ नकद है, उधार कुछ भी नहीं है। अड़ौस-पड़ौस में कोई भी हो, उससे जलना, लड़ना, भिड़ना, अपना उल्लू सीधा करना ये इस 'महामानव' के 'अति मानवीय' गुण हैं। कभी-कभी प्यार प्रदर्शन करना कभी नहीं भूलता। इस प्यार प्रदर्शन के लिए ही वर्ष में होली, दिवाली, दशहरा, ईद, लोहड़ी आदि अनेक अवसर पैदा कर लेता है। विवाह को भी उसी उत्सवधर्मिता का अंग बनाकर नाच-कूद कर लेता है।

आदमी का सबसे बड़ा और लोकप्रिय खेल है 'जाति-जाति।' इसके लिए बराबर वह विभिन्न सुअवसर पैदा कर ही लेता है। जब जान पर बन जाती है तो 'जाति' को कोने में उठाकर रख देता है। जब प्राणों पर बन जाती है तो हॉस्पिटल में नहीं पूछता कि जो खून उसे चढ़ाया जाने वाला है, वह किस जाति के व्यक्ति का है? डॉक्टर, नर्स की जाति क्या है, यह भी नहीं जानना चाहता। ट्रेन, बस या बाजार में खाया जाने वाला भोजन किसने बनाया? वह किस जाति का है! गोलगप्पे के खट्टे पानी में बार-बार हाथ डुबाकर गोलगप्पे खिलाने वाले की जाति क्या है? होटल के मालिक, बियरर, कर्मचारी, रसोइया किस जाति से संबंध रखते हैं, कुछ भी जानने-पूछने की जरूरत नहीं समझी जाती। यहां वह देवता बन जाता है। साक्षात देवता। चौके से चौकी तक, बहुत ज्यादा चौक तक जाति का जबरदस्त खेल चलता है।

लोकतंत्र का महान उत्सव कहे जाने वाले मतदान पर्व का जातीय खेल किसने नहीं खेला! नेता, अधिकारी, मतदाता, प्रत्याशी कोई किसी से पीछे नहीं है। चाहे परोक्ष हो या प्रत्यक्ष; जाति-खेल तो जोरशोर से खेला ही जाता है। बल्कि प्रत्याशी को टिकट ही इस आधार पर लेने होते हैं, कि उसकी जाति की बहुतायत है अथवा नहीं। यही जाति के खिलाड़ी जब संसद और विधानसभा में जाते हैं तो वहां भी इस खेल में खोए रहते हैं। उन्होंने पारंगतता ही जातीय-खेल में प्राप्त की है, तो उससे विमुख कैसे रह सकते हैं। जनता को नौकरी देने में भी यह जाति का नगाड़ा खूब बजाया जाता है। नेता तो नेता, बड़े-बड़े विद्वान प्रोफेसर, प्राचार्य, वकील, इंजीनियर, अधिकारी, संत-महंत जातीय-खेलों के पक्के खिलाड़ी होते हैं। जाति के बिना उनका अस्तित्व ही नहीं, तभी तो अपने नामों के आगे-पीछे विभिन्न जाति सूचक सुनहरे शब्द जोड़ना नहीं भूलते, ताकि उनकी जाति का बंदा बिना पूछे-बताए हुए ही समझ जाए कि अगला अपनी ही जाति का है। कवियों के झुंड भी इसी आधार पर निर्मित किए जाने लगे हैं। समाजसेवियों, धर्म प्रेमियों, मजहबी जनों सबमें जाति-खेल अति लोकप्रिय हैं। कोई किसी से कम नहीं है।

सब कौवे एक जैसे हो सकते हैं ,परंतु मनुष्य नहीं। सब गधे, घोड़े, भैंसे, गाय, सांड, भेड़, बकरी, कुत्ते, बिल्लियां, चूहे, मुर्गे, मुर्गियां भले ही एक जैसे हो जाएं, परंतु मानव यदि एक जैसा हो जाए तो मानव किस बात का! मानव बिना जाति के जिंदा नहीं रह सकता। कुछ जातियों को तो जाति के खेलों को बढ़ा-चढ़ा कर जनता में प्रचार-प्रसार करना मुख्य कार्य है। वे इसके कार्य के ठेकेदार हैं। उनकी रोटी ही जातिगत खेलों से चलती है। इसलिए त्यौहारों का आयोजन भी मनुष्य और मनुष्यता के नाम पर न होकर जातियों में बांट दिया है। रक्षाबंधन-ब्राह्मण, दीवाली- बनिया, दशहरा-क्षत्रिय और होली-शूद्रों के त्यौहारों के नाम से ख्याति प्राप्त किए हुए हैं। पशु -पक्षियों, पेड़-पौधों को भी जातियों के खेल के शिकंजे में फंसाने का खेल भी कम जोरशोर से नहीं चलाया जा रहा है। एक दिन ऐसा भी आने वाला है; जब धरती, आकाश, अग्नि, वायु और सागर को भी जातियों के खेल में सम्मिलित कर लिया जाएगा। यह सब इस मानव के ही कारण होगा। खून भले सबका लाल हो, पर चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव का खेल बहुत पुराना है, जो आज तक और अधिक ताकत के साथ फल-फूल रहा है। मनुष्य अंततः मनुष्य है; उसका जातिवादी खेल ब्रह्मांडव्यापी होने वाला है, जब विमान, ट्रेन, बसें और जलयानों की भी जातियां होंगीं।

जब जाति से जाता रहता है मानव अथवा दुनिया से जाता रहता है; तब वह मात्र देह (बॉडी) मात्र रह जाता है। मनुष्य भी नहीं, वर्ण भी नहीं, अवर्ण भी नहीं, सवर्ण भी नहीं; मात्र एक 'पार्थिव शरीर।' यही है उसकी वास्तविक तस्वीर। जाति जाती रहने वाली है, पर उसका गुमान कितना? न जाने तू किस यौनि में क्या बनने वाला है? कुछ ज्ञात है? कीड़ा, मकोड़ा, गधा, घोड़ा, शुद्र, ब्राह्मण, वैश्य या क्षत्रिय! फिर किस बात का तनना? किस बात का बनना? न किसी की सुनना! न किसी की मानना!

● **अनाम**

HEIDELBERGCEMENT

149 वर्षों का अतुलनीय अनुभव

mycem cement

माईसेम सीमेन्ट की सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता, मज़बूती और टिकाऊपन के पीछे उसके विश्व प्रख्यात उत्पादनकर्ता जर्मन कंपनी हाइडलबर्ग सीमेन्ट का 149 वर्षों का अतुलनीय अनुभव है जो 50 देशों में लगातार सुनिश्चित करता आया है कि उसके द्वारा उत्पादित सीमेन्ट का हर कण गुणवत्ता के मापदंड पर खरा उतरे ताकि उनका नारा "सर्वोत्तम निर्माण के लिए" उसके ग्राहकों का विश्वास पात्र बना रहे।

क्योंकि जब सीमेन्ट की गुणवत्ता का सवाल हो,
तो सीमेन्ट का हर कण मायने रखता है..

माईसेम सीमेन्ट | सर्वोत्तम निर्माण के लिए

सस्ता सीमेन्ट या बढ़िया सीमेन्ट - फैसला आपका

For all licenses and BIS standards please refer to www.bis.gov.in
HeidelbergCement India Limited CIN: L26942HR1956FLC042301 Phone +91-124-4503700 e-mail - assistance@mycem.in

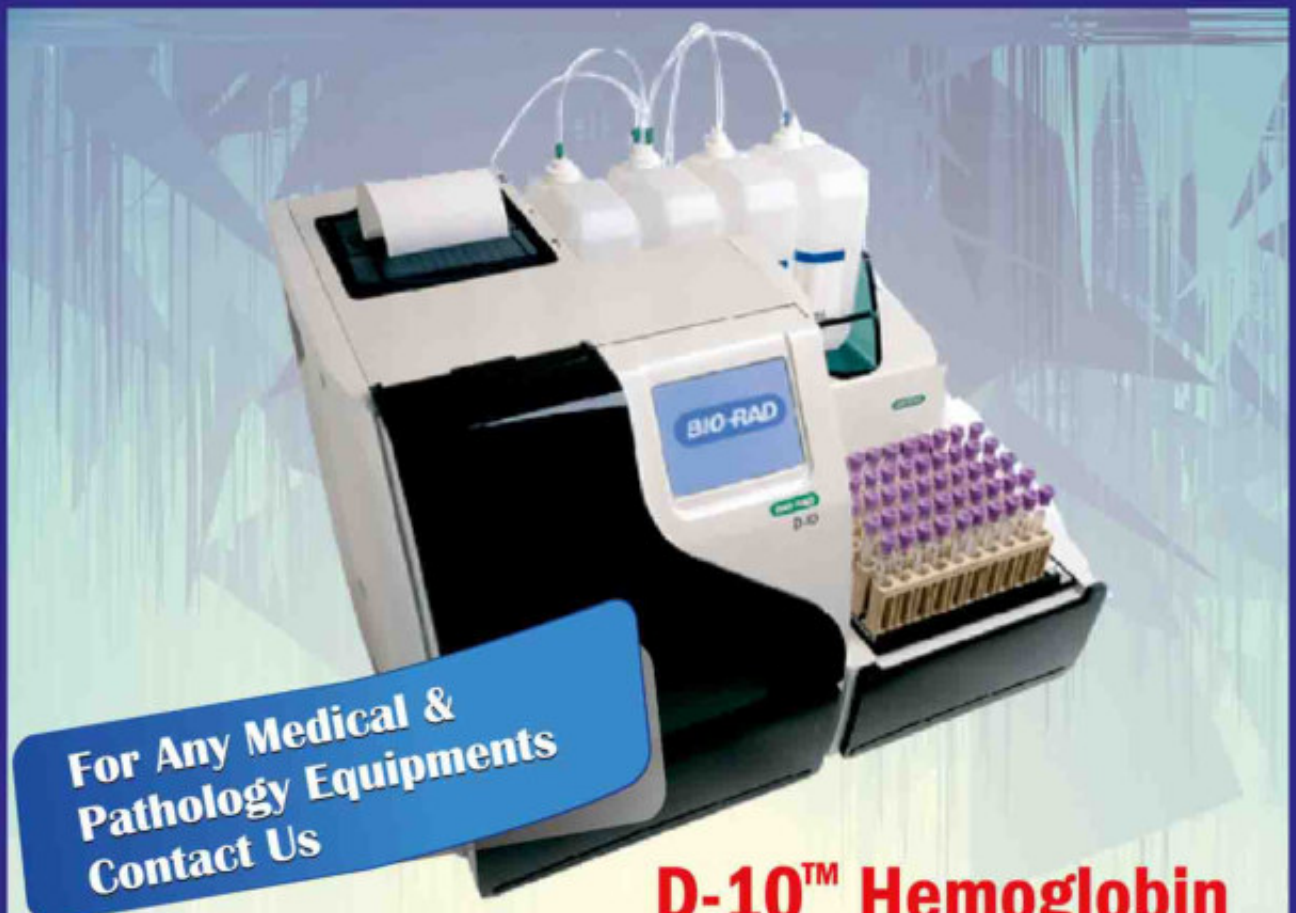

For Any Medical & Pathology Equipments Contact Us

D-10™ Hemoglobin Testing System

For HbA_{1c}, HbA_2 and HbF

Flexible
to solve more testing needs

Comprehensive
B-thalassemia and diabetes testing

Easy
for simple operation

Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly; It's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the D-10™ System with reliability and efficiency in mind.

A simple, fully-automated solution, the D-10™ System Combines diabetes and B-thalassemia testing, enabling rapid HbA_{1c} or $HbA_2/F/A_{1c}$ testing using pripary tube sampling-so you can accomplish more in fewer steps, With the D-10™ System, It's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress-and that can be the difference for the people who count on you most.

SCIENCE HOUSE MEDICAL PVT. LTD.

17/1, Sector-1 Shanti Niketan, Near Chetak Bridge, Bhopal (M.P.) India-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbple@rediffmail.com
Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687